04 - युद्ध की घोषणा के बारे में भारतीय संविधान में क्या प्रावधान

05 - महिलाओं के प्रति सम्मान के बिना कैसे आएगी समता?

A Daily News Magazine

इंदौर

सोमवार, 30 जून, 2025

06 - भयानक तबाही मचा सकते हैं कुछ क्षुद्रग्रह

07 - जिले में 435 हितग्राहियों को 16 करोड़ 19 लाख रुपए का ऋण स्वीकृत

इंदौर एवं भोपाल से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 10 अंक 261, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

subahsaverenews@gmail.com

facebook.com/subahsaverenews

www.subahsavere.news

twitter.com/subahsaverenews

सुप्रभात

मौन चीखता आज भी, सन्नाटे में शोर।
आई फिर हरसूद की, यादें हूक हिलोर।।

सावन भादों नयन थे, टुकुर टुकुर घर द्वार।
कृष्ण निहारें द्वारका, जैसे अन्तिम बार।।

लालच बढ़ा विकास का, किया प्रकृति से युद्ध।
नष्ट हुए वन, खेत सब, जल भी रहा न शुद्ध।

हृदय हृदय ज्वालामुखी, कौन बँधाये धीर।
जन, मन, पर्वत, मृत्तिका, पीर नर्मदा नीर।।

था निमाड़ के मुकुट में, हीरे सा हरसूद।
शोभित ज्यों नवरत्न सा, था बहुग्राम वजूद।।

हुआ नहीं हरसूद ही, केवल एक शिकार।
दो सौ पचपन गाँव ने , झेला वज्र प्रहार।।

जितनी चढ़ी सलाइनें, उतनी टूटी साँस।
धीरे धीरे धँस गयी, यह विकास की फांस।।

समय किसी का कब हुआ, मित्र, शत्रु या दास।
राजतिलक के थाल में, छिप रहता वनवास।।

पेट काट जो घर बना, तिनका तिनका जोड़।
किन्तु कलेजा मुँह लिए, दिया उसे ही तोड़।।

अपनों के हित हेतु ज्यों, रण स्वीकारें वीर।
स्वजन सहित हरसूद ने, अपना तजा शरीर।।

लुप्त हुए सब चैतुए, बिखर गए घर द्वार।
नित जन गण मन तौलता, कागज का अम्बार।।

इसका कौन हिसाब दे, मूल घटा ना सूद।
आखिर किस अपराध में, डूब गया हरसूद।।

डबिंग फ़िल्म सा बन रहा, आज नया हरसूद।
जो सौंधा हरसूद था, उसका कहाँ वजूद।।

याद रखेंगी पीढियां, चुका न पाएं सूद।
कह पाएं केवल यही, धन्य धन्य हरसूद।।

कल भी था, अब भी यहीं, यादों में हरसूद।
अब भी अमर दधीचि सा, जिन्दा है हरसूद।।

– अशोक चन्द्र दुबे 'अशोक'

पहली बात

'एस्ट्रोनॉट' का खूबसूरत 'अर्थ-हाउस' वस्तुतः 'हॉट-स्पॉट' है...

उमेश त्रिवेदी
प्रधान संपादक

जमीन से 4 सौ किलोमीटर से ऊपर आसमान की निशब्द नीरव बुलंदियों पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ संवाद में उभरे भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला के रूह अफजा अल्फाज जहन में उस 'सारे जहां से अच्छा हिन्दुस्तान हमारा' नगमें की तरन्नुम गुनगुनाने लगते हैं, जिसे पहले भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा ने 41 साल पहले चांद की सतह से उकेरा था। शुभांशु शुक्ला अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष सेंटर में वैज्ञानिक प्रयोग करने वाले पहले भारतीय एस्ट्रोनॉट हैं। राकेश शर्मा जब एस्ट्रोनॉट बने थे, तब यह सेंटर स्थापित नहीं हुआ था। 1961 से अबतक दुनिया के 600 एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष कर यात्रा कर चुके हैं। राकेश शर्मा 3 अप्रैल 1984 को रूसी सोयुज टी-11 अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में गए थे। उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बातचीत में राकेश शर्मा ने कहा था कि 'सारे जहां से अच्छा हिन्दुस्तान हमारा'।

41 साल बाद आज शुभांशु शुक्ला ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ 18 मिनट 25 सेकंड तक अपने अनुभव साझा किए। संवाद के दरम्यान शुभांशु शुक्ला ने प्रधानमंत्री से कहा कि- 'जब मैंने पहली बार अंतरिक्ष से भारत को देखा तो वह नक्शे से कहीं ज्यादा विशाल और भव्य नजर आया।' उन्होने कहा कि 'यहां अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखने पर एकता का असली एहसास होता है। कोई सीमाएं नही दिखती हैं। कोई लकीरें नहीं होती हैं। ऐसा लगता है कि जैसे पूरी पृथ्वी हमारा घर है और हम सभी इसके नागरिक हैं।'

प्रधानमंत्री मोदी से शुभांशु शुक्ला की बातचीत लंबी थी, लेकिन हमारे देश, हमारी जमीन, हमारी पृथ्वी के बारे में शुभांशु ने जो कहा, वह गौरतलब है। भारत के लिए शुभांशु का कथन गुदगुदाता है, लेकिन पृथ्वी के बारे में उनका नजरिया थरथराता है। एक एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष से पृथ्वी पर मनुष्यता की एकात्मता का यह परिदृश्य देख सकता है, लेकिन भू-राजनीति के बीहड़ों में तो खूनी ताकतें ही राज करती हैं। पृथ्वी के भूगोल में सभ्यताओं के इतिहास का खलल उन लकीरों को स्याह बना रहा है, जो लकीरें शुभांशु शुक्ला जैसे एस्ट्रानॉट-वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष से नजर नहीं आती हैं। शुभांशु जैसे एस्ट्रोनॉट भले ही अंतरिक्ष की ऊंचाइयों से समूचे मानव समाज के बीच लकीरों के अस्तित्व को नकारें, लेकिन भू-राजनैतिक अवधारणाएं सीमा-हीनता को कभी भी कबूल नहीं करती हैं। विज्ञान भौगोलिक सीमाओं से परे इंसान और इंसानियत को सहेजने और संवारने के लिए सक्रिय है, लेकिन सियासी फितरत उसे गर्त की ओर ढकेल रही है। एस्ट्रोनॉट के लिए भले यह दुनिया याने 'अर्थ', एक 'हाउस' हो, लेकिन उन वर्ल्ड-लीडर के लिए तो यह दुनिया लूट का खजाना है।

दुनिया में ऐसे कई भू-राजनीतिक हॉट-स्पॉट हैं, जो विचारधारा, संसाधन और क्षेत्रीय हितों के नाम पर ज्वालामुखी की तरह विनाश के लावा उगल रहे हैं। रूस-यूक्रेन, इजराइल-ईरान-फिलिस्तीन और भारत-पाकिस्तान के बीच ताजा संघर्षों की तथा-कथा के बीच चीन-ताइवान आमने-सामने खड़े हैं। दक्षिण चीन सागर, मध्य-पूर्व और पूर्वी यूरोप बारूद के ढेर पर बैठे हैं। शुभांशु शुक्ला ने प्रधानमंत्री को बताया कि वो चौबीस घंटों में 16 बार पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। यह उनकी खुशनसीबी है कि वो चौबीस घंटों में सोलह बार सूर्योदय और सूर्यास्त देख रहे हैं। याने हर डेढ़ घंटे में उनके सामने सूर्य उगता और अस्त होता है।

वो नियति के अद्भुत चमत्कार के रूबरू हैं, लेकिन ये चमत्कार दुनिया की भू-राजनैतिक परिस्थितियों के सामने असहाय हैं। आकाश-गंगा की ये वैज्ञानिक-सत्य कथाएँ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर व्लादिमीरोविच पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू या ईरान के सर्वोच्च नेता इस्लामी गणराज्य के प्रमुख अयातुल्लाह अली खामेनेई के विस्फोटक भू-राजनैतिक युद्धों की संहारक-सत्य कथाओं की विनाश-लीलाओं के सामने कराहती और सिसकती महसूस हो रही हैं। पृथ्वी के भीतर छिपे नैसर्गिक प्राकृतिक संसाधनों को हथियाने को होड़ में इन राष्ट्राध्यक्षों ने दुनिया को बारूद के जखीरों में बांट दिया है। प्राकृतिक संसाधनों की हवस में ये नेता मनुष्यता को युद्ध में झोंकने से बाज नहीं आ रहे हैं। इन लड़ाइयों में होने वाला नुकसान और तबाही हैरतअंगेज है।

आकलन करें तो ईरान और इजराइल के बीच बारह दिनो के ताजा युद्ध में दोनो देशों को जबरदस्त नुकसान हुआ है। इस युद्ध में इस्तेमाल राकेटों और मिसाइलों के हमलों ने जहां दोनो देशों के नागरिक ठिकानो पर भारी तबाही मचाई है, वहीं आर्थिक रूप से दोनो राष्ट्र घुटने के बल खड़े नजर आ रहे हैं। 'एमनेस्टी इंटरनेशनल' और विभिन्न मीडिया रिपोर्ट के विश्लेषण में कहा गया है कि इस लड़ाई में ईरान को करीब 200 अरब डॉलर का नुकसान झेलना पड़ा है, जबकि इजराइल को 12 अरब डॉलर की तबाही झेलनी पड़ी है।

ईरान की तबाही के आंकड़ों का मूल्यांकन भी इससे कम नहीं है। इस लड़ाई में लगभग 800 लोगों की मौत हुई है। इनमें 263 रिवोल्युशनरी गार्ड के कई शीर्ष कमांडर और परमाणु वैज्ञानिक भी शरीक हैं। अमरीकी सैन्य हमलों में नतांज और फोर्डो परमाणु केन्द्रों पर महती नुकसान के अलावा तेल-उत्पादन के क्षेत्र में ढाई अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। तेल के इन्फ्रास्ट्रक्चर की तबाही की लागत चार अरब डॉलर आंकी गई है। तेल उत्पादन के निर्यात और उत्पादन में हुए नुकसान ने जीडीपी पर 9.6 अरब डॉलर का नकारात्मक प्रभाव डाला है। जबकि ईरानी-मिसाइलों ने इजराइल में 4.2 अरब डॉलर का इन्फ्रास्ट्रक्चर तबाह किया है। 2 अरब डॉलर का औद्योगिक उत्पादन का नुकसान इसके अलावा है।

अब हम फरवरी 2022 से जारी रूस और युक्रेन के बीच जारी युद्ध की ओर मुखातिब हों तो विश्व बैंक के अनुसार युक्रेन में प्रत्यक्ष तबाही का आंकड़ा 152 बिलियन डॉलर है। यहां भौतिक तबाही के मंजर हैरतअंगेज और दिल हिला देते हैं। कह सकते हैं कि यूक्रेन विनाश की कगार पर खड़ा है। रूस भी युद्ध के दुष्प्रभावों से अछूता नहीं है। रूस ने नवम्बर 2022 में आधिकारिक तौर पर कबूल किया था कि युद्ध ने उसकी इकॉनमी को मंदी में ढकेल दिया है। राष्ट्रीय जीडीपी संकट के दौर से गुजर रही है। अनुमानों मे कहा गया है कि युक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस को प्रति दिन 500 मिलियन से 1 बिलियन डॉलर के बीच नुकसान हो रहा है। 'द वॉल स्ट्रीट जर्नल' की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक तीन साल से जारी रूस-यूक्रेन युद्ध में अभी तक दोनो पक्षों के दस लाख से ज्यादा लोग मारे गए हैं। मृतकों मे अधिकांशतः दोनो पक्ष के सैनिक हैं। जबकि यूक्रेन का दावा है कि अभी तक लड़ाई में रूस अपने दस लाख सैनिकों को खो चुका है। यह सिलसिला रूकने वाला नहीं है, क्योंकि संसाधनों की हवस ने अमेरिका, रूस अथवा चीन जैसे ताकतवर देशों को आमने-सामने खड़ा कर दिया है।

बाढ़-बारिश का कहर संकट में गांव और शहर

झारखंड में बाल-बाल बचे बाढ़ में फंसे 162 बच्चे

यमुनोत्री मार्ग पर बादल फटा, 2 मजदूरों की गई जान

नई दिल्ली (एजेंसी)। झारखंड के जमशेदपुर में लव कुश आवासीय स्कूल में फंसे 162 बच्चों को रेस्क्यू किया गया। बारिश के बाद स्कूल में बाढ़ जैसे हालात बन गए थे। सोशल मीडिया से जानकारी मिलने के बाद जमशेदपुर पुलिस ने बच्चों को बचाया है। देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसूनी बारिश जारी है। उत्तराखंड में शनिवार से भारी बारिश जारी है। यहां चारधाम यात्रा अगले 24 घंटे के लिए रोक दी गई है। यात्रियों को हरिद्वार, ऋषिकेश, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, सोनप्रयाग और विकासनगर में ही रोकने के आदेश दिए गए हैं। उत्तरकाशी में यमुनोत्री मार्ग पर बादल फटने से निर्माणाधीन होटल में काम करने वाले 2 मजदूरों की मौत हो गई और 7 मजदूर लापता हैं। वहीं, बागेश्वर में सरयू नदी ने खतरे का निशान पार कर लिया है। अलकनंदा और सरस्वती भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मानसून ने पूरे देश को कवर कर लिया है। मौसम विभाग ने बताया है कि आमतौर पर यह 8 जुलाई तक होता है, लेकिन इस बार मानसून 9 दिन पहले ही पूरे देश में फैल गया। देशभर में रविवार को बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

पाकिस्तान ने भारत पर लगाया सुसाइड बम अटैक का आरोप

- इसमें 13 सैनिक मारे गए थे

इस्लामाबाद (एजेंसी)। पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के उत्तरी वजीरिस्तान जिले में सैन्य काफिले पर सुसाइड बम अटैक का आरोप भारत पर लगाया है। इसमें 13 सैनिकों की मौत हुई थी। भारत ने पाकिस्तान के आरोपों का खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर कहा, हमने पाकिस्तानी सेना का एक ऑफिशियल बयान देखा है, जिसमें 28 जून को वजीरिस्तान पर हुए हमले के लिए भारत को दोषी ठहराया गया है। हम इस बयान को पूरी अवमानना के साथ खारिज करते हैं, जो इसी के लायक है।

जगन्नाथ रथयात्रा के बाद भगदड़, 3 लोगों की मौत

50 लोग हुए घायल, मुख्यमंत्री माझी ने मांगी माफी

भुवनेश्वर (एजेंसी)। ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ रथयात्रा के बाद रविवार तड़के करीब 4 बजे भगदड़ मच गई। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 घायल हो गए। घायलों

में 6 की हालत गंभीर है। हादसा जगन्नाथ मंदिर से करीब 3 किमी दूर गुंडिचा मंदिर के सामने हुआ। यहां भगवान जगन्नाथ के नंदीघोष रथ के दर्शन करने के लिए भारी भीड़ जुटी थी, इसी दौरान भगदड़ मची। सीएम मोहन चरण माझी ने घटना पर माफी मांगी है। उन्होंने एक्स पर लिखा, 'मैं और मेरी सरकार भगवान जगन्नाथ के सभी भक्तों से व्यक्तिगत रूप से क्षमा मांगते हैं। यह लापरवाही माफ करने लायक नहीं है।' इसके बाद राज्य सरकार ने पुरी के कलेक्टर और एसपी का तबादला कर दिया। चंचल राणा को नया कलेक्टर और पिनाक मिश्रा को नया एसपी बनाया गया है। साथ ही डीएसपी और कमांडेंट को निलंबित कर दिया गया है। पुरी की रथयात्रा में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथों को उनकी मौसी के घर गुंडिचा मंदिर के सामने 9 दिन के लिए खड़ा कर दिया जाता है। यहां बलभद्र और सुभद्रा के रथ पहले पहुंच चुके थे। जगन्नाथ रथ बाद में पहुंचा, जिससे लोगों में उसके दर्शन करने की होड़ लग गई। इसी दौरान भगदड़ मची, जिसमें कई लोग कुचल गए।

आने वाले समय में और सशक्त होगा भारत

पीएम मोदी ने कहा- जनभागीदारी से देश और आगे बढ़ रहा है

नई दिल्ली (एजेंसी)। पीएम नरेंद्र मोदी ने रेडियो शो मन की बात के 123वें एपिसोड के तहत देश को संबोधित किया। एपिसोड की शुरुआत में उन्होंने योग दिवस के बारे में बात की। उन्होंने

- मन की बात में बोले-इमरजेंसी में लोगों को प्रताड़ित किया गया

कहा- 21 जून को देश-दुनिया के करोड़ों लोगों ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस में हिस्सा लिया। योग की भव्यता बढ़ती जा रही, लोग दैनिक जीवन में इसे अपना रहे। पीएम ने कहा- इस बार हमने योग दिवस की आकर्षक तस्वीरें देखीं। विशाखापत्तनम में 3 लाख

लोगों ने एक साथ योग किया। हमारे नौसेना ने जहाजों पर और जम्मू में लोगों ने दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज पर योग किया। वडनगर में 2100 लोगों ने एक साथ भुजंगासन करके रिकॉर्ड बना दिया। पीएम ने आगे कहा- इमरजेंसी के दौर में लोगों को प्रताड़ित किया गया। अनेक लोगों को कठोर यातनाएं दी गई। मीसा के तहत किसी को भी ऐसे ही गिरफ्तार कर लिया जाता था। उन पर ऐसे ही अमानवीय अत्याचार किए गए। आखिर में जनता की जीत हुई और आपातकाल हटा लिया गया। जनता की जीत हुई और आपातकाल लगाने वालों की हार हुई। इंटरनेशनल लेबल ऑर्गनाइजेशन की रिपोर्ट आई है। इसमें सामने आया है कि देश के 95 करोड़ लोग किसी न किसी सरकारी योजना का लाभ उठा रहे हैं। इन सफलताओं ने एक विश्वास दिलाया है कि आने वाले समय में भारत और सशक्त होगा। साथियों, जनभागीदारी से देश और आगे बढ़ रहा है। धार्मिक यात्राएं सेवा के अवसर का महाअनुष्ठान होती है। जितने लोग यात्रा में जाते हैं उससे ज्यादा लोग उनकी सेवा में जुट जाते हैं। लंबे समय के बाद कैलाश मानसरोवर की यात्रा शुरू हुई है।

शिवराज सिंह क्षेत्र के आदिवासियों को साथ लेकर सीएम हाउस पहुंचे

अभयारण्य में ग्रामीणों के घर तोड़े गए थे, शिवराज की शिकायत पर सीहोर डीएफओ हटाए गए

भोपाल (नप्र)। रविवार को शिवराज, क्षेत्र के आदिवासियों को साथ लेकर सीएम हाउस पहुंचे जहां उन्होंने सीएम डॉ. मोहन यादव से मुलाकात की। सीएम के निर्देश पर मंत्री शाह खिवनी पहुंचे।

देवास जिले के खातेगांव विधानसभा क्षेत्र के खिवनी में 23 जून को वन विभाग ने आदिवासियों के 50 से ज्यादा घरों पर बुलडोजर चला दिया था। घटना के बाद सीहोर में पीड़ित आदिवासी परिवारों ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की थी।

रविवार को शिवराज, क्षेत्र के पीड़ितों को साथ लेकर सीएम हाउस पहुंचे। सीएम डॉ. मोहन यादव से मुलाकात के दौरान खातेगांव और इछावर क्षेत्र के आदिवासी समाज के लोगों के साथ बुधनी विधायक रमाकांत भार्गव भी मौजूद थे।

वहीं, सीएम के निर्देश पर मंत्री विजय शाह कीचड़ भरे रास्ते पर तीन-चार किलोमीटर पैदल चलते हुए खिवनी गांव पहुंचे पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। इसके बाद वे ट्रैक्टर की ट्रॉली में बैठकर अधिकारियों के साथ गांव से निकले। बता दें, शाह कर्नल सोफिया पर आपत्तिजनक बयान देकर विवाद में फंसे हैं।

सीएम ने सीहोर डीएफओ मगन सिंह डाबर को हटाया- शिवराज से हुई मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सीहोर के डीएफओ मगन सिंह डाबर को हटा दिया है। डाबर को भोपाल भेजा गया है। अर्चना पटेल को सीहोर का नया डीएफओ बनाया है। खिवनी अभयारण्य सीहोर वन मंडल क्षेत्र में आता है। ऐसे में पहली कार्रवाई डीएफओ पर ही की गई है। 23 जून को आदिवासियों के 50 से अधिक कच्चे मकानों को अतिक्रमण बताकर हटाया गया था। सीएम ने दिया था मदद का आश्वासन।

बारिश के सीजन में ऐसी किसी भी कार्रवाई से बचें- शिवराज सिंह चौहान के साथ सीएम हाउस में आदिवासियों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद सीएम डॉ मोहन यादव ने एक्स पर लिखा- हमारी सरकार गरीबों की सरकार है, गरीबों के साथ है। आज भोपाल निवास पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की मौजूदगी में खिवनी अभयारण्य के लिए वन विभाग की कार्रवाई से प्रभावित जनजातीय समुदाय के नागरिकों से भेंट की।

भोपाल का तापमान

अधिकतम 35 °c

न्यूनतम 30°c

सुबह सवेरे

इंदौर ■ सोमवार, 30 जून 2025

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

दिल्ली में मोदी की हर गारंटी झूठी और नकली निकली

● अरविंद केजरीवाल बोले, पीएम पर लगा दिया बड़ा आरोप

नई दिल्ली (एजेंसी)। आम आदमी पार्टी ने रविवार को दिल्ली में झुग्गियों के खिलाफ चल रही कार्रवाई के विरोध में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा- मोदी की गारंटी झूठी, फर्जी और नकली है। आगे कभी जिंदगी में मोदी की गारंटी पर भरोसा मत करना। केजरीवाल ने कहा- चुनाव के समय मोदी जी ने आपको गारंटी दी थी- 'जहां झुग्गी-वहां मकान।' उनका मतलब

था- 'जहां झुग्गी-वहां मैदान।' वो ये कहना चाहते थे मुझे वोट दे दो, मैं सारी झुग्गियां तोड़ दूंगा और मैदान बना दूंगा। भाजपा का प्लान दिल्ली की सभी झुग्गियां तोड़ने का है। इनकी गंदी नजर आपके घरों पर टिकी हुई है। दिल्ली में 40 लाख से ज्यादा झुग्गीवाले हैं, यह सभी इकट्ठे होकर सड़कों पर आकर आंदोलन करेंगे। मैं भाजपा को चेतावनी देना चाहता हूं कि सुधर जाओ, झुग्गियां तोड़ना बंद करो। अगर झुग्गियां तोड़ना बंद नहीं किया तो तुम्हारा सिंहासन डोलने में वक्त नहीं लगेगा। चुनाव से पहले मैंने दिल्ली के गरीबों और झुग्गीवालों के लिए वीडियो जारी करके कहा था कि अगर भाजपा की सरकार आ गई तो यह एक साल में ही झुग्गियां तोड़ देंगे।

ठाकरे बंधुओं को मिला शरद पवार का साथ

● महाराष्ट्र में भाषा विरोध-प्रदर्शन में होंगे शामिल

मुंबई (एजेंसी)। शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी (एसपी) ने ठाकरे बंधुओं की ओर से 5 जुलाई को बुलाए गए विरोध प्रदर्शन का समर्थन करने की घोषणा की है। एनसीपी (एसपी) अध्यक्ष जयंत पाटिल ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने पार्टी के नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से इस मार्च में बड़ी संख्या में भाग लेने की भी अपील की। पाटिल की ओर से शुक्रवार शाम को जारी बयान में कहा गया, एनईपी 2020 की त्रि-भाषी नीति के तहत हिंदी के थोपे जाने के विरोध में

मुंबई में मराठी भाषी नागरिकों की विशाल रैली होगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार गुट) ने इस मार्च को अपना पूरा समर्थन दिया है। एससीपी (एसपी) के अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र के लोग हिंदी विरोधी नहीं हैं, लेकिन पहली कक्षा से चौथी तक के विद्यार्थियों पर यह भाषा थोपना उचित नहीं है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान पवार ने कहा कि देश की 55 प्रतिशत आबादी हिंदी बोलती है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पवार की यह टिप्पणी महाराष्ट्र में भाषा विवाद के बीच आई है, जो पिछले सप्ताह राज्य सरकार की ओर से संशोधित आदेश जारी करने के बाद शुरू हुआ था। इसमें कहा गया कि हिंदी को आम तौर पर कक्षा एक से पांच तक मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में छात्रों को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाया जाएगा।

जल गंगा संवर्धन अभियान

पीएम मोदी जल गंगा संवर्धन अभियान के समापन समारोह को वर्चुअली करेंगे संबोधित

मुख्यमंत्री डॉ. यादव 1518 करोड़ के कार्यों का करेंगे लोकार्पण और भूमि-पूजन, खंडवा में 30 जून को अभियान का होगा भव्य समापन, वाटर-शेड सम्मेलन भी होगा

भोपाल (नप्र)। पानी की हर बूंद को सहेजने के उद्देश्य से चलाए जा रहे जल गंगा संवर्धन अभियान का समापन और वॉटरशेड सम्मेलन सोमवार 30 जून को खंडवा में होगा। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी वर्चुअल शामिल होंगे और कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कार्यक्रम में 1518 करोड़ रुपये से अधिक के जल संरक्षण कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पहल पर मध्यप्रदेश में 3 माह के लिए 'जल गंगा संवर्धन अभियान' चलाया गया। इस दौरान जल स्त्रोतों के संरक्षण और संवर्धन पर लगातार कार्य किया गया। सोमवार को अभियान के समापन कार्यक्रम में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जल गंगा संवर्धन अभियान में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत 578.08 करोड़ रुपये की लागत से कराए गए 57 हजार 207 जल संरक्षण कार्य, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वॉटरशेड विकास के अंतर्गत 63.46 करोड़ रुपये की लागत से 888 जल

संरक्षण के कार्य, वॉटरशेड परियोजनाओं के कार्यों के प्रबंधन और अनुश्रवण के लिए वॉटरशेड वर्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का लोकार्पण किया जाएगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव जल संसाधन विभाग की 4 सिंचाई परियोजनाओं क्रमशः भाम राजगढ़ मध्यम सिंचाई परियोजना, बिहार सारोला बैराज, लाजैरा बैराज, हापला दीपला बैराज लघु सिंचाई परियोजना का लोकार्पण करेंगे। इन परियोजनाओं की लागत करीब 312.77 करोड़ रुपये है, जिससे 8557 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी। इससे 21 ग्रामों के 7260 किसान लाभांवित होंगे। नर्मदा घाटी विकास विभाग की जावर माईक्रो उद्वहन सिंचाई योजना प्रशासकीय स्वीकृति रुपए 563.72 करोड़ का लोकार्पण भी किया जाएगा। योजना से खण्डवा जिले के 52 ग्रामों के 21,666 किसानों की करीब 26 हजार हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित होगी। कार्यक्रम में नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा जल गंगा संवर्धन अभियान में अमृत 2.0 योजना अंतर्गत 50 करोड़ की लागत से जीर्णोद्धार की गई 74 जल संग्रहण संरचनाओं का लोकार्पण किया जाएगा।

अहमदाबाद विमान हादसे में अब साजिश समेत हर एंगल से होगी जांच

नई दिल्ली (एजेंसी)। अहमदाबाद में 12 जून को हुए एअर इंडिया विमान हादसे की जांच सभी पहलुओं से की जा रही है, जिसमें साजिश (सबोटाज) की संभावना को भी खंगाला जा रहा है। यह जानकारी केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने दी है। उन्होंने कहा कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो इस मामले की पूरी जांच कर

● केंद्रीय मंत्री बोले-ब्लैक बॉक्स भारत के पास, इन्वेस्टीगेशन के लिए विदेश नहीं भेजेंगे

रहा है। ब्लैक बॉक्स भारत में (एएआईबी के पास) है, उसे बाहर नहीं भेजा जाएगा। केंद्रीय मंत्री मोहोल पुणे में एक चैनल के कार्यक्रम एमर्जिंग बिजनेस कॉन्क्लेव में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण हादसा था। एएआईबी इसकी हर एंगल से जांच कर रहा है। सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं और कई एजेंसियां मिलकर जांच में जुटी हैं। अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट एआई 171 टेकऑफ के कुछ ही देर बाद एक मेडिकल हॉस्टल की इमारत से टकरा गई थी। इसमें 270 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें 241 यात्री और क्रू मेंबर शामिल थे। सिर्फ एक यात्र जिंदा बचा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हादसे की वजह अभी स्पष्ट नहीं है कि यह इंजन फेलियर, फ्यूल सप्लाई की समस्या या कोई तकनीकी गड़बड़ी की वजह से हुआ। ब्लैक बॉक्स में मौजूद सीवीआर और एफडीआर की जांच की जा रही है। 3 महीने में रिपोर्ट आने की संभावना है। उन्होंने बताया कि डीजीसीए (नागर विमानन महा निदेशालय) के आदेश पर एअर इंडिया के सभी 33 ड्रीमलाइनर विमानों की जांच कर ली गई है और सब कुछ सुरक्षित पाया गया है। ये हादसा एक अपवाद था, अब लोग बिना डर के यात्रा कर सकते हैं। एअर इंडिया के ड्रीमलाइनर प्लेन हादसे की जांच में संयुक्त राष्ट्र शामिल होगा। संयुक्त राष्ट्र की विमानन संस्था आईसीएओ (इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गनाइजेशन) के एक विशेषज्ञ को ऑब्जर्वर के तौर पर शामिल होने की इजाजत भारत सरकार ने दे दी है। आईसीएओ ने जांच में शामिल होने की इजाजत मांगी थी। भारत ने पारदर्शिता के साथ जांच करने के इरादे से संयुक्त राष्ट्र को इसमें शामिल करने का फैसला लिया है। हादसे की जांच 13 जून से ही एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टीगेशन ब्यूरो की टीम कर रही है। इसमें विमानन चिकित्सा विशेषज्ञ, एयर ट्रैफिक कंट्रोल अफसर और अमेरिका की नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड के प्रतिनिधि भी शामिल हैं।

'मन की बात' कार्यक्रम में बालाघाट की बहन का शामिल होना हमारे लिए गर्व की बात

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया 1 और 2 जुलाई को संपन्न होगी : विष्णुदत्त शर्मा

भोपाल। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा ने रविवार को मध्य विधानसभा के अरेरा मंडल के बूथ क्रमांक 159 स्थित कम्युनिटी हॉल में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की 'मन की बात' कार्यक्रम को सुना। उन्होंने 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत कम्युनिटी हॉल परिसर में पौधारोपण किया। मीडिया से चर्चा करते हुए श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यक्रम में बालाघाट जिले के कटंगी की बहन सुमा उइके के आर्थिक आत्मनिर्भरता के प्रयासों की विस्तार से चर्चा की है, जो प्रदेश की सभी बहनों के लिए प्रेरणादायक है, साथ ही हम सभी के लिए गर्व की बात है।

सार्थक हो रहे प्रधानमंत्री जी के प्रयास - भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि हमने 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया है, जिसकी चर्चा प्रधानमंत्री जी ने की है। प्रधानमंत्री के प्रयासों के चलते अंतरराष्ट्रीय योग दिवस आज सारी दुनिया में मनाया जाता है और इतना लोकप्रिय हो चुका है, जिसकी हम लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी। योग आज देश और दुनिया में हर वर्ग के लोगों के लिए निरोग रहने का

माध्यम बन चुका है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने अपने कार्यक्रम में बताया कि किस तरह भारत का जल-जीवन मिशन दूषित पानी से पैदा होने वाली बीमारियों पर रोक लगाने में कामयाब हो रहा है। अब तो विश्व स्वास्थ्य संगठन भी इस तथ्य को स्वीकार कर रहा है। श्री शर्मा ने कहा कि बीमारी मुक्त भारत प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है और उनके द्वारा शुरू की गई योजनाएं इसी दिशा में आगे बढ़ रही हैं।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि 25 जून को हमने संविधान हत्या दिवस मनाया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लगाकर संविधान को कुचल दिया था। प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यक्रम में उस समय विपक्ष के नेता स्वर्गीय मोरार जी देसाई, बाबू जगजीवन राम, श्रद्धेय अटल जी की प्रतिक्रियाओं को देशवासियों के सामने प्रस्तुत किया। आपातकाल के बारे में इन नेताओं का एक्चुअल वर्जन उन्हीं की आवाज मे सुनना सभी के लिए एक रोमांचक अनुभव रहा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि हम सभी के लिए यह सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यक्रम में बालाघाट जिले की कटंगी की बहन सुमा उइके की चर्चा कर बताया कि किस तरह यह बहन स्व-सहायता समूह के माध्यम से मशरूम उत्पादन और पशुपालन के काम करके आर्थिक रूप से सशक्त बन रही है।

छात्रा से जोर जबर्दस्ती करते दिख रहे गैंगरेप के आरोपी

कोलकाता मामले में सीसीटीवी फुटेज से हो गई पुष्टि

कोलकाता (एजेंसी)। कोलकाता की लॉ छात्रा से गैंगरेप मामले में सीसीटीवी फुटेज से गैंगरेप की पुष्टि हुई है। कॉलेज के सीसीटीवी में 25 जून की दोपहर 3.30 बजे से रात 10.50 बजे तक करीब 7 घंटे की फुटेज हैं। एक जांच अधिकारी ने बताया कि सीसीटीवी में पीड़ित छात्रा को गार्ड के कमरे में जबर्दस्ती ले जाने की घटना कैद हुई है। इससे छात्रा की लिखित शिकायत में लगाए गए आरोपों की पुष्टि होती है। वहीं, जिस गार्ड के कमरे में रेप हुआ था, शनिवार को उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मामले में अब तक कुल चार गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इसके अलावा मामले में शुक्रवार को गठित स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम में आज मेंबर्स की संख्या पांच से बढ़ाकर नौ कर दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस प्रदीप कुमार घोषाल इसे लीड कर रहे हैं। घटना 25 जून को कॉलेज के ग्राउंड फ्लोर के गार्ड रूम में हुई थी। मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा (31) है। घटना में जैब अहमद

(19) और प्रमित मुखर्जी (20) भी शामिल हैं। मनोजीत कॉलेज का पूर्व छात्र है, जबकि जैब और प्रमित कॉलेज के छात्र हैं। मेडिकल रिपोर्ट में भी पीड़ित से रेप की पुष्टि हुई पीड़ित छात्रा की मेडिकल रिपोर्ट में शनिवार को रेप की पुष्टि हुई।

राजा हत्या कांड

शिलोम के ससुराल में मिला सोनम का लैपटॉप !

● किचन से मिले बैग से खुलेंगे हत्याकांड के कई राज

भोपाल (एजेंसी)। इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में शिलांग पुलिस को एक और नया सबूत मिला है। शिलांग एसआईटी की टीम प्रॉपर्टी ब्रोकर शिलोम जेम्स को उसके ससुराल रतलाम लेकर पहुंची। वहां पर एसआईटी ने तलाशी ली तो किचन से एक बैग मिला है। एसआईटी की टीम ने बैग में रखे सामान का

पंचनामा बनाया और अपने कब्जे में ले लिया। सूत्रों के अनुसार इस बैग में सोनम के लैपटॉप का होना बताया जा रहा है। दरअसल, शिलांग पुलिस शिलोम जेम्स के साथ कार से उसके ससुराल रतलाम में मंगल मूर्ति कॉलोनी पहुंची। एसआईटी के साथ शिलोम जेम्स की पत्नी और साली भी मौजूद थी।

विधायक की कार गुजरी लेकिन एंबुलेंस नहीं जाने दी

● यूपी में मां का शव लेकर 1 किमी पैदल चला बेटा, फिर ऑटो से घर ले गया

हमीरपुर (एजेंसी)। यूपी के हमीरपुर से मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां यमुना पुल पर मरम्मत के चलते वाहनों की एंट्री बंद है। इसके बाद भी भाजपा विधायक की कार पुल से होकर गुजरी, लेकिन मजदूर की मां का शव लेकर जा रही एम्बुलेंस को रोक दिया गया। बेटों ने पुलिसकर्मियों के हाथ-पैर जोड़े, काफी देर तक मिन्नतें कीं, लेकिन पुलिसकर्मी एम्बुलेंस को भेजने के लिए राजी नहीं हुए। इसके बाद बेटे ने स्ट्रेचर सहित एम्बुलेंस से शव को उतारा और करीब 1 किमी पैदल चलकर पुल पार किया। स्ट्रेचर को एक तरफ बेटा, तो दूसरी तरफ एम्बुलेंस ड्राइवर और चिकित्सा कर्मी पकड़े हुए थे। इसके बाद शव को ऑटो से लेकर घर गया। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया है मामला

कानपुर-सागर हाईवे एनएच-34 का है। कानपुर-सागर (एनएच-34) पर यमुना नदी पर बने पुल की मरम्मत का काम शनिवार सुबह 6 बजे से शुरू हुआ। इसके चलते पुल से वाहनों की आवाजाही दो दिन के लिए रोक दी गई। शनिवार सुबह 6.44 बजे सदर विधायक मनोज प्रजापति की कार को पार कराने के लिए यमुना पुल पर लगी बैरिकेडिंग हटा दी गई। इसके तीन घंटे बाद सुबह 9.30 बजे टेढ़ा गांव निवासी बिंदा अपनी मां शिवदेवी के शव को लेकर लौटे।

फाइटर जेट की रिपेयरिंग में भारत की मदद लेगा ब्रिटेन

● केरल के तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट में खड़ा है एफ-35 जेट

तिरुवनंतपुरम (एजेंसी)। केरल के तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर खड़े ब्रिटिश रॉयल नेवी के स्टील्थ एफ-35 फाइटर जेट ने सभी की नजरें अपनी ओर खींची हैं। यह विमान 14 जून को इमरजेंसी लैंडिंग के जरिए यहां पहुंचा और तभी से लगातार अपने देश से सहायता आने की उम्मीद में खड़ा हुआ है। ब्रिटेन की तरफ से शुक्रवार को बयान जारी करके कहा गया है कि वह इसकी मरम्मत के लिए भारतीय मदद को स्वीकार कर रहे हैं। इसकी मरम्मत के लिए इसे स्थानीय रखरखाव, मरम्मत

और ओवरहॉल सुविधा केंद्र में ले जाया जाएगा। इससे पहले रॉयल एयरफोर्स ने भारतीय हैंगर का उपयोग करने से इनकार कर दिया था।

मजीठिया की गिरफ्तारी पर अपनों ने ही उठाया सवाल

घिर गई मान सरकार, विधायक को 5 साल के लिए किया सस्पेंड

चंडीगढ़ (एजेंसी)। पूर्व आईपीएस अधिकारी और अमृतसर नॉर्थ से आम आदमी पार्टी के विधायक कुंवर विजय प्रताप सिंह को 5 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ विजिलेंस कार्रवाई और उनकी गिरफ्तारी पर सवाल उठाए थे। पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति ने यह कठोर कदम कुंवर विजय प्रताप की पार्टी विरोधी गतिविधियों और पंजाब सरकार की ड्रग्स के खिलाफ मुहिम में बाधा डालने के आरोपों के चलते उठाया है। मजीठिया को 25 जून को पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने अमृतसर में उनके घर से गिरफ्तार किया था। मजीठिया पर 540 करोड़ रुपये से अधिक की ड्रग मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने का आरोप है। कुंवर विजय प्रताप ने मजीठिया के खिलाफ विजिलेंस कार्रवाई और उनकी गिरफ्तारी पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि मजीठिया जेल में थे तब पंजाब सरकार ने कोई पूछताछ नहीं की और

उनकी जमानत में सहायता की लेकिन अब अचानक कार्रवाई शुरू करना सवाल उठाता है। उन्होंने सोशल मीडिया पर मजीठिया की पत्नी के साथ विजिलेंस टीम की बहस का वीडियो साझा करते हुए सरकार की कार्रवाई को अनुचित बताया था। इस मुद्दे को उठाने से आम आदमी पार्टी को अपनी कार्रवाई पर जवाब देना भी मुश्किल हो गया था। उन्होंने गिरफ्तारी के तरीकों को लेकर के भी पार्टी की नियत पर सवाल खड़े किए थे। इसे पार्टी ने अनुशासनहीनता माना और राजनीतिक मामलों की कमेटी ने कड़ा कदम उठाते हुए कुंवर विजय प्रताप को 5 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया। कुंवर विजय प्रताप सिंह ने बिक्रम सिंह मजीठिया की गिरफ्तारी को लेकर सोशल मीडिया पर लिखा, जब मजीठिया 2022 में नशा मामले में जेल में थे।

इंस्टाग्राम पर दोस्ती, शादी का झांसा

इंदौर। इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला आरोपी करण पटेल आखिरकार आजाद नगर पुलिस की गिरफ्त में आ गया। आरोपी पर पुलिस ने रू. 5000 का इनाम घोषित कर रखा था। जानकारी के अनुसार, करण पटेल खुड़ैल गांव में दूध का व्यवसाय करता है। वहीं उसकी इंस्टाग्राम के जरिए एक प्राइवेट नौकरी करने वाली युवती से जान-पहचान हुई। धीरे-धीरे बातचीत बढ़ी और आरोपी ने युवती को शादी का झांसा दिया। इसके बाद वह उसे तीन इमली क्षेत्र स्थित एक होटल में ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म कर फरार हो गया। पीड़िता की शिकायत पर आजाद नगर पुलिस ने करण पटेल के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की थी। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने उसके गांव और खेत पर कई बार दबिश दी, लेकिन वह हर बार बच निकलता था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल थाना प्रभारी तिलक करोले के नेतृत्व में आरोपी से पूछताछ की जा रही है।

फरमान शेख 6 माह के लिए जिला बदर

इंदौर। पाटनीपुरा क्षेत्र के शातिर बदमाश फरमान शेख पिता इकबाल शेख के खिलाफ पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर ने मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत सख्त कार्रवाई की है। फरमान को 6 माह के लिए इंदौर (नगरीय व देहात) सहित सीमावर्ती जिलों की सीमा से बाहर कर दिया गया है। थाना एमआईजी पुलिस ने आदेश को लाउडस्पीकर से प्रसारित कर क्षेत्र में जानकारी दी और फरमान व परिजनों को आदेश का पालन सुनिश्चित करने की हिदायत दी है।

फर्जी दस्तावेजों से शिक्षिका बनी महिला को सजा

बड़वाहा। शिक्षा विभाग में नौकरी के लिए फर्जीवाड़ा करने वाली महिला शिक्षिका को अदालत ने कड़ी सजा सुनाई है। रुक्मणी उर्फ बेबी पति विक्रम सिंह चौहान निवासी बड़वाह को प्रथम अपर सत्र न्यायालय बड़वाह ने 7-7 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी महिला ने असली अंजू बाला पिता मन्नालाल राठौर की 10वीं-12वीं की अंकसूचियां और स्वयं का फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाकर शासकीय प्राथमिक विद्यालय क्रमांक 6 बड़वाह में नौकरी हासिल की थी। इस फर्जीवाड़े का खुलासा वर्ष 2017 में आरटीआई कार्यकर्ता प्रेमलाल गुर्जर ने किया। उन्होंने शिक्षा विभाग से प्राप्त दस्तावेजों को असली अंजू बाला से मिलवाया, तो पता चला कि उसकी ही मार्कशीट की छाया प्रति उपयोग की गई थी। इसके बाद अंजू बाला ने शिक्षा विभाग और बड़वाह थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस जांच में रुक्मणी उर्फ बेबी और उसके पति विक्रम सिंह पर मामला पुख्ता पाया गया। प्रकरण में थाना बड़वाह द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर न्यायालय में चालान पेश किया गया। 26 जून 2025 को न्यायालय ने रुक्मणी को धारा 420, 468 में 7-7 साल, धारा 419 में 3 साल व धारा 471 में 2 साल सश्रम कारावास तथा रू. 8000 के जुर्माने की सजा सुनाई। इस मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक चंपालाल मुजाल्दे ने की।

जल संरक्षण का संदेश लेकर निकली साइक्लोथॉन

इंदौर। जल गंगा निर्माण अभियान के अंतर्गत रविवार सुबह रीजनल पार्क से जल बचाव का संदेश लेकर साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत महापौर पुष्यमित्र भार्गव और एमआईसी सदस्य अभिषेक शर्मा बबलू द्वारा साइकिल चलाकर की। जबकि, साइक्लोथॉन को हरी झंडी विधायक मधु वर्मा ने दिखाकर रवाना किया। साइक्लोथॉन दो श्रेणियों में आयोजित की गई। 10 किलोमीटर और 15 किलोमीटर, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिकों, युवाओं और पर्यावरण प्रेमियों ने भाग लिया। साइकिल यात्रा के दौरान प्रतिभागियों ने जल संरक्षण और गंगा संवर्धन का संदेश दिया। आज सुबह रीजनल पार्क साइकिल और साइकिल सवारों से गुलजार रहा। आयोजन का उद्देश्य आमजन को जल बचाने और स्वच्छता बनाए रखने के प्रति जागरूक करना था।

48 घंटे के महाजाम के बाद इंदौर-देवास

रोड खुला तो लोगों का गुस्सा फट पड़ा

किसानों ने 10 दिन का अल्टीमेटम दिया, टोल टैक्स का भी विरोध

इंदौर। इंदौर-देवास हाईवे पर 48 घंटे तक लगा भीषण जाम सिर्फ ट्रैफिक अव्यवस्था नहीं, बल्कि सिस्टम की नाकामी और लापरवाही की खौफनाक मिसाल बन गया। अर्जुन बड़ौदा के पास पुल निर्माण की अनियमितता और खराब सर्विस रोड ने बीते दो दिनों में तीन लोगों कमल पांचाल, बलराम पटेल और संदीप पटेल की जान ले ली। लोगों में इसके खिलाफ भारी रोष है। ये हादसे लापरवाही नहीं, बल्कि उदासीनता के नतीजे हैं। एनएचएआई और ठेकेदारों की सुस्ती, बदइंतजामी और अनदेखी ने सड़क को गड्ढों में बदल दिया। सर्विस लेन कीचड़ और गड्ढों से भरी पड़ी है। बारिश ने हालात और बिगाड़ दिए, लेकिन जिम्मेदारों की आंखें नहीं खुलीं। इंदौर-देवास रोड पर शुक्रवार को 48 घंटे लंबा जाम लगा था। 8 किलोमीटर के इस जाम में 4 हजार गाड़ियां फंसी रही। इस जाम के दौरान तीन लोगों की मौत होना व्यवस्था की बहुत बड़ी खामी माना जा रहा है। इंदौर के कमल पांचाल, शुजालपुर के बलराम पटेल और गारी पिपल्या गांव के संदीप पटेल की मौत हुई। दो को दिल का दौरा पड़ा, जबकि एक मरीज ने अस्पताल पहुंचने से पहले दम तोड़ दिया। इस लंबे जाम में फंसे इंदौर के सैटेलाइट टाउनशिप, बिजलपुर निवासी किसान कमल पांचाल (62) की कार जाम में डेढ़ घंटे तक फंसी रही। इस दौरान उन्हें घबराहट हुई, वे तड़प कर बेहोश हो गए। कमल को देवास के एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। आम लोगों की जिंदगियों की कीमत पर ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के आरोप लग रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अमित चौरसिया ने इन मौतों को 'गैर इरादतन हत्या' करार दिया। पार्टी ने मांग की है कि मृतकों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा मिले और जिम्मेदारों पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो। ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। मौके पर मौजूद रहकर भी ये हालात को संभालने में नाकाम रहे। जाम में फंसी एम्बुलेंस और तड़पते मरीज सिस्टम की घोर संवेदनहीनता की गवाही दे रहे हैं।

किसानों का अल्टीमेटम, हालात सुधारें

इंदौर-देवास रोड पर लगातार जाम और बदहाल हालात को लेकर किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। किसानों ने चेतावनी दी है, कि यदि 10 दिन में इंदौर-देवास मार्ग की स्थिति नहीं सुधारी गई, तो किसान देवास तक पदयात्रा करेंगे। उन्होंने कहा कि मांगलिया रेलवे क्रॉसिंग के पास वैकल्पिक मार्ग को चालू करने, गिट्टी-मुरम डालकर रास्ता बनाने और पुरानी रोड को सुधारने की मांग लंबे समय से की जा रही है, पर नेताओं और अधिकारियों ने अनदेखी की। किसान नेता हंसराज मंडलोई ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि मार्ग की बिगड़ी व्यवस्था को सुधारने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। किसानों का यह भी आरोप है कि मांगलिया टोल कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए व्यासखेड़ी रोड बंद कराया गया, जिससे जाम ने विकराल रूप ले लिया और तीन लोगों की मौत हो गई।

जाम की अव्यवस्था जनता ने संभाली

इस पूरे जाम के दौरान कहीं भी पुलिसकर्मी, अधिकारी और जनप्रतिनिधि नजर नहीं आए। कई जगह जनता ही ट्रैफिक संभालती नजर आई। लोग अपनी दुकानों और काम को छोड़कर जाम में फंसे लोगों की मदद करते रहे। लसूड़िया थाने के सामने ही पूरा रोड कई घंटों तक जाम रहा। जब टीआई तारेश सोनी से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जितना पुलिस फोर्स दिया गया है वह दिन रात जाम खुलवा रहा है। लेकिन, जाम फिर भी नहीं रुका।

टोल-टैक्स का भारी विरोध

अर्जुन बड़ौदा गांव से शुरू हुआ ट्रैफिक जाम दस-बारह किलोमीटर तक फैल गया है। टोल नाके के बाद से ही गाड़ियां अटकने लगी। इंदौर से देवास जाने वाले रास्ते की तरफ फजीहत ज्यादा रही। देवास से इंदौर आ रहे रास्ते पर भी गाड़ियां रांग साइड चलती रही जिससे हालात बिगड़ी। लोगों ने खेत में गाडियां उत्तार दी और निकलने की कोशिश की, लेकिन वे फंस गए। डकाच्या से जयपुरिया कॉलेज होकर जाने वाला वैकल्पिक रास्ता भी बंद हो गया। उस पर भी कई वाहन फंस गए। इस घटना के बाद टोल टैक्स का भारी विरोध हो रहा है। लोगों का कहना है कि किस बात का टोल टैक्स वसूला जा रहा है। न सड़क सुधारते है, न ट्रैफिक की कोई व्यवस्था है। इंदौर की 15वीं बटालियन से सिपाहियों की ड्यूटी लगाई, लेकिन सब नाकाफी साबित हुआ है। ये जाम व्यवस्था के जिम्मेदारों के लिए सबक माना जा रहा है।

इंदौर में 'डिजिटल प्लेट प्रोजेक्ट' की शुरुआत सुदामा नगर से की गई

शहर के हर घर का होगा अलग यूनिक डिजिटल पता

इंदौर। स्वच्छता की राजधानी अब डिजिटल गवर्नेंस की ओर भी सशक्त कदम बढ़ा रही है। वार्ड 82 स्थित सुदामा नगर से 'डिजिटल प्लेट प्रोजेक्ट' का शुभारंभ महापौर पुष्यमित्र भार्गव और नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने किया। इस ऐतिहासिक परियोजना के तहत प्रत्येक घर को जीपीएस आधारित डिजिटल एड्रेस कोड (डीएसी) से युक्त एक यूनिक डिजिटल प्लेट दी जाएगी, जिससे नागरिकों को तमाम सेवाओं का डिजिटल लाभ एक क्लिक पर मिल सकेगा। इस प्लेट में क्यूआर कोड, स्वच्छता रेटिंग,टैक्स डिटेल, शिकायत मॉनिटरिंग, पानी-बिजली जैसी सभी सेवाओं की जानकारी एकीकृत होगी। इसे मोबाइल से स्कैन कर नागरिक तुरंत सारी जानकारी देख

सकेंगे। महापौर भार्गव ने कहा कि सुदामा नगर डिजिटल इंदौर का पहला मॉडल है। जैसे श्रीकृष्ण ने सुदामा को सौगात दी थी, वैसे ही हम इस क्षेत्र को डिजिटल, साफ-सुथरी सड़कें और बेहतर ड्रेनेज की सौगात दे रहे हैं। यह क्षेत्र मेरे लिए काशी जैसा पवित्र है। आयुक्त शिवम वर्मा ने इसे 'ऐतिहासिक बदलाव' बताते हुए कहा कि यह तकनीक-आधारित प्लेटफॉर्म नगर सेवाओं को पारदर्शी, त्वरित और नागरिकों के लिए अधिक सुलभ बनाएगा।

नागरिकों को मिलेंगे कई लाभ

- हर घर को मिलेगा यूनिक डिजिटल पता
- सेवाओं की ट्रैकिंग होगी आसान
- ई-कॉमर्स और सरकारी योजनाओं में सटीक डिलीवरी
- मेडिकल या आपदा स्थिति में लोकेशन ट्रेसिंग

शिलांग एसआईटी शिलोम को इंदौर लाई, गहने रतलाम में ठिकाने लगाए

मामले के साक्ष्य नष्ट करने के आरोप में उससे पूछताछ चल रही

इंदौर। शनिवार रात शिलांग से एसआईटी प्रॉपर्टी ब्रोकर शिलोम को इंदौर लेकर आई और उसके घर की तलाशी ली। शिलोम को फ्लाइट से लेकर आई टीम ने राजा और सोनम के छुपाए गए गहनों को उसके घर में तलाश किया। करीब एक घंटे तक घर में छानबीन कर टीम रवाना हो गई। इस दौरान महिलाओं से भी पूछताछ की गई। बताते हैं कि शिलोम ने बाद में बताया कि उसने उन गहनों को रतलाम में ठिकाने लगाया है। पुलिस उसे रतलाम भी लेकर जा सकती है।

महालक्ष्मी नगर निवासी प्रॉपर्टी ब्रोकर शिलोम जेम्स से साक्ष्य नष्ट करने के आरोप में पूछताछ चल रही है। ईस्ट खासी हिल्स शिलांग पुलिस और एसआईटी शनिवार शाम 7.30 बजे की फ्लाइट से इंदौर पहुंची। क्राइम ब्रांच थाने में आमद दर्ज करवाई और कार (एमपी 09 डब्ल्यूएम 9493) से सीधे महालक्ष्मी नगर पहुंचे। एक अन्य कार (एमपी 03 ए 2423) में क्राइम ब्रांच के अफसर थे। अफसरों ने घर के दरवाजे बंद कर शिलोम और उसके परिवार की महिलाओं से पूछताछ की। आभूषण जब्ती की अधिकृत जानकारी अभी नहीं मिली है।

ब्रोकर, बिल्डर, चौकीदार रिमांड पर

शिलोम (ब्रोकर), लोकेंद्र तोमर (बिल्डर) और बलवीर अहिरवार (चौकीदार) छह दिन की पुलिस रिमांड पर हैं। एसआईटी ने 26 जून को उन्हें कोर्ट में पेश किया था। शिलोम ने विशाल को फ्लैट किराए पर दिया था। इसमें सोनम रघुवंशी रुकी थी। हीराबाग स्थित फ्लैट लोकेंद्र का है। सोनम की गिरफ्तारी के बाद लोकेंद्र, सिलोम और बलवीर ने बैग गायब कर दिए थे। शिलोम सोनम का एक बैग निपानिया क्षेत्र में जला चुका है। उसमें भी मोबाइल व अन्य सामान था। लैपटॉप वाला बैग फेंकना बता रहा है। पुलिस उससे लैपटाप के संबंध में भी पूछताछ करेगी।

साइबर सेल को अमेरिका से 'चाइल्ड पोर्नोग्राफी' की शिकायत भेजी गई!

60 साल के ड्राइवर पर अश्लील वीडियो शेयर करने का आरोप

इंदौर। राज्य साइबर सेल ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी के एक मामले में कार्रवाई करते हुए इंदौर में एक 60 साल के ऑटो चालक को गिरफ्तार किया। आरोपी का नाम इरशाद है, वह खजराना इलाके का रहने वाला है। उस पर नाबालिगों से संबंधित अश्लील वीडियो शेयर करने का आरोप है। इंदौर में स्टेट साइबर सेल थाना पुलिस ने वॉट्सएप इंक यूनाइटेड स्टेट से मिली जानकारी के बाद केस दर्ज किया गया। मामले का खुलासा तब हुआ, जब अमेरिका स्थित वॉट्सएप इंक ने भारत सरकार की साइबर टिपलाइन को एक शिकायत भेजी। यह शिकायत चाइल्ड पोर्नोग्राफी कंटेंट के डाउनलोड और शेयरिंग से जुड़ी थी। इसमें आरोपी की संलिप्तता पाई गई। गृह मंत्रालय की साइबर यूनिट से यह सूचना इंदौर की राज्य साइबर सेल को मिली। साइबर सेल के इंस्पेक्टर दिनेश वर्मा ने बताया कि आरोपी की उम्र 60 साल है। वो ई-रिक्शा चालक है। उसने व्हाट्सएप के जरिए बच्चों से जुड़ी पोर्न क्लिप शेयर की थीं। इसके बाद पुलिस से बचने के लिए उसने आरोपी ने अपने मोबाइल फोन फॉर्मेट कर दिया था। लेकिन, पुलिस ने आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर डिलीट किए गए आपत्तिजनक वीडियो को रिकवर कर लिया। गुरुवार को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। 60 वर्षीय इरशाद स्कूली छात्र-छात्राओं को लाने एवं ले जाने का काम करता है। उसने पूछताछ में स्वीकारा कि उसने वाट्सएप के माध्यम से मिला वीडियो अन्य लोगों में शेयर भी किया था। ऑटो चालक इरशाद वॉट्सएप पर अश्लील वीडियो चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाउनलोड कर शेयर कर रहा था। उसे पता नहीं था कि वाट्सऐप इंक यूनाइटेड स्टेट से निगरानी हो रही थी। इस मामले में भारत सरकार के गृह मंत्रालय की साइबर टिप लाइन के माध्यम से शिकायत स्टेट साइबर सेल इंदौर को दी गई। बताया गया कि इरशाद अपने वॉट्सएप पर कई ग्रुप में चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित कंटेंट शेयर कर रहा है। इसके बाद साइबर पुलिस ने खजराना इलाके से इरशाद को अरेस्ट कर उसका मोबाइल जब्त किया।

सुप्रीम कोर्ट ने क्रूरता करार दिया

नाबालिग बच्चों के साथ यौन गतिविधियों के संबंध में बनाए गए वीडियो चाइल्ड पोर्नोग्राफी की श्रेणी में आते हैं। इसमें वीडियो और तस्वीर दोनों शामिल है। इसको लेकर पिछले साल मद्रास हाई कोर्ट के एक फैसले पर आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्रूर करार दिया था। मद्रास हाई कोर्ट ने अपने फैसले में चाइल्ड पोर्नोग्राफी को अपराध की श्रेणी में रखने से इनकार कर दिया था। नाबालिग बच्चों के साथ यौन गतिविधियों के संबंध में बनाए गए वीडियो चाइल्ड पोर्नोग्राफी की श्रेणी में आते हैं, इसमें वीडियो और तस्वीर दोनों शामिल है। इसको लेकर पिछले साल मद्रास हाई कोर्ट के एक फैसले पर आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्रूर करार दिया था। मद्रास हाई कोर्ट ने अपने फैसले में चाइल्ड पोर्नोग्राफी को अपराध की श्रेणी में रखने से इनकार कर दिया था।

रंगवासा में करोड़पतियों को पट्टे 5 महीने बाद भी कार्रवाई नहीं

जिम्मेदार अधिकारी मौन, सरपंच व सचिव को कौन बचा रहा

इंदौर। रंगवासा ग्राम पंचायत में करोड़पतियों को आबादी क्षेत्र की सरकारी जमीन के 59 पट्टे बांटे जाने का मामला अब भी अधर में लटका है। वर्ष 2018 से 2021 के बीच तत्कालीन सरपंच श्याम पांडे और सचिव रमेश भाभर ने नियमों की अनदेखी कर यह पट्टे बांटे थे। इस गंभीर अनियमितता की शिकायत के बाद तहसीलदार राऊ ने जांच कर रिपोर्ट एसडीएम राकेश परमार को सौंपी थी। एसडीएम ने 31 जनवरी 2024 को जिला पंचायत और जनपद पंचायत सीईओ को पत्र भेजकर अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की थी। लेकिन, 15 महीने बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। यह सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिर दोषियों को राजनीतिक संरक्षण क्यों मिल रहा है! जांच अधिकारी धीरेंद्र सोनी ने सचिव रमेश भाभर को कई बार नोटिस दिए,,लेकिन वह कभी भी उपस्थित नहीं हुए। इसके बावजूद उन्हें बार-बार समय दिया जाता रहा। वहीं, जांच के दौरान ही सरपंच और सचिव ने अपने स्तर पर पट्टे निरस्त भी कर दिए, जो उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर था। सचिव ने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर से इंकार किया, जबकि शिकायतकर्ताओं ने ऐसे प्रमाण प्रस्तुत किए जिनमें उसके हस्ताक्षर स्पष्ट रूप से मौजूद थे।

अब बड़ा सवाल यह है कि जांच और सिफारिशों के बावजूद सीईओ जिला व जनपद पंचायत कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे! शिकायतकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने कई बार अधिकारियों से संपर्क किया। लेकिन, हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिला। रमेश भाभर पिछले 10 वर्षों से अधिक रंगवासा पंचायत में पदस्थ है और उसके खिलाफ भ्रष्टाचार की कई शिकायतें लंबित हैं। फिर भी उसे बचाया जा रहा है।

बरसात के दौरान बायपास का ट्रैफिक सुधार की मुहिम, कलेक्टर के निर्देश

सुचारू ट्रैफिक के लिए कई अधिकारी बायपास पर तैनात किए

इंदौर। मानसून सत्र के दौरान इंदौर शहर और राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर आशीष सिंह ने शुक्रवार को संबंधित विभागों की महत्वपूर्ण बैठक ली। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि वर्षाकाल के दौरान किसी भी स्थिति में शहर में ट्रैफिक बाधित न हो, इसके लिए विशेष निगरानी और प्रबंधन जरूरी है। खुद कलेक्टर आशीष सिंह ने भी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि वर्षाकाल के दौरान किसी भी स्थिति में शहर में ट्रैफिक बाधित न हो, इसके लिए विशेष निगरानी और प्रबंधन जरूरी है। निर्माणाधीन ओवरब्रिज के डायवर्सन व सर्विस रोड की स्थिति सुधारने के लिए एनएचएआई को तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। निर्माणाधीन ओवरब्रिज के

डायवर्सन व सर्विस रोड की स्थिति सुधारने के लिए एनएचएआई को तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में नगर निगम, ट्रैफिक पुलिस, एनएचएआई, पीडब्ल्यूडी सहित कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। भारी वाहनों की भीड़ से निपटने के लिए बायपास के वैकल्पिक मार्ग तय किए गए हैं। देवास के लिए मानपुर, घाटाबिल्लोद,लेबड़, बदनावर होकर बड़नगर मार्ग,भोपाल के लिए देवगुराड़िया,डबल चौकी,चापड़ा मार्ग,शिप्रा के लिए डकाच्या, जयपुरिया मार्ग सुझाए गए हैं। कलेक्टर ने ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए क्यूआरटी दल (त्वरित रिस्पांस टीम) गठित करने के निर्देश भी दिए, जिसमें ट्रैफिक पुलिस के साथ नगर निगम और होमगार्ड को शामिल किया जाएगा। जलभराव से निपटने के लिए ड्रेनेज और जल निकासी तंत्र सक्रिय रखने को भी कहा गया।

जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद - कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर व्यापक प्रबंध किए गए हैं, एडीएम, एसडीएम और संबंधित विभागों का अमला बायपास पर तैनात है। कलेक्टर के निर्देश पर शनिवार सुबह से ही जिला प्रशासन, पुलिस, यातायात पुलिस, होमगार्ड, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सहित संबंधित विभागों के अधिकारी पूरी सक्रियता से कार्य में जुटे हैं। कलेक्टर स्वयं स्थिति की लगातार समीक्षा कर रहे हैं। एडीएम रोशन राय अर्जुन बड़ौदा क्षेत्र में पूरी टीम के साथ तैनात हैं और ट्रैफिक नियंत्रण की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। देवगराड़िया क्षेत्र में एसडीएम अजय शुक्ला स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। जबकि, मानपुर क्षेत्र में एसडीएम राकेश परमार संबंधित विभागों के अधिकारियों और अमले के साथ मिलकर व्यवस्था संभाल रहे हैं। वे भारी वाहनों को वैकल्पिक मार्गों की ओर मोड़ने का कार्य भी करा रहे हैं ताकि मुख्य मार्गों पर यातायात का दबाव न बढ़े। प्रशासन की तत्परता और विभागीय समन्वय के चलते अब बायपास पर यातायात सामान्य बन रहा है।

संपादकीय

बिहार ने रचा इतिहास

अमूमन राजनीति, जातिवाद और भ्रष्टाचार को छोड़कर बाकी मामलों में फिसड्डी समझे जाने वाले बिहार द्वारा एक संदर्भ में इतिहास रचना अपने आप में सुखद है। यहां स्थानीय निकाय चुनावों में राज्य चुनाव आयोग ने पहली बार मोबाइल फोन के जरिए वोटिंग का सफल प्रयोग किया, जिसे काफी उत्साह से लिया गया। इसे देश में ई-वोटिंग का आगाज माना जा रहा है। हालांकि मतदाताओं के सामने पारंपरिक तरीके से मतदान का विकल्प भी मौजूद था। इस पहल को राज्य चुनाव आयोग द्वारा तकनीक के सहारे लोकतंत्र को अधिक सुलभ और समावेशी बनाने की दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है। इसमें पूर्वी चंपारण की बिभा कुमारी मोबाइल से वोट डालने वाली देश की पहली मतदाता बनीं। इस उपलब्धि को राज्य चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर साझा करते हुए इसे 'सुविधा, सुरक्षा और सशक्त भागीदारी का प्रतीक' बताया। राज्य चुनाव आयुक्त दीपक प्रसाद के अनुसार मोबाइल आधारित ई-वोटिंग के लिए पात्र मतदाताओं में से 70.20 प्रतिशत ने इस नई प्रणाली के माध्यम से मतदान किया, जबकि 54.63 प्रतिशत मतदाताओं ने पारंपरिक मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि ई-वोटिंग विशेष रूप से उन मतदाताओं के लिए फायदेमंद है, जो किसी कारणवश मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच सकते, जैसे बुजुर्ग, दिव्यांग, गर्भवती महिलाएं और प्रवासी। हालांकि, इस सुविधा का लाभ केवल उन्हीं मतदाताओं को दिया गया जो पहले से पंजीकृत थे। राज्य निर्वाचन आयुक्त दीपक प्रसाद के अनुसार दुनिया के कुछ ही देशों में ऐसा होता है, जिनमें एस्टोनिया एक उदाहरण है। आयोग ने इसके लिए 10 से 22 जून तक एक विशेष अभियान चलाया था। रिटर्निंग ऑफिसर की टीमों ने लोगों को ई-वोटिंग के लिए जागरूक किया। हेल्प डेस्क, रैली और पोस्टरों के ज़रिए प्रचार किया गया। गौरतलब है कि राज्य की 6 नगर पंचायतों और नगरपालिकाओं में हुए उपचुनावों में कुल मिलाकर 62.41 प्रतिशत मतदान दर्ज हुआ। इसमें कुल 538 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। मतदान शांतिपूर्ण रहा। ये चुनाव पटना, बक्सर, भोजपुर, कैमूर, नालंदा, कटिहार, अररिया, सहरसा और पूर्वी चंपारण जैसे जिलों में नगर पंचायत और नगर निगम के उपचुनाव कराए गए। मतों की गिनती 30 जून को की जाएगी। आयोग का मानना है कि ई-वोटिंग प्रणाली न केवल समय की बचत करेगी बल्कि मतदान की पारदर्शिता और भागीदारी को भी बढ़ाएगी। बिहार की यह पहल अन्य राज्यों के लिए भी एक उदाहरण बन सकती है, जहां मतदान में गिरती भागीदारी चिंता का विषय बनी हुई है। आयोग को उम्मीद है कि इस नई तकनीक के चलते मतदान में युवाओं के साथ साथ बुजुर्गों, दिव्यांगों और बीमार मतदाताओं की भागीदारी भी बढ़ेगी। जहां तक राजनीतिक दलों का सवाल है तो किसी ने भी इस प्रयोग का विरोध नहीं किया है। हालांकि चुनाव नतीजों के बाद उनका रुख क्या रहेगा, यह देखने की बात है। क्योंकि अभी तो राज्य में तमाम विपक्षी दल भारत निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान का ही विरोध कर रहे हैं। अगर इन चुनावों के नतीजे भी उनकी अपेक्षा के विपरीत रहे तो नई तकनीक का व्यापक विरोध शुरू हो जाएगा। वैसे इन चुनाव का फिलहाल बहुत ज्यादा महत्व नहीं है, क्योंकि बिहार में चार बाद ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसमें तय होगा कि बिहार पर अगले पांच साल फिर कौन राज करेगा? क्या राज्य में नीतीश कुमार युग समाप्त होगा या नहीं? क्या बिहार की जनता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन को सत्ता सौंपेगी? क्या इस बार चुनाव में ओवैसी की पार्टी कुछ कमाल करेगी? इनके जवाब भी भविष्य में मिलेंगे, लेकिन स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजे राज्य के राजनीतिक मिजाज का संकेत जरूर देंगे।

नजरिया

रघु ठाकुर

लेखक समाजवादी विचारक हैं।

महिलाओं के प्रति सम्मान के बिना कैसे आएगी समता?

पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर में श्रीमती सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह ने भी महिलाओं की शक्ति और योग्यता का एहसास कराया है। 1960 के दशक में डॉ. लोहिया ने लिखा था कि हमारे देश में जाति और योनि के दो कटघरे में देश की बड़ी संख्या को कैद कर दिया गया और निर्जीव बना दिया गया है। जिस जमाने में किसी ने नारी सशक्तिकरण जैसा शब्द सुनना तो दूर सोचा भी नहीं होगा, उस जमाने में लोहिया न केवल नारियों को जाति व परंपरा के बंधन से मुक्त कर पुरुष के समकक्ष खड़े करने के लिए संघर्षरत थे। उन्होंने द्रौपदी बनाम सावित्री की बहस को प्रतीकात्मक स्वरूप देकर द्रौपदी के संघर्षशील पक्ष को उभारा। नारी की क्षमता, योग्यता संघर्ष की प्रतिभा को एक नए ढंग से प्रस्तुत किया। लोहिया के जीवन काल में इन सवालों पर हलचल तो शुरू हुई परंतु वह शुरुआत भर थी। लोहिया कहते भी थे कि लोग मेरी बात सुनेंगे शायद मेरे मरने के बाद, पर सुनेंगे जरूर। आज जब सुनीता विलियम्स से लेकर सोफिया कुरैशी विभिन्न क्षेत्रों में नारियों के उपलब्धियों के किस्से छपते हैं तब लगता है लोहिया की बात सुनी जा रही है।

अभी कुछ समय पूर्व संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्णयानुसार समूची दुनिया ने विश्व महिला दिवस मनाया। भारत में भी यह दिवस बड़े पैमाने पर मनाया गया। दुनिया और देश में किस प्रकार महिलाएं आगे जा रही है इसका भी चित्रण किया गया। इसमें कोई दो मत नहीं है कि अवसर मिलने से महिलाओं की प्रतिभा में निखार आता है। उनकी छिपी प्रतिभाएं सामने आई हैं। हाल ही में एक अंतरिक्ष यात्री जिन्होंने 8 माह से अधिक अंतरिक्ष में गुजारे उन सुनीता विलियम्स के साहस और पराक्रम का क्या मुकाबला हो सकता है? यद्यपि पूंजीपतियों में महिलाओं की संख्या अभी कम है।

पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर में श्रीमती सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह ने भी महिलाओं की शक्ति और योग्यता का एहसास कराया है। 1960 के दशक में डॉ. लोहिया ने लिखा था कि हमारे देश में जाति और योनि के दो कटघरे में देश की बड़ी संख्या को कैद कर दिया गया और निर्जीव बना दिया गया है। जिस जमाने में किसी ने नारी सशक्तिकरण जैसा शब्द सुनना तो दूर सोचा भी नहीं होगा, उस जमाने में लोहिया न केवल नारियों को जाति व परंपरा के बंधन से मुक्त कर पुरुष के समकक्ष खड़े करने के लिए संघर्षरत थे। उन्होंने द्रौपदी बनाम सावित्री की बहस को प्रतीकात्मक स्वरूप देकर द्रौपदी के संघर्षशील पक्ष को उभारा। नारी की क्षमता, योग्यता संघर्ष की प्रतिभा को एक नए ढंग से प्रस्तुत किया। लोहिया के जीवन काल में इन सवालों पर हलचल तो शुरू हुई परंतु वह शुरुआत भर थी। लोहिया कहते भी थे कि लोग मेरी बात सुनेंगे शायद मेरे मरने के बाद, पर सुनेंगे जरूर। आज जब सुनीता विलियम्स से लेकर सोफिया कुरैशी विभिन्न क्षेत्रों में नारियों के उपलब्धियों के किस्से छपते हैं तब लगता है लोहिया की बात सुनी जा रही है।

जहां एक तरफ नारियां आगे बढ़ रही है दूसरी तरफ महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार भेदभाव की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। यदि आप किसी भी दिन के अखबार को देखें या टीवी चौनल के समाचारों को देखें तो आपको प्रतिदिन ऐसी घटनाएं सुर्खियों में मिलती हैं जहां नारी शाब्दिक और शारीरिक अन्याय का शिकार होती है। ऐसी घटनाएं पहले भी होती रही हैं। आज आजादी के सात दशक के बाद भी घट रही हैं। कई बार ऐसा लगता है जैसे प्रगतिशील मानस और पीछे देखू मानस में एक सतत संघर्ष चल रहा है। उत्तर प्रदेश के एक विधायक ने एक लड़की को न केवल हवस का शिकार बनाया बल्कि बाद में उसकी हत्या भी कर दी, ताकि कोई प्रमाण न रहे। तंदूर कांड से लेकर हत्याकांड तक ऐसी घटनाएं निरंतर सामने आ रही हैं। अब पिछले एक डेढ़ दशक से केंद्र और कई सूबे में एक दल की सरकार के बाद ऐसी घटनाओं को पंख लग गए हैं। कुछ दिन पहले एक भाजपा नेता ने टीवी चौनल पर किसी को मां की गालियां दीं। आज भी जो गालियां है वह अमूमन नारियों को लेकर हैं। कहीं ना कहीं मस्तिष्क में नारी को कमजोर और छोटा समझने का भाव है। जिन पार्टियों के नेता नारियों के प्रति ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उनकी पार्टियां उनके बचाव में खड़ी हो जाती हैं। मध्यप्रदेश के एक पूर्व-मुख्यमंत्री ने एक बार एक महिला का उल्लेख करते हुए टंचमाल कहा था। सरकारी पार्टी की महिलाएं भी निजी बातचीत में अपने आप को असुरक्षित मानती हैं और असम्मान का शिकार होती हैं। हाल में मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि लड़कियां कम वस्त्र पहनती हैं जो उन्हें पसंद नहीं। ऐसा एक जुमला वे पहले भी कह चुके हैं। बच्चियां क्या पहनें, उनकी क्या आवश्यकता है, यह निर्णय भी पुरुष समाज लेना चाहता है।

मुझे याद है जब श्रीमती सानिया मिर्जा का नाम टेनिस खिलाड़ी के रूप में उभरा था तो कई मौलवियों ने उनके खिलाफ टिप्पणियां की थीं। एक प्रकार का घोषित अघोषित फतवा जारी किया था। नारियों के प्रति ऐसी घटनाएं आमतौर पर सभी धर्म में हो रही हैं। जहां भी नारियां प्रतिकार में खड़ी होती हैं, जुल्म का शिकार होती हैं। ईरान में हिजाब के खिलाफ लड़ने वाली हजारों बच्चियों को जेल में रहना पड़ा। पाकिस्तान अफगानिस्तान में पढ़ाई और पढ़ाई की वकालत करने वाली बच्चियों को गोली तक खानी पड़ी। यूरोप के देशों में भी महिलाएं कुछ मुक्त तो हुई हैं परंतु बराबरी पर आज भी नहीं हैं। अगर नर-नारी की समता सही मायने में कहीं देखने मिलती है तो वह आदिवासी समाज में। समाज के मानस की जकड़न कितनी गहरी है उसे हाल में अखबार में आई एक घटना से समझा जा सकता है। कटनी में पुलिस विभाग में डीएसपी के पद पर कार्यरत श्रीमति ख्याति मिश्रा ने अपने अधिकारियों से कहा है कि उन्हें अपने पति से खतरा है। कुछ दिनों पूर्व पुलिस ने उनके घर में घुसकर उनके माता-पिता आदि से मारपीट की। इसके पीछे उनके पति को बताया जा रहा है जो तहसीलदार हैं। कटनी की घटना के बाद श्रीमती मिश्रा का तबादला मैहर किया गया। उन्होंने अधिकारियों को पत्र लिखकर मैहर में अपनी जान को खतरा बताया है क्योंकि उनके पति वहां रह चुके हैं। श्रीमति ख्याति मिश्रा के अनुसार उनके पति यह बर्दाश्त नहीं कर कर पा रहे कि पत्नी बड़े पद पर पहुंच गई और वे खुद अभी तहसीलदार ही हैं। अपने मन में यह स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि कोई पद पुरुष से बड़ा होता है। उनके बयान के बाद पति ने पत्नी के पुलिस अधीक्षक से संबंध होने का आरोप लगाया। इस आरोप में कितनी सच्चाई है यह कहना कठिन है। सच्चाई भी है तो इस आधार पर न्यायिक अलगाव की मांग कर सकते थे। पत्नी से अलग रह सकते थे, परंतु उन्होंने यह नहीं किया। आज भी ज्यादातर यही भाव काम कर रहा है कि महिलाओं को पुरुष से नीचे रहना चाहिए। सरकार इसे किस रूप में ले रही है यह अभी स्पष्ट नहीं है। लड़कियों के छोटे कपड़ों के प्रति चिंतित मंत्री की भावनाओं को भी प्रदेश सरकार किस भाव से ले रही है कहना कठिन है। कुछ लोगों का यह भी मानना है की मंत्री का बयान उनके संगठन के इशारे पर दिया गया है जो भारत को सनातन में ले जाना चाहता है। परंपराओं में महिलाओं का पतिव होना, उनका दासी होना, पर्दे में रहना सभी घोषित सामाजिक परंपराएं हैं। कुछ साल पहले भी मंत्री ने एक प्रसंग में कुछ महिलाओं की तुलना शुर्पणखा से की थी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री रावत ने भी महिलाओं के जींस पहनने की निंदा की थी। उसे संस्कृति विरोधी बताया था कई बड़े तथाकथित जनप्रतिनिधि या सत्ताधारी नेता कपड़ों को ही बलात्कार का कारण बताते हैं। ऐसी और भी बहुत सी घटनाएं हैं जिसमें कोलकाता की डॉक्टर लड़की के बलात्कार से लेकर निर्भया तक आए दिन घट रहे अपराधों को उद्धृत किया जा सकता है। यह बड़ा विचित्र और दुखद है कि हाल की घटनाओं के बाद देश के महिला संगठनों द्वारा इस प्रकार की घटनाओं को लेकर कोई विशेष भूमिका दिखाई नहीं दी।

मेरा यह कहना नहीं है कि महिलाओं के सम्मान की रक्षा करना केवल महिला का दायित्व है। समूचा पुरुष समाज राजनीति वोट के लिए असहाय है। मध्य प्रदेश के वन मंत्री के द्वारा सुश्री सोफिया कुरैशी के बारे में दिए गए बयान के बाद भी न मंत्री जी का इस्तीफा हुआ, न उन्हें हटाया गया, न उन पर मुकदमा दर्ज हुआ। ऐसा लगता है कि संघ व संगठन मामले के शांत होने की प्रतीक्षा कर रहा है। प्रधानमंत्री जी भी 3 जून 2025 को भोपाल आए थे जहां मीडिया के अनुसार उन्होंने कई लाख महिलाओं को संबोधित किया था। इस सम्मेलन में वे सरकार की उपलब्धियां को गिनाते रहे। पर एक शब्द भी उन्होंने अपने मंत्रियों के खिलाफ बोलने का साहस नहीं किया। यानी वे भी यह जानते मानते हैं कि देश में आम मानस अभी भी पुरुष सत्तात्मक का है। इसलिए वे अपने वोट के खेल में कोई जोखिम नहीं लेना चाहते। प्रधानमंत्री की इस स्थिति के वास्तविक कारण क्या हैं? मेरा मानना है कि कारण जो भी हों उन्हें उन कारणों से मुक्ति पाना चाहिए। देश को स्पष्ट तौर पर बताना चाहिए। देश जानना चाहता है कि सोफिया कुरैशी से लेकर कम वस्त्रों तक जो मानसिकता समाज व सत्तापक्ष में उभरी है वे उसे मिटाना चाहते हैं या बनाए रखना चाहते हैं। क्या उनकी पार्टी सनातन व्यवस्था के नाम पर उस दौर में जाना चाहती है जहां नारी को दोयम दर्जा का माना जाएगा? जहां महिलाएं पुरुषों की दासी बन कर रहें? लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, सावित्री, पार्वती ऐसी महान नारियों की पूजा करना यह समता नहीं है जो हाथ पाषाण प्रतिमा को पूजते हैं वही जिंदा तन को पीटते हैं। यह सरकार व समाज सभी की जिम्मेदारी है कि नर नारी को समान समझा जाए। उन्हें पूरे अवसर मिलें, आजादी मिले उनकी आजादी का सम्मान हो।

सामयिक

प्रमोद भार्गव

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

आतंकवाद पर चीन और पाकिस्तान के दोहरे पैमाने

आतंकवाद के मसले पर चीन के किंगदाओ नगर में हुई शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की बैठक में एक बार फिर चोर-चोर मौसेरे भाई चीन और पाकिस्तान ने भारतीय हितों के परिप्रेक्ष्य में दोगलापन दिखाया है। इस बैठक में सदस्य देशों के रक्षा मंत्री उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आतंकवाद के खात्मे के लिए किए जा रहे आवाहन ने वैश्विक स्तर पर ऐसा माहौल बनाने का काम किया है कि इस समस्या को जड़ से उखाड़ दिया जाए। लेकिन एससीओ की बैठक में जिस दस्तावेज को साझा हस्ताक्षर के लिए सामने लाया गया तब उसमें पहलगाम में हुए आतंकी हमले को शामिल नहीं किया गया। जबकि इस हमले में 26 भारतीय नागरिक आतंकवादियों ने मार दिए थे। इस दस्तावेज में बलूचिस्तान का नाम हैं। जबकि बलूचिस्तान के नागरिक पाकिस्तान के विरुद्ध स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं। अर्थात इस दस्तावेज को पढ़ने के बाद भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कड़ा रुख अपनाते हुए इस पर दस्तखत करने से साफ इंकार कर दिया। इस संगठन पर चीन का प्रभाव है और चीन ही इस बार संगठन का अध्यक्ष देश है। भारत ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले को न केवल पक्षपातपूर्ण माना, बल्कि इसे पाकिस्तान और उसके हितचिंतक चीन की हरकत माना। अतएव राजनाथ सिंह ने दस्तखत नहीं किए। इस संगठन के दस्तावेज की उपयोगता तभी है, जब बैठक में उपस्थित सभी सदस्य देश मुद्दों पर सहमत होकर हस्ताक्षर करने के साथ साझा बयान भी जारी करें। तब कहीं इस दस्तावेज पर सहमति बन पाती है।

इस संगठन में 10 देश परस्पर जुड़े हितों को मजबूत करने के लिए शामिल हैं। इन देशों में भारत, चीन, पाकिस्तान, रूस, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, बेलारूस और तजाकिस्तान शामिल हैं। 2001 में इस संगठन का गठन हुआ था। आरंभ में चीन और रूस समेत पांच देश इसमें शामिल थे। 2001 में उज्बेस्तिन, 2017 में भारत और पाकिस्तान, 2022 में ईरान एवं 2024 में बेलारुस इस संगठन में भागीदार हुए। इन देशों की कुल जीडीपी में 30 फीसदी और दुनिया की आबादी में 40 प्रतिशत हिस्सेदारी है। यानी इस संगठन की इन देशों की अर्थव्यवस्था के लिए परस्पर भागीदारी जरूरी है। लेकिन जब राजनाथ सिंह ने दस्तावेज की इबारत को पक्षपात पूर्ण पाया तो उन्होंने खुले षब्दों में कहा, 'भारत आतंकवाद पर दोहरे मापदंड मंजूर नहीं करेगा। आतंक को बढ़ावा देने वाले देशों की खुली निंदा होनी चाहिए। कुछ देशों ने सीमा पार आतंकवाद को न केवल अपनी नीति ही मान लिया है, बल्कि अपने देश में उन्हें संरक्षण भी देते हैं। बावजूद इस हकीकत को नकारते हैं। ऐसे दोहरे मापदंडों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। उन्हें अब समझना होगा कि आतंकवाद के अधिकेंद्र (एपीसेंटर) अब सुरक्षित नहीं रह गए हैं।' नए भारत के इस कड़े संदेश ने उपस्थित रक्षा मंत्रियों को हैरानी में डाल दिया। अतएव न तो कोई सहमति बन पाई और न ही संयुक्त बयान जारी हो पाया। इस परिणाम ने समूची दुनिया को संदेश दे दिया है कि अब भारत अपने हितों से समझौता करने के लिए कतई तैयार नहीं है।

दरअसल भारत चाहता था कि एससीओ पहलगाम हमले की निदां करे और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर स्पष्ट रुख अपनाए। लेकिन चीन की एक बार फिर दगा की दोगली नीति सामने आ गई। एक सदस्य देश ने इस पहलगाम मुद्दे को दस्तावेज में षामिल करने से असहमति जता दी। वस्तुतः राजनाथ सिंह ने कड़ा रुख अपना लिया और दस्तखत नहीं किए। इस साझा बयान पर हस्ताक्षर नहीं करने का बड़ा कारण दस्तावेज न तो निश्पक्ष था और न ही इसमें कोई पारदर्शिता थी। यह भी साफ नहीं किया कि आखिर इस अभिलेख को किन देशों ने तैयार किया है। यह दस्तावेज आतंकवाद से जुड़े तथ्यों के विपरीत था। भारत के जम्मू-कश्मीर प्रांत में 22 अप्रैल को पहलगाम में सैलानियों पर बड़ा हमला हुआ था। इसमें 26 निर्दोष लोग मारे गए थे। आतंकियों द्वारा किया यह हमला मानवता के लिए क्रूरता का चरम था। इसलिए भारत ने इस आतंकी हमले को दस्तावेज में शामिल करने की मांग भी की थी। परंतु इस मांग को नमंजुर कर दिया गया। अध्यक्षता कर रहे चीन का यह रुख पाकिस्तान के प्रति उदारता जताता है, जो सर्वथा पक्षपातपूर्ण है। जबकि बलूचिस्तान की आतंकी गतिविधियों से जुड़ी जफर एक्सप्रेस की घटना इसमें दर्ज थी। इस संगठन का लक्ष्य शामिल देशों की सुरक्षा, आर्थिक और राजनीतिक सहयोग को बढ़ाने के साथ आतंकवाद, नशीले पदार्थों की तस्करी और साइबर आपराध जैसे मसलों पर सटीक रणनीति बनाकर उस पर संयुक्त पहल करना भी है। लेकिन जिस तरह से पहलगाम हमले को नजरअंदाज किया गया उससे साफ है कि अध्यक्ष देश की नियत साफ नहीं है।

इस तरह का दोहरा चरित्र इसलिए खतरनाक है कि इसने क्षेत्रीय सहयोग से जुड़े मुद्दों पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया। जिसके चलते आतंकवाद की समस्या से निपटना जटिल होगा। क्योंकि पाकिस्तान भारत के विरुद्ध लगातार आतंकी खेल, खेलता हुआ खून की इबारतें लिख रहा है। इस सच्चाई को समूची दुनिया भलीभांति जानती है। क्योंकि भारत आतंक से पिछले ढाई दशक से निरंतर लड़ाई लड़ रहा है। स्वयं चीन ने बीजिंग में कुछ वर्ष पहले हुए ब्रिक्स देशों के सम्मेलन के घोषणा पत्र में इस तथ्य को षामिल किया था कि कई बड़े आतंकवादी संगठन पाकिस्तान के सुरक्षित ठिकानों से अपनी गतिविधियां चलाते हैं।

पहलगाम में किए निरंकुश हमले में भी पाकिस्तान से आए आतंकियों का हाथ था। बावजूद एससीओ की बैठक के संयुक्त बयान में पहलगाम को नजरअंज करना दोगलापन नहीं तो और क्या है ? एससीओ में आतंकवाद पर शिकंजा नहीं कसना इसलिए और चिंताजनक है, क्योंकि पाकिस्तान परमाणु शक्ति संपन्न देश है और वहां अनेक आतंकी संगठन सक्रिय हैं। इन संगठनों में लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिद्दीन और जैश-ए-मोहम्मद प्रमुख हैं। अमेरिका पर आतंकी हमला करने वाले ओसामा बिन लादेन को ही पाकिस्तान ने शरण दी थी। उसका अंत अमेरिकी वायुसेना ने पाकिस्तान में घुसकर किया था। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी सूची में बताया है कि पाक में 136 आतंकवादियों के ठिकाने हैं और यहां 22 आतंकवादी हथियारबंद संगठनों को पाक सेना संरक्षण दे रही है। वाइदवे इन आतंकियों के हाथ परमाणु हथियार लग जाते हैं तो ये मानवता के विरुद्ध कैसी तबाही मचाएंगे, यह कहना अनुमान से परे है। अतएव राजनाथ सिंह ने अभिलेख पर दस्तखत न करके दुनिया को यह संदश दे दिया है कि भारत आतंक के विरुद्ध लड़ाई लड़ता रहेगा।

अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस

प्रो. आरके जैन 'अरिजीत'

लेखक स्तंभकार हैं।

संसदों के अंतर्मंथन का क्षण

जब हम किसी राष्ट्र की आत्मा को समझने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले हमारे सामने उसकी संसद की छवि उभरती है–वह पवित्र मंच, जहाँ जनता की आकांक्षाएँ, चिंताएँ और अधिकार एक स्वर में गूंजते हैं। संसद केवल कानूनों का कारखाना नहीं, बल्कि लोकतंत्र का वह जीवंत हृदय है, जो हर नागरिक की धड़कनों को प्रतिबिंबित करता है। इस जीवंतता को वैश्विक स्तर पर और सशक्त करने के लिए हर साल 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस मनाया जाता है। यह दिन केवल संसदों की उपलब्धियों का उत्सव नहीं, बल्कि उनके दायित्वों, चुनौतियों और भविष्य की दिशा में गहन चिंतन का अवसर है। यह एक ऐसा आह्वान है, जो संसदों को याद दिलाता है कि वे केवल सत्ता का केंद्र नहीं, बल्कि जनता की आवाज़, विश्वास और उम्मीदों का प्रतीक हैं।

इस महत्वपूर्ण दिवस की शुरुआत 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव के माध्यम से हुई, जब 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस के रूप में मान्यता दी गई। यह तारीख संयोगवश 1889 में स्थापित इंटर-पार्लियामेंटरी यूनियन (आईपीयू) की स्थापना की वर्षगांठ से भी जुड़ी है। आईपीयू वह वैश्विक संगठन है, जिसने 136 साल पहले संसदों को एक मंच पर लाकर वैश्विक संवाद, शांति और लोकतंत्र को बढ़ावा देने की नींव रखी। इसका नारा–'लोकतंत्र के लिए, सभी के लिए' और उद्देश्य 'संसदों के माध्यम से विश्व शांति और विकास के लिए हर आवाज़ को सुनना' आज भी उतना ही प्रासंगिक है। 2025 में इस दिवस की थीम 'संसद और सतत विकास लक्ष्य- लैंगिक समानता और समावेशिता' न केवल समय की मांग है, बल्कि लोकतंत्र की सच्ची आत्मा को उजागर करती है। यह थीम हमें याद दिलाती है कि कोई भी लोकतंत्र तब तक पूर्ण नहीं हो सकता, जब तक उसमें हर वर्ग–महिलाएँ, युवा, हाशिए पर पड़े समुदाय, और सामाजिक रूप से उपेक्षित लोग–की समान भागीदारी सुनिश्चित न हो।आज विश्व संयुक्त राष्ट्र के 2030 सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है। इन 17 लक्ष्यों में लैंगिक समानता (एसडीजी-5) और मज़बूत, समावेशी संस्थानों का निर्माण (एसडीजी-16) संसदों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। आंकड़े बताते हैं कि वैश्विक स्तर पर संसदों में महिलाओं की भागीदारी अभी भी केवल 26 प्रतिशत है (आईपीयू, 2023), जबकि भारत में यह आंकड़ा और भी कम, लगभग 14.4 प्रतिशत (लोकसभा, 2024) है। यह असंतुलन न केवल लैंगिक समानता के लिए चुनौती है, बल्कि लोकतंत्र की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाता है। संसदें नीतियां बनाती हैं, संसाधनों का आवंटन करती हैं और सरकार को जवाबदेह बनाती हैं। लेकिन अगर इन नीतियों में आधी आबादी की आवाज़ शामिल नहीं है, तो क्या यह लोकतंत्र वास्तव में 'सभी के लिए' है?भारत, जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इस संदर्भ में एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करता है। भारतीय संसद, लोकसभा और राज्यसभा, करोड़ों लोगों की आकांक्षाओं का केंद्र है। यह वह मंच है, जहाँ 1.4 अरब लोगों की विविधता को एक स्वर में ढाला जाता है। लेकिन इस विविधता को प्रतिबिंबित करने के लिए संसद को और अधिक समावेशी होना होगा। उदाहरण के लिए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के तहत संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान एक ऐतिहासिक कदम है, लेकिन इसका पूर्ण कार्यान्वयन अभी बाकी है। इसी तरह, युवाओं और हाशिए पर पड़े समुदायों जैसे आदिवासियों, दलितों, और एलजीबीटीक्यू+ समुदाय को संसद में अधिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है। आंकड़े बताते हैं कि भारत में 65 प्रतिशत आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है, लेकिन संसद में युवा सांसदों की संख्या केवल 12 प्रतिशत के आसपास है। यह असंतुलन न केवल नीतियों को प्रभावित करता है, बल्कि युवाओं के बीच राजनीतिक संस्थानों के प्रति विश्वास को भी कम करता है।

अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस हमें उन मूलभूत सवालों से रूबरू कराता है, जो अक्सर संसदीय बहसों के शोर में दब जाते हैं। क्या संसदें जनता के सबसे ज़रूरी मुद्दों को प्राथमिकता दे रही हैं? क्या वे लैंगिक भेदभाव, सामाजिक असमानता और पर्यावरणीय संकट जैसे मुद्दों पर ठोस कदम उठा रही हैं? आईपीयू की 2022 की वैश्विक संसदीय रिपोर्ट के अनुसार, केवल 40त्न संसदों ने ही सतत विकास लक्ष्यों को अपनी नीतियों में स्पष्ट रूप से शामिल किया है। यह आंकड़ा चेतावनी देता है कि संसदों को अपनी भूमिका को और अधिक सक्रिय और प्रभावी बनाना होगा। भारत में, उदाहरण के लिए, संसद ने जलवायु परिवर्तन (एसडीजी-13) और शिक्षा (एसडीजी-4) जैसे क्षेत्रों में कई नीतियां बनाई हैं, लेकिन उनकी निगरानी और कार्यान्वयन में कमी दिखती है।संसदों की जवाबदेही और पारदर्शिता लोकतंत्र की नींव है। आईपीयू के अनुसार, विश्व की 80 प्रतिशत संसदें अब डिजिटल तकनीकों का उपयोग कर रही हैं, जैसे कि ऑनलाइन सत्र, ई-वोटिंग, और नागरिक संवाद मंच। भारत में भी डिजिटल संसद पहल के तहत संसद के सत्रों को डिजिटल रूप से प्रसारित किया जा रहा है, लेकिन नागरिकों की सीधी भागीदारी अभी भी सीमित है। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि संसदें न केवल नीतियां बनाएं, बल्कि नागरिकों के साथ सीधा संवाद स्थापित करें। उदाहरण के लिए, न्यूज़ीलैंड और कनाडा जैसे देशों में 'संसदीय ओपन डे' जैसे आयोजन होते हैं, जहाँ आम लोग संसद में जाकर अपने सांसदों से मिल सकते हैं। भारत में भी इस तरह की पहल लोकतंत्र को और जीवंत बना सकती हैं।

इस दिवस का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि यह संसदों को आत्म-मूल्यांकन का अवसर देता है। क्या संसदें वास्तव में समावेशी हैं? क्या वे बदलते समय के साथ तालमेल बिठा रही हैं? आईपीयू की एक रिपोर्ट के अनुसार, विश्व की केवल 20त्न संसदों में ही लैंगिक समानता और समावेशिता के लिए विशेष समितियाँ हैं। भारत में, हालाँकि संसद में महिला सशक्तीकरण समिति जैसी संरचनाएँ हैं, लेकिन इनका प्रभाव अभी व्यापक नहीं हुआ है। यह समय है कि संसदें न केवल कानून बनाएं, बल्कि स्वयं को अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण और जवाबदेह बनाने के लिए नवाचार करें।नागरिकों की भूमिका भी इस दिन उतनी ही महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र केवल संसद तक सीमित नहीं है; यह जनता की जागरूकता और भागीदारी से जीवित रहता है। हम कितनी बार अपने सांसदों से सवाल पूछते हैं? कितनी बार संसद के सत्रों पर ध्यान देते हैं? भारत में, आरटीआई (सूचना का अधिकार) जैसे उपकरणों ने नागरिकों को सशक्त किया है, लेकिन संसदीय कार्यवाहियों में उनकी भागीदारी अभी भी न्यूनतम है। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस हमें यह याद दिलाता है कि लोकतंत्र एक दोतरफा प्रक्रिया है, संसद को जनता के प्रति जवाबदेह होना होगा, और जनता को संसद के प्रति जागरूक। 30 जून केवल एक तारीख नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है–एक संकल्प कि संसदें केवल सत्ता के गलियारों में गूंजने वाली आवाज़ें न बनें, बल्कि समाज के हर कोने तक समानता, न्याय और विकास की गूंज पहुँचाएँ। जब संसदें हर नागरिक की आवाज़ को सुनेंगी–चाहे वह एक महिला हो, एक युवा हो, या समाज के हाशिए पर खड़ा व्यक्ति–तब ही लोकतंत्र एक नारा नहीं, बल्कि एक जीवनशैली बनेगा। यह दिवस हमें यह विश्वास दिलाता है कि संसदें केवल कानून बनाने वाली इमारतें नहीं, बल्कि वे मंदिर हैं, जहाँ मानवता की आकांक्षाएँ आकार लेती हैं। इस 30 जून को हम संकल्प लें कि हमारी संसदें न केवल सशक्त होंगी, बल्कि संवेदनशील, समावेशी और सतत विकास की दिशा में मार्गदर्शक भी बनेंगी। यही लोकतंत्र की सच्ची जीत होगी।

सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं 662, साई कृपा कॉलोनी, बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने, इंदौर से प्रकाशित।
प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
स्थानीय संपादक
हेमंत पाल
प्रबंध संपादक
रमेश रंजन त्रिपाठी
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र इंदौर रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2015/ 66040,
Mobile No.: 09893032101
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

व्यंग्य

डॉ. अतुल चतुर्वेदी

लेखक व्यंग्यकार हैं

एक नोबेल बपु रे दई दो दई

नोबेल पुरस्कार की कामना एक सतत और चिर प्रतीक्षित कामना है। साहित्य के साधकों को तो कई बार ज्ञात भी नहीं होता वे चुपचाप एकला चलो रे के साधना कर्म में लगे रहते हैं लेकिन राजनीतिज्ञों की कार्य शैली अलग तरह की होती है और उसमें भी महामहिम की तो है ही ढिंढोरा पीटन शैली। महामहिम कोई काम शांति और सिस्टम से करने के लिए जन्मे ही नहीं हैं। वो तो धूमकेतु के अपडेटेड वर्जन हैं। उत्पात के अवतार हैं। जो करेंगे ढोल बाजों के साथ। प्रचार की दुनिया के आदमी हैं। आदमी भी खासे दिलचस्प और मजाहिया किस्म के। आज आपके साथ हैं, आपके प्रशंसक हैं क्या पता कल आपके जानी दुश्मन हो जायें। आज आपके बच्चे उनके आँगन में खेल रहे हैं क्या पता कल आपके कपड़े फाड़ने की नौबत आ जाये।

कई बार पता ही नहीं चलता कि अमुक व्यक्ति किसी सर्कस में मसखरे की भूमिका में है या दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति की भूमिका में। पद को इतना सुपद और अवपदित कर दिया है कि आम जन और मीडिया भौंचक है। मजेदार बात यह है कि पहले हम दो विरोधी देशों को हथियार बाँटते हैं फिर वे हथियारों की फूंक में एक दूसरे से लड़ते हैं और अंततः हम महामहिम दोनों में समझौता करवाते हैं। समझौता भी लॉलीपॉप देने का लालच देने के लिए होता है। अब उनको इस युद्ध विराम के लिए नोबेल शांति की आकांक्षा है।

यह तो साठ की दशक की फ़िल्मों सा टुटका हुआ जब हीरो स्वयं गुंडों से आक्रमण करवा कर हीरोइन को इंप्रेस कर देता था। पहले हथियार बाँटो फिर युद्ध रुकवाओ और आखिर में नोबेल शांति की लॉबिंग करो। आखिर शांति के लिए उनके प्रयासों को कौन नहीं जानता? अफ़ग़ानिस्तान , ईराक और पहले वियतनाम तक में उनका देश शांति की पहल ही करता रहा है। नोबेल शांति एक ऐसी चिड़िया है जिसको अपने पिंजरे में क़ैद कर आँगन में सजाने की कामना हर राजनेता की रही है। हमारे देश के भी अनेक पी एम इसकी लाइन में लगे रहे और अब दुनिया के दूसरे बड़े लोकतंत्र के शासनाध्यक्ष इसके लिए दर्दीला बयान जारी कर रहे हैं।

उनकी तुनक मिजाजी के चर्चे कम नहीं हैं। उनका इतिहास ज्ञान भी अद्भुत है, उनकी नवीनतम शोध से ही पता चला कि भारत और पाकिस्तान कश्मीर के लिए हजारों साल से लड़ रहे हैं। दो दिन पूर्व तक वो युद्ध रोकने की बात करते हैं और फिर उनका मूड अचानक बदल जाता है और युद्ध में कूद पड़ते हैं। हमारे देश से तो उनको गहरा लगाव है वे हमारे प्रिय मेहमान भी रहे हैं और हमने उनका दुर्दिनों में साथ भी दिया है प्रचार कर के लेकिन उनको देखकर हमारे रहनुमा जी यही गुनगुनाते होंगे – अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। भारत पर टैरिफ बढ़ा कर और चीन को पहले धमका कर फिर घुटने टेक कर उन्होंने विलक्षण साहस का परिचय दिया है। इस तरह उन्होंने ट्रेड वार को भी रोकने की महान कोशिश की है। तो अर्थशास्त्र का नोबेल भी उनके नाम बनता तो है। शांति नहीं तो अर्थशास्त्र का ही दे दो महामहिम जी को। कितना व्यापार फल फूल रहा है दुनिया में उनकी बदौलत आखिर !

नोबेल का दर्द अनोखा दर्द है। इसकी पीर हर कोई नहीं जानता? जिनको नोबेल मिलना था उन्होंने कभी इस ओर नहीं झांका। चाहे गांधी रहे हो या लियो टॉलस्टॉय। लेकिन राजनेता महत्वाकांक्षी जीव होता है उसका परिणाम में विश्वास होता है त्याग में नहीं। इधर युद्धविराम करवाया उधर नोबेल शांति दे दो।

लगता है नोबेल नादिया किनारे बना एक बंगला है और सुदूर से आवाज आ रही है युद्ध के मुहाने इक नोबेल बपु रे दई दो दई हजारों बेगुनाह नागरिकों और बच्चों की हत्या को नज़रअंदाज़ कर के भी उनको एक नोबेल चाहिए अदद। ताकि इतिहास के सुनहरे अक्षरों में उनका नाम सुरक्षित हो सके। सच मानव मन कितना भोला और निश्छल होता है !

कानून और न्याय

विनय झैलावत
(पूर्व असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल एवं वरिष्ठ अधिवक्ता)

युद्ध की घोषणा के बारे में भारतीय संविधान में क्या प्रावधान

राष्ट्रपति द्वारा युद्ध या शांति की कोई भी औपचारिक घोषणा पूरी तरह से मंत्रिमंडल की सलाह पर की जाती है। वास्तविक निर्णय लेने वाला निकाय केंद्रीय मंत्रिमंडल है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं। संविधान का अनुच्छेद 53(2) घोषित करता है, कि पूर्वगामी प्रावधान की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, संघ के रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान राष्ट्रपति में निहित होगी और उसका प्रयोग कानून द्वारा विनियमित होगा। युद्ध की घोषणा करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। लेकिन, इसका प्रयोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पर किया जाता है।

गंभीर सैन्य तनाव के तहत पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइलों का उपयोग करके जम्मू, पठानकोट और उधमपुर में भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। भारतीय सशस्त्र बलों ने इन स्थानों की सफलतापूर्वक रक्षा की और खतरों को बेअसर कर दिया। जवाब में, भारत ने प्रमुख पाकिस्तानी शहरों इस्लामाबाद, लाहौर और सियालकोट को निशाना बनाकर जोरदार जवाबी कार्रवाई की। यह तीव्र सीमा पार आदान-प्रदान भारत द्वारा 'ऑपरेशन सिंदूर' शुरू किए जाने के बाद हुआ। जिसके तहत भारतीय सशस्त्र बलों ने पहलगाम आतंकवादी हमले का बदला लेने के लिए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नौ स्थानों पर आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर दिया था। फिलहाल युद्ध विराम हो चुका है, लेकिन इस संदर्भ में यह जानना जरुरी है कि कोई युद्ध छिड़ने पर भारतीय संविधान युद्ध की घोषणा के संबंध में क्या कहता है! ऐसी स्थिति में युद्ध की औपचारिक घोषणा आवश्यक है अथवा नहीं, यह आम लोगों में भी स्वाभाविक जिज्ञासा है।

भारत में युद्ध की घोषणा करने के लिए कोई औपचारिक, एकल कानून नहीं है, जैसा कि कुछ अन्य देशों में है। इसके बजाय, ऐसे मामलों को संवैधानिक प्रावधानों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इसका नेतृत्व किया जाता है। राष्ट्रपति इसकी सलाह पर कार्य करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 53(2) के तहत राष्ट्रपति सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर है। हालांकि, राष्ट्रपति स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को केवल केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करना चाहिए। संविधान का अनुच्छेद 53(2) घोषित करता है कि पूर्वगामी प्रावधान की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, संघ के रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान राष्ट्रपति में निहित होगी और उसका प्रयोग कानून द्वारा विनियमित होगा। युद्ध की घोषणा करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। लेकिन, इसका प्रयोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पर किया जाता है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 यह घोषित करता है कि (1) राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होगी, जो अपने कार्यों के निर्वहन में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर सामान्यतः या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। (2) यह प्रश्न कि क्या मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को कोई सलाह दी गई थी और यदि दी गई थी तो क्या, किसी न्यायालय में नहीं पूछा जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53 निर्दिष्ट करता है कि संघ की कार्यकारी शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित है। फिर भी अनुच्छेद 74 के तहत, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के अनुसार कार्य करता है।इसलिए, राष्ट्रपति द्वारा युद्ध या शांति की कोई भी औपचारिक घोषणा पूरी तरह से मंत्रिमंडल की सलाह पर की जाती है। वास्तविक निर्णय लेने वाला निकाय केंद्रीय मंत्रिमंडल है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं।

मंत्रिमंडल रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, सैन्य प्रमुखों और खुफिया एजेंसियों से प्राप्त इनपुट को ध्यान में रखता है। व्यवहार में, युद्ध में जाने या शांति की घोषणा करने का निर्णय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल (मंत्रिपरिषद) द्वारा किया जाता है। रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद इस प्रक्रिया में मंत्रिमंडल को महत्वपूर्ण सलाह देते हैं। किसी निर्णय पर पहुंचने से पहले, मंत्रिमंडल सैन्य प्रमुखों, खुफिया एजेंसियों और राजनयिक चैनलों से इनपुट ले सकता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का नेतृत्व करते हैं, जो राष्ट्रपति को युद्ध की घोषणा की सिफारिश करने के लिए जिम्मेदार हैं। 1978 के 44 वें संशोधन अधिनियम के अनुसार, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल (जो युद्ध की स्थिति में लागू होता है) की घोषणा केवल कैबिनेट की लिखित सिफारिश के आधार पर कर सकते हैं।

संसद को युद्ध की घोषणा को पहले से मंजूरी देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह निगरानी, वित्तपोषण और सरकार को जवाबदेह ठहराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संसद रक्षा बजट की निगरानी करती है और उसे सैन्य कार्रवाइयों पर बहस करने का अधिकार है। हालांकि, संसद संवैधानिक रूप से युद्ध की घोषणा या पूर्व-अनुमोदन करने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन यह निगरानी और वित्तपोषण में भूमिका बनाए रखती है। यह रक्षा बजट की निगरानी करती है, इसके पास सैन्य कार्रवाइयों पर बहस करने और सरकार को जवाबदेह ठहराने का अधिकार है। लंबे समय तक सैन्य मुठभेड़ों के दौरान सरकार से संसद को सूचित करने और राजनीतिक सहमति प्राप्त करने की अपेक्षा की जाती है।

यद्यपि प्रारंभिक युद्ध घोषणा राष्टपति द्वारा मंत्रिमंडल की सलाह पर की जाती है, फिर भी इसे अनुमोदन के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। युद्ध की घोषणा करने के बारे में कोई प्रत्यक्ष संवैधानिक अनुच्छेद नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने की प्रक्रिया युद्ध जैसी स्थिति के दौरान भारत द्वारा उपयोग की जाने वाली सबसे करीबी औपचारिक विधि है। ''प्रक्रियात्मक रूप से कहें तो, यदि युद्ध की औपचारिक घोषणा की जानी है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल, स्थिति का आकलन करने के बाद, राष्ट्रपति को एक लिखित सिफारिश करेगा। मंत्रिमंडल से लिखित सिफारिश प्राप्त करने के बाद, राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत ''युद्ध'' या ''बाहरी आक्रमण'' के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जारी कर सकते हैं।

आपातकाल की यह घोषणा पूरे देश या किसी विशिष्ट भाग पर लागू की जा सकती है। आपातकाल की घोषणा संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जानी चाहिए। यह एक महीने के बाद लागू नहीं होगी जब तक कि दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत (उस सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और उस सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत) से पारित प्रस्तावों द्वारा अनुमोदित न हो जाए। एक बार अनुमोदित के बाद, आपातकाल छह महीने तक सक्रिय रहता है और हर छह महीने में संसद की मंजूरी से इसे नवीनीकृत किया जा सकता है। राष्ट्रपति किसी भी समय किसी बाद की घोषणा के माध्यम से आपातकाल की घोषणा को रद्द कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, 44 वें संशोधन में यह अनिवार्य किया गया है कि यदि लोकसभा आपातकाल को जारी रखने के लिए कोई प्रस्ताव पारित करती है तो राष्टपति को आपातकाल को रद्द करना होगा। लेकिन, युद्ध की घोषणा करने के लिए कोई विशेष नियम नहीं है।

इन सबके बावजूद, भारत के संविधान में युद्ध की घोषणा के लिए कोई विशेष अनुच्छेद नहीं है। हालांकि, भारतीय संविधान में युद्ध की घोषणा के लिए समर्पित कोई विशेष अनुच्छेद या प्रक्रिया नहीं है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित प्रावधानों को युद्ध या बाहरी आक्रमण की स्थितियों में लागू किया जाता है। भारत ने कई युद्ध लड़े हैं, लेकिन उनमें से किसी में भी युद्ध की औपचारिक घोषणा नहीं की गई। सन् 1962 भारत-चीन युद्ध, चीन ने अचानक हमला किया। युद्ध की कोई औपचारिक घोषणा नहीं। यह युद्ध विवादित सीमा पर बड़े पैमाने पर चीनी आक्रमण के साथ शुरू हुआ था। भारत इस हमले से हैरान था। भारत या चीन की ओर से युद्ध की कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई थी। चीन ने एकतरफा युद्ध विराम की घोषणा की और लगभग एक महीने बाद वापस चला गया।

सन् 1965 भारत-पाकिस्तान युद्ध, सीमा पर तनाव और पाकिस्तान के ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम से बढ़ा। युद्ध की कोई औपचारिक घोषणा नहीं। यह युद्ध सीमा पर झड़पों और कश्मीर में पाकिस्तान के ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम से बढ़ा। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके जवाबी कार्रवाई की। फिर से, बड़े पैमाने पर शत्रुता से पहले युद्ध की कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई थी। संघर्ष संयुक्त राष्ट की मध्यस्थता वाले युद्ध विराम और ताषकंद घोषणा के साथ समाप्त हुआ। सन् 1971 भारत-पाकिस्तान युद्ध (बांग्लादेष मुक्ति युद्ध), पूर्वी पाकिस्तान से बड़ी संख्या में शरणार्थियों के आने के बाद भारत ने हस्तक्षेप किया। पाकिस्तान ने पहले हमला किया। युद्ध की कोई औपचारिक घोषणा नहीं। यह युद्ध पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) में राजनीतिक संकट और मानवीय संकट से उपजा था। शरणार्थियों की बड़ी संख्या में आमद के बाद भारत ने बंगाली मुक्ति आंदोलन के समर्थन में हस्तक्षेप किया।

हालांकि संघर्ष व्यापक था, लेकिन भारत की सैन्य भागीदारी से पहले युद्ध की कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई थी। पाकिस्तान ने भारतीय हवाई अड्डों पर हवाई हमले शुरू किए, जिसके कारण भारत ने युद्ध में पूरी तरह से प्रवेष किया। सन् 1999 कारगिल युद्ध, पाकिस्तान ने भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की। भारत ने ऑपरेशन विजय के साथ जवाब दिया। युद्ध की कोई औपचारिक घोषणा नहीं। यह संघर्ष कारगिल क्षेत्र में भारतीय क्षेत्र में पाकिस्तानी सैनिकों और आतंकवादियों की घुसपैठ से शुरू हुआ। भारत ने ऑपरेशन विजय के साथ जवाब दिया, जो कि एक सीमित संघर्ष था और दोनों पक्षों द्वारा युद्ध की कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई थी। इस कारण वर्तमान संदर्भों में भी औपचारिक रूप से युद्ध की कोई घोषणा आवश्यकता नहीं थी।

शिक्षा प्रणाली

मनीष जैसल
स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।

कहीं हम 'गुणवत्ता' को आंकड़ों में तो नहीं खो रहे?

भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली बीते कुछ दशकों में जिस गति से विस्तारित हुई है, उसमें गुणवत्ता की निगरानी एक जटिल कार्य बन गया है। यही कारण था कि वर्ष 1994 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (नेक) की स्थापना की। इसका उद्देश्य देशभर के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की अकादमिक गुणवत्ता का मूल्यांकन करना और उन्हें ग्रेड प्रदान करना रहा है। परंतु तीन दशकों के बाद यह विचार करना आवश्यक है कि क्या यह संस्था वास्तव में उस उद्देश्य को पूर्ण कर पा रही है, जिसके लिए इसकी स्थापना की गई थी।

नेक द्वारा दी जाने वाली ग्रेडिंग न केवल किसी संस्था की सार्वजनिक छवि को प्रभावित करती है, बल्कि इसके माध्यम से सरकारी अनुदान, पाठ्यक्रम-स्वायत्तता और अकादमिक स्वतंत्रता भी तय होती है। नेक के मूल्यांकन मापदंड बहुआयामी होते हैं, जिनमें किसी संस्था के मूल उद्देश्य, शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया, अनुसंधान और नवाचार, बुनियादी ढांचा, छात्र सहयोग, शासन प्रणाली और 'बेस्ट प्रैक्टिस' को सम्मिलित किया जाता है। संस्थानों को ए++ से लेकर डी तक ग्रेड प्रदान किया जाता है। यह ग्रेड न केवल संस्थान की प्रतिष्ठा का सूचक बनते हैं, बल्कि अनुदान प्राप्त करने, मान्यता बनाए रखने और छात्रों को आकर्षित करने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। मगर विडंबना यह है कि ये ग्रेड कई बार संस्थान की जमीनी वास्तविकताओं से मेल नहीं खाते।

ऐश 2020-21 रिपोर्ट, नेक वेबसाइट, और यूजीसी द्वारा प्रकाशित आंकड़े (2024 तक) को आधार बनाकर देखें तो, देश में कुल लगभग 45,000 कॉलेजों में से केवल 4,000 के आसपास ही ऐसे हैं जिन्होंने नेक से मान्यता प्राप्त की है। यह कुल संख्या का मुश्किल से 9 प्रतिशत होता है। इसी प्रकार देश के 1,100 से अधिक विश्वविद्यालयों में से केवल 410 ही मूल्यांकन प्रक्रिया से गुजरे हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि नेक की पहुंच अभी भी सीमित है। इतना ही नहीं, जो संस्थान मूल्यांकन प्रक्रिया में भाग लेते हैं, वे भी कई बार इसे केवल एक औपचारिकता मानते हैं, न कि आंतरिक सुधार का अवसर।

वर्तमान प्रणाली में एक गंभीर समस्या यह देखी गई है कि मूल्यांकन के दौरान अक्सर संस्थानों द्वारा सजाए गए आंकड़ों, प्रस्तुतियों और तथाकथित 'बेस्ट प्रैक्टिस' को ही मूल्यांकन का आधार बना लिया जाता है। मूल्यांकनकर्ता संस्थानों द्वारा तैयार किए गए डॉक्युमेंटेशन पर भरोसा करते हैं, जिससे वास्तविक अकादमिक माहौल का सटीक चित्र सामने नहीं आ पाता। उदाहरणस्वरूप, कुछ संस्थानों को ए या ए+ ग्रेड दिया गया, जबकि छात्रों ने उसी अवधि में बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी, पुस्तकालयों में संसाधनों की अनुपलब्धता और फैकल्टी की अनुपस्थिति की शिकायतें दर्ज की थीं।

नेक के मूल्यांकन में पारदर्शिता की कमी को लेकर अकादमिक जगत में समय-समय पर प्रश्न उठते रहे हैं। कई रिपोर्टों में यह संकेत मिला है कि कुछ संस्थान बाह्य प्रभावों और राजनीतिक संरक्षण के कारण ऊंचे ग्रेड प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं, जबकि कुछ उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान केवल संसाधनों की सीमितता के कारण कम ग्रेड प्राप्त करते हैं। इससे एक 'ग्रेड इनइक्विटी' उत्पन्न होती है, जो संस्थानों के बीच कृत्रिम प्रतिस्पर्धा और असमानता को जन्म देती है।

सवाल यह भी उठता है कि क्या ग्रेड में सुधार वास्तविक सुधार का प्रतिबिंब होता है या केवल पुनः मूल्यांकन और डॉक्युमेंटेशन की कलात्मक प्रस्तुति का परिणाम। 2022 की एक रिपोर्ट में सामने आया कि 200 से अधिक संस्थानों ने अपनी ग्रेडिंग सुधारने हेतु पुनर्मूल्यांकन की याचिका दी थी, जिनमें से अधिकांश को अपेक्षाकृत बेहतर ग्रेड मिला। इससे यह धारणा बनती है कि मूल्यांकन प्रणाली में कठोरता और स्थायित्व का अभाव है।

नेक की प्रक्रिया में एक अन्य प्रमुख चिंता यह है कि यह डिजिटल शिक्षा, नवाचार और आधुनिक शिक्षण तकनीकों को अभी भी सीमित दृष्टि से देखती है। जब शिक्षण संस्थानों में ऑनलाइन पाठ्यक्रम, मोक प्लेटफॉर्म, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित लर्निंग जैसे आधुनिक उपकरणों का प्रयोग किया जा रहा है, तब मूल्यांकन प्रणाली में इनकी भूमिका अपर्याप्त है। परिणामस्वरूप, वे संस्थान जो डिजिटल रूपांतरण की दिशा में अग्रसर हैं, उन्हें भी पारंपरिक मापदंडों के आधार पर ही मूल्यांकित किया जाता है, जिससे उनका यथोचित मूल्यांकन नहीं हो पाता।

छात्रों की दृष्टि से देखा जाए तो नेक ग्रेडिंग कई बार भ्रम का कारण बनती है। विद्यार्थी उच्च ग्रेड देखकर किसी संस्थान में प्रवेश लेते हैं, परंतु बाद में उन्हें अधूरी सुविधाएं, कमजोर फैकल्टी या खराब प्लेसमेंट की सच्चाई का सामना करना पड़ता है। इससे न केवल छात्रों का समय और संसाधन व्यर्थ होते हैं, बल्कि संस्थान की विश्वसनीयता पर भी प्रश्नचिन्ह लगते हैं। यदि ग्रेड गुणवत्ता के सटीक संकेतक नहीं बन पा रहे हैं, तो फिर उनका क्या औचित्य रह जाता है?

निजी और ग्रामीण इलाकों के संस्थानों के बीच भी एक स्पष्ट अंतर दृष्टिगोचर होता है। शहरों में स्थित, संसाधन-सम्पन्न संस्थान अक्सर अच्छी ग्रेडिंग प्राप्त कर लेते हैं, जबकि सीमित संसाधनों में काम कर रहे ग्रामीण कॉलेज, भले ही शैक्षणिक दृष्टि से बेहतर हों, अपेक्षित ग्रेड प्राप्त नहीं कर पाते। इससे ना केवल शिक्षा की गुणवत्ता का असमान वितरण होता है, बल्कि इससे सामाजिक और आर्थिक विषमता को भी बल मिलता है।

हाल के वर्षों में सरकार द्वारा कुछ सुधारात्मक प्रयास किए गए हैं जैसे कि NAAC प्रक्रिया को स्वैच्छिक से अनिवार्य बनाने की दिशा में सोच, मूल्यांकन प्रक्रिया में तकनीकी प्लेटफॉर्म का समावेश, और डेटा स्वचालन की शुरुआत। परंतु ये पहल तब तक प्रभावशाली नहीं हो सकतीं जब तक कि मूल्यांकनकर्ताओं की निष्पक्षता, संस्थानों की ईमानदारी और प्रणाली की पारदर्शिता सुनिश्चित न की जाए। कई बार मूल्यांकनकर्ता के अपने ही संस्थान की ग्रेडिंग का कम होना इस दिशा में और भी बड़े सवाल खड़ा करता है। इसके लिए एक स्वतंत्र निगरानी तंत्र, छात्र व फैकल्टी फीडबैक का सशक्तीकरण, और मूल्यांकन प्रक्रिया को दो-तरफा संवाद का मंच बनाना आवश्यक है।

नेक जैसी संस्था का होना उच्च शिक्षा व्यवस्था के लिए एक सकारात्मक आवश्यकता है। यह गुणवत्ता सुधार की दिशा में एक सैद्धांतिक आधार प्रदान करती है, परंतु इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए इसकी अपनी प्रणाली में निरंतर आत्म-मूल्यांकन, आधुनिकीकरण और आलोचनात्मक प्रतिक्रिया का स्वागत होना चाहिए। आज आवश्यकता है कि नेक स्वयं को केवल एक 'प्रत्यायन एजेंसी' के रूप में न देखकर 'गुणवत्ता सुधार के उत्प्रेरक' के रूप में स्थापित करे।

यदि शिक्षा व्यवस्था को समाज के लिए परिवर्तनकारी बनाना है, तो उसके मूल्यांकन की प्रणाली को भी उतना ही संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह होना होगा। नेक को अपनी भूमिका पर पुनः चिंतन करते हुए उन मूल मूल्यों की ओर लौटना होगा, जिनके लिए उसकी स्थापना की गई थी – अर्थात् सुधार की भावना, निष्पक्षता की प्रतिबद्धता, और गुणवत्ता की खोज।

नेक ग्रेडिंग व्यवस्था अपने प्रारंभिक उद्देश्य में सफल रही है, यह संस्थानों को जवाबदेही, पारदर्शिता और आत्म-चिंतन की दिशा में ले गई है। किंतु यह भी सत्य है कि आज यह व्यवस्था गुणवत्ता सुधार का माध्यम बनने की बजाय कई बार सूचकांक पूर्ति की होड़ बन गई है। हमें यह याद रखना चाहिए कि उच्च शिक्षा केवल इमारतों, लैब और प्रमाणपत्रों का खेल नहीं है। यह ज्ञान, मूल्य और समाज में बदलाव की प्रक्रिया है। यदि मूल्यांकन की प्रणाली उस मूल उद्देश्य से भटकती है, तो हम आंकड़ों की सुनामी में बहते हुए शिक्षा की आत्मा को खो देंगे।

हमें चाहिए एक ऐसा मूल्यांकन मॉडल जो संस्थान के साथ छात्र को भी केंद्र में रखे, जो संख्या से ज़्यादा अनुभव को मापे, और जो गुणवत्ता को सिर्फ रिपोर्ट नहीं, संस्कार बनाये।

मैं स्वयं ऐसे संस्थानों को निकट से जानता हूँ जहाँ शिक्षा की परिभाषा केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं है। वहाँ संगीत, समाज, नृत्य, आधुनिकता और भारतीय ज्ञान परंपरा इन सभी को एक सजीव शैक्षणिक अनुभव के रूप में छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। कक्षाओं के भीतर और बाहर, छात्रों के सोचने, महसूस करने और समझने की क्षमता को गहराई से विकसित किया जाता है। यह संस्थान न केवल ज्ञान देता है, बल्कि छात्रों को अपने समाज, संस्कृति और अस्तित्व से जोड़ता है। अब सवाल यह उठता है – क्या एक ऐसी अन्य सैकड़ों संस्थाएं जो नई पीढ़ी को सोचने और सवाल उठाने की क्षमता से लैस कर रही हैं, महज इसलिए नकार दी जाएंगी क्योंकि वे नेक के औपचारिक ग्रेडिंग मापदंडों पर 'उत्कृष्ट' नहीं मानी जातीं?

यह प्रश्न न केवल उस एक संस्था पर लागू होता है, बल्कि उन सैकड़ों संस्थानों पर भी जो सीमित संसाधनों में भी एक बड़ी सामाजिक भूमिका निभा रहे हैं। शिक्षा का उद्देश्य केवल प्रमाणपत्र देना नहीं होता; यह व्यक्तित्व निर्माण, सामाजिक उत्तरदायित्व और सांस्कृतिक चेतना का वाहक भी होता है। यदि मूल्यांकन प्रणाली इन मूल्यों को न माप सके, तो वह अधूरी ही कही जाएगी।

नेक जैसी संस्था का होना निःसंदेह आवश्यक है, लेकिन उसकी प्रक्रिया को यथार्थ, विविधता और संवेदनशीलता के साथ जोड़ा जाना चाहिए। शिक्षा को आंकने वाली कोई भी प्रणाली तब तक पूर्ण नहीं मानी जा सकती जब तक वह उन संस्थानों की गहराई को न पहचान सके जो चुपचाप, बिना शोर-शराबे के, देश और समाज के भविष्य को आकार दे रहे हैं। यही वह बिंदु है जहाँ नेक को आत्मावलोकन करना होगा और यह तय करना होगा कि वह एक 'रेटिंग एजेंसी' बनना चाहती है या 'रचनात्मक शिक्षा की संरक्षक संस्था'।

जल संकट

डॉ. सत्यवान सौरभ
लेखक स्तंभकार हैं।

नीतियों के बावजूद क्यों प्यासी है भारत की धरती?

भारत की धरती पर जल का संकट एक ऐसी विडंबना बन चुका है, जिसे देखकर हैरानी होती है कि इतनी योजनाओं, घोषणाओं और नीतियों के बावजूद यह देश बूंद–बूंद के लिए क्यों तरस रहा है। जब कोई देश दुनिया की 18 प्रति. जनसंख्या को समेटे हुए हो और उसके पास केवल 4 प्रति. ताजे जल संसाधन हों, तो संकट की आशंका तो बनती है, पर यदि यही देश दशकों से जल संरक्षण और जल प्रबंधन की योजनाओं का ढोल पीटता हो और फिर भी सूखा, प्यास, और जलजनित बीमारियाँ उसके हिस्से में आएं — तो यह केवल प्राकृतिक संकट नहीं, यह नीति, प्रशासन और नागरिक चेतना की सामूहिक असफलता है।

भारत में पानी की स्थिति को अगर आंकड़ों की भाषा में समझें, तो भयावहता साफ़ दिखाई देती है। नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा भूजल उपभोक्ता है — लगभग 25 प्रतिशत भूजल अकेले भारत निकालता है। 11 प्रति. से अधिक भूजल खंड 'अत्यधिक दोहित' यानी **over-e&ploited** की स्थिति में हैं। दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद जैसे 21 प्रमुख शहरों के 2030 तक भूजल समाप्त होने की चेतावनी दी जा चुकी है। वहीं दूसरी ओर, 70 प्रति. जल स्त्रोत प्रदूषित हैं। फ्लोराइड, आर्सेनिक, नाइट्रेट और भारी धातुओं से दूषित यह जल 23 करोड़ से अधिक लोगों को प्रभावित कर रहा है। हर साल लगभग 2 लाख मौतें सिर्फ जलजनित बीमारियों से होती हैं — यह सिर्फ आंकड़ा नहीं, यह हमारी संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है।

पानी का यह संकट केवल ग्रामीण इलाकों या गरीबों तक सीमित नहीं है। 2019 में जब चेन्नई जैसे आधुनिक शहर को '□□□ □□□' का सामना करना पड़ा और जल ट्रेनें चलानी पड़ीं, तब यह साफ हो गया कि यह समस्या अब दरवाज़े पर नहीं, घर के भीतर आ चुकी है। और फिर भी हम इसे मौसमी समस्या मानकर हर बार भूल जाते हैं।

सवाल यह है कि नीतियाँ तो बनीं — राष्ट्रीय जल नीति (2012), जल जीवन मिशन, अटल भूजल योजना, नमामि गंगे, जल शक्ति अभियान — पर फिर भी पानी का स्तर क्यों गिरता जा रहा है? जवाब सरल है — हमारी नीतियाँ ज़मीन पर नहीं उतरतीं, और हमारे व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आता।

आज भी देश के अधिकांश किसान पानी की फिजूलखर्ची करने वाली फसलों की खेती करते हैं। पंजाब और हरियाणा जैसे जल–संकटग्रस्त राज्य में धान और गन्ने की खेती केवल इसलिए होती है क्योंकि सरकार MSP और मुफ्त बिजली देती है। नतीजा — भूजल का तेज़ी से दोहन, खेतों का क्षरण, और जल स्त्रोतों का खत्म हो जाना। दूसरी ओर, ड्रिप सिंचाई या स्प्रिंकलर जैसे आधुनिक जल संरक्षण उपायों की पहुंच केवल 9 प्रति. खेतों तक ही सीमित है। किसान जानते हैं, पर अपनाते नहीं — क्योंकि नीति और व्यवहार में दूरी है।

शहरों की बात करें तो पाइपलाइन से लेकर टंकी तक, हर जगह लीकेज और बर्बादी का आलम है। स्मार्ट मीटरिंग अभी भी अधिकांश नगरपालिकाओं के लिए नया शब्द है। पुन: उपयोग (रीसाइकिलिंग) और वर्षा जल संचयन (रेन वाटर हार्वेस्टिंग) जैसे उपाय कहीं–कहीं दिखते हैं, लेकिन सामूहिक रूप से अपनाए नहीं जाते।

सबसे चिंताजनक बात यह है कि जल संकट को अब भी केवल 'प्राकृतिक समस्या' समझा जाता है। जबकि यह एक स्पष्ट रूप से 'नीतिगत और नैतिक' संकट है। जब तक यह दृष्टिकोण नहीं बदलेगा, तब तक कोई भी योजना सफल नहीं होगी।

अब समय आ गया है कि भारत पानी को 'मुफ्त संसाधन' मानना बंद करे और उसे 'जीवन मूल्य' की तरह देखे। इसके लिए कुछ गहन और ठोस सुधारों की आवश्यकता है। सबसे पहले, पानी की कीमत तय होनी चाहिए — चाहे वह पीने का हो, या सिंचाई का। मुफ्त पानी की संस्कृति ने उपभोग को बर्बादी में बदल दिया है। जल का मूल्य निर्धारण सामाजिक न्याय और पर्यावरणीय विवेक के बीच संतुलन साध सकता है।

दूसरा, सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों को केवल योजना पत्रों से निकालकर ज़मीनी हकीकत बनाना होगा। इसके लिए तकनीकी प्रशिक्षण, सस्ती उपलब्धता, और स्थानीय स्तर पर सहायता तंत्र बनाना होगा। तीसरा, भूजल का प्रबंधन केवल सरकार का नहीं, ग्राम पंचायतों और स्थानीय समुदायों का भी कर्तव्य होना चाहिए। अटल भूजल योजना को इस दिशा में सफल मॉडल के रूप में बढ़ाया जा सकता है।

चौथा, किसानों को केवल फसल बीमा या सब्सिडी नहीं, जल आधारित फसल मार्गदर्शन की ज़रूरत है। यह तभी होगा जब MSP का ढांचा जल संरक्षण के अनुकूल फसलों को बढ़ावा देगा। देश को ऐसे नीतिगत हस्तक्षेपों की ज़रूरत है जो किसान की आय भी बढ़ाएं और पानी की बचत भी करें।

पाँचवां, शहरों में जल पुनर्चक्रण अनिवार्य किया जाए। जो नगर पालिकाएं wastewater recycle नहीं करतीं, उन्हें दंड और प्रोत्साहन दोनों के माध्यम से बदला जाए। बड़े भवनों में वर्षा जल संचयन अनिवार्य हो, और इसके अनुपालन की निगरानी की जाए।

छठा, बच्चों के स्कूली पाठ्यक्रम में जल संरक्षण को केवल पर्यावरण अध्याय के रूप में न पढ़ाया जाए, बल्कि व्यवहार परिवर्तन के रूप में सिखाया जाए। यदि अगली पीढ़ी जल को 'कीमती' माने, तो आज की प्यास भविष्य की सूखी धरती को बचा सकती है।

सातवां, जल संरक्षण को 'जन आंदोलन' बनाना होगा — जैसा प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था। लेकिन यह आह्वान केवल भाषणों में नहीं, बजट और प्रशासनिक प्रतिबद्धता में दिखना चाहिए। जल शक्ति मंत्रालय को केवल नल जोड़ने वाला मंत्रालय नहीं, जल नीति, जल शिक्षा और जल चेतना का नेतृत्व करना होगा।

साथ ही, निजी क्षेत्र की भूमिका को भी समझना और बढ़ाना होगा। जल एटीएम, पाइपलाइन प्रबंधन, स्मार्ट मीटरिंग, और जल पुनर्चक्रण जैसी सेवाओं में PPP मॉडल को बढ़ावा देकर न केवल निवेश लाया जा सकता है, बल्कि तकनीकी नवाचार भी हो सकते हैं।

और सबसे महत्वपूर्ण — हमें यह समझना होगा कि जल संकट केवल वैज्ञानिकों और नौकरशाहों का विषय नहीं है। यह आम नागरिक का संकट है। हर घर, हर हाथ को यह जिम्मेदारी लेनी होगी कि पानी को बर्बाद नहीं किया जाएगा, और हर बूंद का सम्मान होगा।

जलवायु परिवर्तन के इस युग में, जब बारिश की मात्रा अनिश्चित हो गई है, और हिमालयी ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं — हमें जल को 'अनंत' नहीं, बल्कि 'सीमित और नाजुक' संसाधन मानना होगा। भारत की सांस्कृतिक परंपरा में जल को देवता का दर्जा मिला है — लेकिन विडंबना यह है कि आज वही जल नदियों में मल–मूत्र के रूप में बह रहा है, या गंदे नालों से होकर भूजल में जहर घोल रहा है। इसलिए आज का भारत केवल 'जल संकट' नहीं झेल रहा, बल्कि वह अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। जल संकट में डूबा भारत, विकास के हर मोर्चे पर कमजोर पड़ता जाएगा — चाहे वह स्वास्थ्य हो, कृषि, उद्योग या सामाजिक समरसता। अंततः यही कहा जा सकता है कि जल संकट केवल पानी की समस्या नहीं है — यह व्यवस्था, संस्कृति, शिक्षा और नीयत की भी परीक्षा है। यदि हमने अब भी नहीं संभला, तो इतिहास गवाह रहेगा कि हमने एक ऐसे संसाधन को खो दिया, जो जीवन का मूल था, और जिसकी एक–एक बूंद सोने से भी महंगी थी। अब वक्त आ गया है — नीतियों की बौछार से बाहर निकलकर बूंद-बूंद बचाने के व्यवहारिक आंदोलन को अपनाने का। क्योंकि आने वाले वर्षों में 'जल' ही 'राजनीति', 'आर्थिक ताकत' और 'सामाजिक न्याय' का सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला है।

अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस पर विशेष

भयानक तबाही मचा सकते हैं कुछ क्षुद्रग्रह

योगेश कुमार गोयल
लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

प्रतिवर्ष 30 जून को रूस के साइबेरिया में तुंगुस्का नदी के पास वर्ष 1908 में हुई क्षुद्रग्रह (एस्टेरायड) घटना की वर्षगांठ के प्रतीक के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसम्बर 2016 में 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस के रूप में घोषित किया था। इसी दिन साइबेरिया और उसके आसपास हुए तुंगुस्का क्षुद्रग्रह के प्रभाव को समझने के लिए ही इस तिथि का चयन किया गया था। इस दिन को चिह्नित करने का विचार एसोसिएशन ऑफ स्पेस एक्सप्लोरर्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिसे बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर समिति द्वारा समर्थन दिया गया था। दरअसल 30 जून 1908 को तुंगुस्का नदी के करीब एक बड़ा विस्फोट हुआ था, जिसे तुंगुस्का प्रभाव कहा गया। उस विस्फोट में कई किलोमीटर क्षेत्र में जमीन तहस-नहस हो गई थी। क्षुद्रग्रह के चलते पृथ्वी पर हुआ वह नुकसान अभी तक का सबसे बड़ा नुकसान बताया जाता है। यह दिवस मनाने का प्रमुख उद्देश्य लोगों को उस संकट के बारे में जागरूक करना है, जो क्षुद्रग्रह के प्रभाव से ब्रह्मांड पर हो सकता है। इस दिवस के माध्यम से क्षुद्रग्रह के प्रभाव के चलते होने वाले खतरनाक प्रभावों के बारे में जागरुकता फैलाने के लिए एक वैश्विक आंदोलन छेड़ा गया है।

क्षुद्रग्रह दिवस का लक्ष्य क्षुद्रग्रहों और पृथ्वी पर उनके संभावित प्रभाव के बारे में सार्वजनिक जागरूकता को बढ़ावा देने के अलावा सरकारों, संगठनों और व्यक्तियों को हमारे ग्रह को भविष्य के क्षुद्रग्रह प्रभावों से बचाने के लिए कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित करना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 30 जून को क्षुद्रग्रह दिवस के रूप में घोषित करने के लिए लाए गए संकल्प में तय किया था कि दुनियाभर में लोगों को क्षुद्रग्रहों के घातक प्रभावों के बारे में जागरुक किया जाएगा। दरअसल आज भी विश्व में अधिकांश लोगों को यह जानकारी नहीं है कि आखिर ये क्षुद्रग्रह हैं क्या और किसी क्षुद्रग्रह की घटना पृथ्वी पर कितना विनाश कर सकती है? हमारे ब्रह्मांड के निर्माण में क्षुद्रग्रहों की क्या भूमिका है, भविष्य में उनके संसाधनों का उपयोग कैसे किया जा सकता है, क्षुद्रग्रह भविष्य की खोज के लिए कैसे मार्ग प्रदान करते हैं और हम अपने ग्रह को क्षुद्रग्रहों के प्रभाव से कैसे बचा सकते हैं, यह दिवस इन्हीं सब बातों को जानने-समझने तथा किसी क्षुद्रग्रह के पृथ्वी से टकराने पर होने वाले विनाशकारी प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है।

अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस 1908 के तुंगुस्का प्रभाव की वर्षगांठ का प्रतीक है। 30 जून 1908 को रूस के साइबेरिया में पॉडकामेनेया तुंगुस्का नदी के ऊपर आसमान में एक बड़ा विस्फोट हुआ था। नासा के अनुसार अनुमान लगाया गया था कि उस क्षुद्रग्रह ने करीब 33500 मील प्रति घंटे की गति से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया था। 220 मिलियन पाउंड की उस अंतरिक्ष चट्टान ने अपने आसपास की हवा को 44500 डिग्री फॉरेनहाइट तक गर्म कर दिया था। करीब 28 हजार फीट की ऊंचाई पर दबाव और गर्मी के संयोजन ने क्षुद्रग्रह के टुकड़े को नष्ट कर दिया था, जिससे आग का गोला पैदा हुआ और उससे करीब 185 हिरोशिमा बमों के बराबर ऊर्जा निकली। उस भयंकर विस्फोट से पैदा गई आग ने जंगल के करीब 2150 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में 80 मिलियन से भी ज्यादा पेड़ों को जलाकर राख कर दिया था। माना गया था कि उस विस्फोट के लिए कोई क्षुद्रग्रह या धूमकेतु जिम्मेदार था। क्षुद्रग्रह दिवस की स्थापना 2013 के चेल्याबिंस्क उल्का विस्फोट के अगले वर्ष 2014 में भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग ने खगोलशास्त्री और क्रीन के प्रमुख गिटारवादक डा. ब्रायन मे, बी612 फाउंडेशन के अध्यक्ष डेनिका रेमी, अपोलो 9 अंतरिक्ष यात्री रस्टी श्वेकार्ट और फिल्म निर्माता ग्रिग रिक्टर्स के साथ मिलकर जागरूकता को बढ़ावा देने और लोगों को हमारे ब्रह्मांड के निर्माण में क्षुद्रग्रहों के महत्व तथा हमारे सौरमंडल में उनकी भूमिका के बारे में ज्ञान प्रदान करने के उद्देश्य से की थी। बी612 नामक संगठन एक ऐसा संगठन है, जो पृथ्वी को क्षुद्रग्रह प्रभावों से बचाने और ग्रह रक्षा के मुद्दों पर विश्वभर में निर्णय लेने की जानकारी देने और अग्रेषित करने की दिशा में कार्य करता है।

क्षुद्रग्रह छोटे आकाशीय चट्टान रूपी पिंड होते हैं, जो सदैव सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। ये वो पिंड हैं, जो किसी कारण से ग्रह नहीं बन पाए। क्षुद्र ग्रह को ग्रहिका भी कहते है। ये आकाशीय पिंड किसी ग्रह से छोटे होते हैं लेकिन ग्रहों की ही भांति सूर्य की परिक्रमा करते हैं। दरअसल तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अलावा कई छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं, इन्हीं पिंडों को क्षुद्रग्रह कहा जाता है। अंतरिक्ष विज्ञानियों के मुताबिक क्षुद्र ग्रह एक ग्रह के हिस्से हैं, जो हजारों साल पहले टूटे थे। क्षुद्रग्रह चट्टानी-धात्विक वस्तुएं हैं, जिनका आकार एक छोटे से कंकड़ के आकार से लेकर 600 मील तक भी होता है। इन्हें सौरमंडल का बचा हुआ पदार्थ भी कहा जाता है। हमारे सौरमंडल में कई लाख क्षुद्रग्रह मौजूद हैं और कई की खोज अभी बाकी है। कुछ क्षुद्रग्रह तो इतने छोटे होते हैं कि उनका पता लगाना मुश्किल होता है। ज्यादातर क्षुद्रग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं लेकिन कुछ की कक्षाएं अधिक विलक्षण होती हैं।

करीब 10 लाख ज्ञात क्षुद्रग्रहों में से सबसे बड़ी संख्या मुख्य क्षुद्रग्रह बेल्ट में सूर्य से करीब 2 से 4 खगोलीय इकाई दूर मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच स्थित है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरेस है, जिसका व्यास करीब 1083 किलोमीटर है, जिसकी खोज 1801 में हुई थी। दरअसल उस दौरान तारों का नक्शा बनाते समय इटली के खगोल शास्त्री ग्यूसेप पियाजी ने गलती से मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच एक हजार किलोमीटर (करीब 600 मील) व्यास की एक वस्तु की खोज की थी। उन्होंने उस वस्तु का नाम अनाज और फसल की रोमन देवी के नाम पर 'सेरेस' रखा, जो खोजा जाने वाला पहला क्षुद्रग्रह था। यह मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्रग्रहों के पट्टे में रहता है। प्लूटो क्षुद्रग्रह सेरेस से करीब ढ़ाई गुना बड़ा है।

अंतरिक्ष विज्ञानियों का मानना है कि सेरेस शुष्क और धूसर दिखाई दे सकता है लेकिन संभवत: इसके अतीत में एक तरल महासागर था। ज्यादातर क्षुद्रग्रह पृथ्वी और उस पर पनप रहे जीवन के लिए खतरा नहीं हैं लेकिन कुछ क्षुद्रग्रह इतने खतरनाक हैं और अगर वे पृथ्वी से टकरा जाते हैं तो भयानक तबाही मचा सकते हैं।

साप्ताहिक बाजार में कम नहीं दुकानदारी, तापमान में आई कमी

बैतूल। रविवार सुबह शुरू हुआ बारिश का दौर रुक-रुककर दिनभर चलता रहा। इससे तापमान कम हुआ है और मौसम ठंडा होने से सभी को राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। बीते चौबीस घंटे यानि 28 जून से 29 जून सुबह 8 बजे तक जिले में महज 1.5 मिमी बारिश दर्ज की गई है। जबकि अभी तक 126.7 मिमी बारिश हो चुकी हैं। हालांकि पिछले साल से इस बारिश साल की बारिश का आंकड़ा बढ़ा है। पिछले साल 29 जून तक जिले में 124.4 मिमी बारिश दर्ज की गई थी। जिले में अभी तक तेज बारिश का दौर शुरू नहीं हो सका है। रूक-रूककर बारिश हो रही हैं। जिससे बारिश का आंकड़ा तेजी से नहीं बढ़ पा रहा है। हालांकि रविवार को बैतूल में दिन भर रूक-रूककर कभी तेज तो कहीं रिमझिम बारिश होते रही। बताया गया कि जिले में वर्षाकाल के दौरान अभी तक सर्वाधिक बारिश शाहपुर ब्लाक में हुई है। यहां अब तक 171.0 मिमी बारिश दर्ज की जा चुकी है, वहीं दूसरे नंबर पर प्रभातपट्टन में 169.8 मिमी और सबसे कम बारिश बैतूल में 52.0 मिमी दर्ज की है। इसके अलावा अन्य ब्लॉकों में बारिश का आंकड़ा 100 मिमी से ऊपर है।

जिले में 82 फीसदी बुआई का काम पूरा- अच्छी बारिश से किसानों ने बोवनी का काम तेज कर दिया है। कई किसान 8 जून के बाद बुआई चालू कर दी थी, ऐसे में इन किसानों की फसल करीब 18 से 20 दिनों की हो चुकी है। बीज अंकुरित होकर खेत लहलहाने लगे है। वही जिन किसानों ने बुआई नहीं की थी, वह किसान भी बुवाई में जुट गये है। शनिवार को मौसम खुले रहने से अधिकांश किसानों ने बुआई का काम निपटा लिया है। वैसे जिले में जिले में 16 जून से मानसून एक्टिव हुआ है। जिसके बाद किसानों ने बुआई कार्य शुरू कर दिया था। किसानों के अनुसान रिमझिम बारिश फसलों के लिए फायदेमंद बताई जाती है। कृषि विभाग के अनुसार इस साल जिले में 4 लाख 43 हजार हेक्टेयर में खरीफ फसल की बुआई का रकबा तय किया है।

अधिकतम तापमान 28 डिग्री किया दर्ज- जिले में हो रही लगातार बारिश से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। रविवार जिले का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 21.0 डिग्री था। बारिश के कारण अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कमी आने से सभी को उमस से राहत मिली है। मौसम विभाग की मानें तो अगले दो दिन बारिश होने की संभावना है। इससे जून में बारिश का सूखा पूरा हो जाएगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले दो-तीन दिन बारिश होगी। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, इस बार मानसून की शुरुआत हल्की बारिश के साथ हुई है। आने वाले दिनों में मानसून की गति बढने की संभावना है।

साप्ताहिक बाजार पर पड़ा असर- रविवार सुबह से बारिश का दौर जारी रहा। जिसका असर साप्ताहिक बाजार पर देखा गया। बारिश के साप्ताहिक बाजार में दुकानदार और ग्राहक कम नजर आये। कोठी बाजार के साप्ताहिक बाजार में दोपहर 12 बजे तक बहुत कम दुकानें लगी हुई थी। वहीं ग्राहक भी कम थे। जिले के आसपास क्षेत्र से सब्जियां कम आने से सब्जियों के दाम भी बढ़ गये। रविवार साप्ताहिक बाजार में टमाटर 40 रूपये किलो तक बिके। इसके अलावा आलू 30 रूपये प्रति किलो थी। अन्य सब्जियों के दाम भी 15 से 20 रूपये किलो तक रहे। बारिश के कारण बाजार में दुकानदार तिरपाल लगाकर दुकाने संचालित करते देखे गये।

सतपुड़ा डैम के खुले तीन गेट

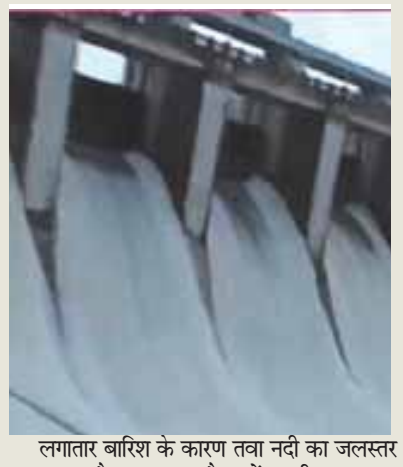

लगातार बारिश के कारण तवा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। सतपुड़ा डैम में पानी का स्तर 1429.50 फीट तक पहुंचने पर तीन गेट खोलने पड़े। रविवार सुबह तक एक ही गेट खुला था, लेकिन बाद में तीन गेट खोलकर अतिरिक्त पानी छोड़ा गया। इससे तवा नदी के निचले इलाकों में जलस्तर में वृद्धि हुई है। घोड़ाडोंगरी क्षेत्र में अब तक 158 इंच बारिश दर्ज की गई है, जिससे जल स्रोतों और बांधों के भरने की उम्मीद बढ़ गई है।

जिले के ब्लाकों में अब तक दर्ज बारिश

ब्लाक	बारिश (मिमी में)
बैतूल	52.0
घोड़ाडोंगरी	158.0
चिचोली	139.2
शाहपुर	171.0
मुलताई	115.1
पट्टन	169.8
आमला	118.0
भैंसदेही	106.0
आठनेर	109.6
भीमपुर	132.0
कुल	126.7

ब्रम्हांड से जोड़ दिया बैतूल का इतिहास सराहनीय : हेमन्त खण्डेलवाल

मैं बैतूल हूँ कि मंच पर दी गई जीवंत प्रस्तुति, राजा जैतपाल, तात्याटोपे, से लेकर राजा ईल की कहानी से रूबरू हुए दर्शक

बैतूल। जिले के 200 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जिले के इतिहास की परिकल्पना युवाओं के सहयोग से मंच पर नजर आई। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा मैं बैतूल हूं... का मंचन बैतूल के उत्कृष्ट कलाकारों ने जीवंत कर दिखाया। कार्यक्रम में बतौर अतिथि बैतूल विधायक एवं कार्यक्रम के संरक्षक हेमन्त खण्डेलवाल, नपा अध्यक्ष पार्वती बाई बारस्कर, भाजपा जिला अध्यक्ष सुधाकर पवार समेत बडी संख्या में दर्शक गण शामिल हुए। इस अवसर पर युवा वर्ग द्वारा किये गए इस प्रयास की विधायक हेमन्त खण्डेलवाल ने खुलकर सराहना कर उनका उत्साह बढ़ाया। उन्होंने कहा कि, मैं बैतूल हूं के शीर्षक को कलाकारों ने जीवंत कर दिखाया। जिस तरह ब्रम्हांड से बैतूल का इतिहास जोड़ा गया, यह प्रयास काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा कि यह तो एक छोटा सा प्रयास है। कोशिश की जाए तो यह कार्यक्रम बडे रूप में आयोजित किया जा सकता है। जिसमें हजारों की संख्या में जिलेवासी शामिल होकर जिले के इतिहास से रूबरू हो सकते हैं।

राजा जैतपाल से लेकर राजा ईल और स्वतंत्रता सैनानी मंच पर आए नजर

दरअसल मैं बैतूल हूं .. के मंचन की पटकथा और मंचन उत्कृष्ट कलाकार शिरीष ध्वनि और सूर्यदीप त्रिवेदी द्वारा तैयार की गई थी। ग्रुप में शामिल कलाकारों ने राजा जैतपाल से लेकर खण्डारा रियासत के राजा ईल, तात्या टोपे का अभिनय साकार किया। खास बात ये है कि,नाटक के मंचन में अंग्रेजों का शाषन काल तक शामिल किया गया था। अंग्रेजो ने जिस तरह जिले में अपनी आमद दी और देश को आजादी दिलाने में जिले के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की भूमिका क्या रही इसे कलाकारों ने अपने अभिनय के रूप में जब प्रस्तुत किया तो हॉल तालियों की गडगडाहट से गूंज उठा। कार्यक्रम में आदिवासी नृत्यों की बेहतरीन झलक भी नजर आई। आदिवासी समुदाय के युवाओ ने कोरकू और गोंधळ नृत्य की प्रस्तुति देकर जमकर तालियां बटोरी, विधायक हेमन्त खण्डेलवाल ने सभी कलाकारों को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका उत्साह वर्धन किया। कार्यक्रम के अंत में कार्यक्रम के सूत्रधार आदर्श सोनकपुरिया एवं संकल्प सिंह चौहान ने अतिथियों समेत सभी दर्शकों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन सताक्षी गौर द्वारा किया गया।

कुनबी समाज के विकास के लिए हर स्तर पर करेंगे सहयोग : हेमंत खंडेलवाल

शिवाजी परिसर गौठाना में मंगल भवन निर्माण का हुआ शुभारंभ

बैतूल। क्षत्रिय लोनारी कुनबी समाज सेवा संगठन जिला बैतूल द्वारा शिवाजी परिसर गौठाना में रविवार 29 जून को मंगल भवन निर्माण हेतु भूमिपूजन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डी.डी. उइके रहे, जबकि विशिष्ट अतिथियों में बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल, नगर पालिका परिषद बैतूल की अध्यक्ष श्रीमती पार्वती बाई बारस्कर, समाजसेवी डॉ. एन.आर. मानकर, वसंत वागद्रे, दिनेश माथनकर, संगठन के जिलाध्यक्ष यशवंत (मुन्ना) मानकर सहित समस्त जिला कार्यकारिणी उपस्थित रही। मंगल भवन के लिए क्रय की गई भूमि में सहयोग देने वाले प्रमुख समाजसेवियों का संगठन द्वारा पुष्पमालाओं और श्रीफल से सम्मान किया गया। इनमें डॉ. एन.आर. मानकर, वसंत वागद्रे, दिनेश माथनकर, पंकज साबले और जिलाध्यक्ष यशवंत मुन्ना मानकर का विशेष उल्लेखनीय योगदान रहा। इस भूमि की क्रय प्रक्रिया संगठन के पूर्व अध्यक्ष मनोज धोटे के नेतृत्व में पूरी की गई थी, जिनका भी मंच पर अभिनंदन किया गया। विधायक हेमंत खंडेलवाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि क्षत्रिय लोनारी कुनबी समाज एक संगठित और प्रेरणादायक समाज है, जो लगातार सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में सक्रिय रहता है। उन्होंने कहा कि समाज द्वारा मंगल भवन का निर्माण किया जाना एक दूरदर्शी पहल है, जो आने वाली पीढ़ियों को एकजुटता, सहयोग और सुसंस्कारों का संदेश देगा। उन्होंने आश्वस्त किया कि समाज के विकास के लिए वे हर स्तर पर सहयोग के लिए तैयार हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि मंगल भवन सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन का केंद्र बनेगा, यह नई पीढ़ी के लिए एक प्रेरणास्रोत और मार्गदर्शन स्थल की भूमिका निभाएगा। विधायक ने कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए समाजजनों से आग्रह किया कि वे एकजुट होकर शिक्षा, स्वास्थ्य, और रोजगार के क्षेत्र में आगे आएं। इस अवसर पर अभिभाषक संघ के चुनाव में सफलता प्राप्त करने वाले रोशन मागरदे और गौरव मागरदे को संगठन द्वारा प्रतीक चिह्न भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के उपरांत संगठन की कार्यकारिणी बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जिले भर में बड़े स्तर पर सदस्यता अभियान चलाया जाएगा, ताकि समाज को और अधिक संगठित व प्रभावशाली बनाया जा सके। कार्यक्रम का संचालन संयोजक डॉ. उज्ज्वल पांसे एवं मनोज धोटे ने किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से डॉ. उज्ज्वल पांसे, मीडिया प्रभारी पंकज धोटे, हरीश चढोकार, राजेश बारस्कर एवं संगठन की समस्त कार्यकारिणी के सदस्य मौजूद रहे।

यूपी में कथा वाचक के साथ अमानवीय घटना के विरोध में यादव समाज ने सौंपा ज्ञापन

बैतूल। इटावा जिले के बकेबर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम दादरपुर में विगत 22 जून को श्रीमद्भागवत कथा वाचक मुकुटमणि यादव और उनके साथियों के साथ हुई अमानवीय, जातिगत और बर्बर घटना से आक्रोशित यादव समाज ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। घटना के विरोध में अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा मध्यप्रदेश के बैनर तले समस्त यादव समाज के नेतृत्व में प्रधानमंत्री के नाम जिला प्रशासन को सामूहिक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि स्वतंत्र भारत में जातिवाद की संकीर्ण सोच अब भी समाज के ताने-बाने को छिन्न-भिन्न कर रही है। दादरपुर में कथा वाचक मुकुटमणि यादव और उनके सहयोगियों के साथ सरेआम मारपीट की गई, जबरन बाल काटे गए, मुंडन कर नाक रगड़वाया गया। यादव समाज का कहना है कि इस कृत्य का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करना शर्मनाक है। संतोष यादव ने कहा कि इस घटना से पूरे देश का यादव समाज आहत है। उन्होंने कहा कि इस मामले में दोषियों पर कठोरतम कानूनी कार्यवाही की जाए ताकि भविष्य में कोई जातिगत जहर घोलने की हिम्मत न कर सके। अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा ने मांग की कि इस कांड को सामूहिक सामाजिक अपराध माना जाए और दोषियों पर राष्ट्रीय एकता भंग करने, जातीय विद्वेष फैलाने, सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाने जैसी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए। इस मौके पर बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित रहे और एकजुटता का प्रदर्शन किया। समाजजनों ने जिला प्रशासन से तत्काल प्रभाव से इस मामले को प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचाने की मांग की। यादव समाज ने चेताया कि यदि समय रहते दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती तो आंदोलनात्मक कदम उठाए जाएंगे। ज्ञापन सौंपने वालों में जिला अध्यक्ष संतोष यादव सहित बड़ी संख्या में यादव समाज के लोग उपस्थित रहे। सभी ने इस जातिगत हमले की घोर निंदा करते हुए सरकार से न्याय की मांग की।

भौरा बायपास पर ब्रिज के पास मिट्टी का कटाव बना खतरा

नेशनल हाईवे की रोड पर कभी भी हो सकती है बड़ी दुर्घटना

बैतूल/भौरा। भौरा से होकर निकली नेशनल हाईवे-46 की बायपास रोड पर खतरा गहराता जा रहा है। लगभग 20 फीट गहराई में बनाई गई इस रोड के साइड की जमीन पर तेज कटाव हो रहा है, जो सीधे हाईवे पर मिट्टी गिरने का कारण बन रहा है। खासकर भौरा-बीजादेही मार्ग पर बने ब्रिज के पास की जमीन पर हालात बेहद गंभीर हो चुके हैं। यदि समय रहते जरूरी कदम नहीं उठाए गए, तो कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। यह मार्ग नेशनल हाईवे का हिस्सा होने के कारण यहां वाहनों की रफ्तार आमतौर पर तेज रहती है। यदि ऊपर से मिट्टी का कटाव अचानक हाईवे पर गिरा, तो वाहन फिसलने या टकराने जैसी गंभीर दुर्घटनाएं हो सकती हैं। यह खतरा खासतौर पर बारिश के समय कई गुना बढ़ सकता है। जानकारी के अनुसार भौरा बायपास निर्माण के दौरान एनएचएआई ने रोड बनाने के लिए लगभग 20 फीट गहराई तक खुदाई की थी। इसके बाद साइड की जमीन को स्थिर करने के लिए कोई स्थायी संरचना या रिटेनिंग वॉल नहीं बनाई गई, जिससे अब यह जमीन कटाव की चपेट में है। मिट्टी का यह कटाव लगातार नीचे बनी रोड पर गिर रहा है। भौरा-बीजादेही रोड पर बने ब्रिज के साइड में स्थित शराब दुकान के पास की जमीन में कटाव सबसे अधिक देखने को मिल रहा है। बाईपास हाईवे पर स्थित शराब दुकान के बगल वाली भूमि के भू-स्वामी मोहन मालवीय ने बताया कि वे कई बार इस समस्या को लेकर एनएचएआई अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। बारिश के समय मिट्टी तेजी से धंसती है। यदि ऊपर से मिट्टी रोड पर अचानक गिरी, तो कई लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है।

एनएचएआई की चुप्पी पर उठे सवाल

स्थानीयों ने सवाल उठाया है कि बार-बार शिकायत के बावजूद भी एनएचएआई ने अब तक कोई कदम क्यों नहीं उठाया? क्या किसी बड़ी दुर्घटना के बाद ही अधिकारियों की नींद खुलेगी? भौरा बायपास पर मिट्टी का यह कटाव अब महज भू-क्षरण नहीं, बल्कि जानलेवा खतरा बन सकता है। हाईवे पर तेज रफ्तार से गुजरते वाहनों के लिए यह एक अनदेखा खतरा है, जो किसी भी दिन बड़ी दुर्घटना में बदल सकता है। समय रहते कदम उठाना अब सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, बल्कि अनिवार्यता बन गया है।

इनका कहना है-

आप जगह की फोटो भेजिए, मैं आज ही अधिकारियों को भेजकर निरीक्षण कराता हूं। यदि यह स्थान मेरे कार्यक्षेत्र में आता है, तो आवश्यक कार्यवाही तत्काल शुरू की जाएगी। सडक़ की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है।

- मनीष कुमार मीणा, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, एनएचएआई

संक्षिप्त समाचार

खाद्य सुरक्षा विभाग ने खाद्य पदार्थों के लिए सैंपल

बैतूल (निप्र)। कलेक्टर श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा जिले में खाद्य पदार्थों का विक्रय करने वाले प्रतिष्ठानों की जांच एवं नमूने लिए जाने की कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा प्रशासन श्री शैलेंद्र बड़ोनिया के मार्गदर्शन में 26 जून को खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीमती मीना कुमरे द्वारा आठनेर तहसील नयन साख समिति मिल्क चिलिग सेंटर, नव्या डेली नीड्स, दिव्यांशु रेस्टोरेंट, वैष्णवी भोजनालय का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थों में उपयोग होने वाले खाद्य तेल खाद्य नमक, पनीर, माजा फ्रूटी ड्रिंक, नींबू मसाला ड्रिंक, कार्बोनेटेड बेवरेज चार्जड, तीन मिश्रित दूध के नमूने लिए गए। लिए गए सैंपल राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला एवं केली लैब भोपाल भेजे जाएंगे। जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की जाएगी।

अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस पर जिला स्तरीय पुरूस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ

विदिशा (निप्र)। अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस के अवसर पर आज कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता के मुख्य आतिथ्य में शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय विदिशा में जिला स्तरीय पुरूस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एक जून से 26 जून 2025 तक नशा निवारण कार्यक्रम के तहत विभिन्न शासकीय महा विद्यालय, विद्यालय, संस्था द्वारा नशामुक्त भारत अभियान अंतर्गत निबंध, प्रश्नोत्तरी, पोस्टर, चित्रकला, मिनी मैराथन आदि प्रतियोगिताएं आयोजित कराई गई थी। जिसमें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विजेताओं को पुरुस्कार वितरित किये गये। उपस्थित अतिथियों द्वारा नशे से होने वाले दुष्प्रभो के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही नशा से होने वाले नुकशान की प्रदर्शिनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता, एस एटी आई कॉलेज के डायरेक्टर श्री वायके जैन, जिला पंचायत के अतिरिक्त सीईओ श्री पंकज जैन, जिला खेल अधिकारी श्री प्रदीप सिंह रावत, प्राचार्य श्री के सिंह, मनो चिकित्सक डॉ. जगमोहन प्रजापति, ईश्वरी प्रजापति ब्रह्मकुमारी सपना दीदी, अध्यक्ष अजंता ललित कला समाज कल्याण समिति श्रीमति इंदिरा शर्मा, एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारी, कर्मचारी मौजूद रहे।

कलेक्टर ने अस्पताल से छुट्टी करने से पहले बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनाने के संबंधितों को दिए निर्देश

सीहोर (निप्र)। कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने आमजन की सुविधा और जन्म प्रमाण पत्र के बढ़ते महत्व को दृष्टिगत रखते हुए जिले के सिविल सर्जन तथा प्रभारी चिकित्सा एवं रजिस्ट्रार को निर्देश दिए हैं कि अस्पताल से माता को छुट्टी देने से पहले बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जाए। जन्म प्रमाण पत्र समय सीमा के भीतर जारी नहीं होने के कारण आमजन को अत्यधिक असुविधा का सामना करना पड़ता है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सभी प्रभारी चिकित्सा एवं रजिस्ट्रार अस्पताल से माता को छुट्टी देने से पहले नवजात शिशु का जन्म प्रमाण पत्र जारी करें और बच्चे की माता को प्रदान करें।

कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने पड़रियाकला पहुंचकर प्रभावितों को दी सांत्वना

रायसेन (निप्र)। कलेक्टर श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा गुरूवार को सिलवानी तहसील के ग्राम पडरियाकला पहुंचे तथा गत दिवस हुई विद्युत दुर्घटना के प्रभावितों से मिलकर उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि शासन द्वारा हर संभव सहायता की जाएगी। कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने उपस्थित अधिकारियों से भी दुर्घटना के बारे में विस्तृत जानकारी ली।

जिला पंचायत सीईओ ने किया अश्वगंधा से औषधी निर्माण की प्रक्रिया अवलोकन

सीहोर (निप्र)। जिला पंचायत सीईओ डॉ नेहा जैन सीहोर स्थित आईटीसी चौपाल पहुंचकर अश्वगंधा एवं अन्य औषधीय पौधों से बनाई जाने वाली औषधीय सामग्रियों की निर्माण प्रक्रिया का अवलोकन किया। उन्होंने आईटीसी के विशेषज्ञों से औषधीय सामग्रियों के निर्माण और विक्रय प्रक्रिया के संबंध में विस्तार से चर्चा की। ताकि जिले में अन्य फसलों के साथ-साथ अश्वगंधा की खेती को प्रोत्साहित किया जा सके। उन्होंने कहा कि अश्वगंधा की खेती से किसान अच्छा मुनाफा अर्जित कर सकते हैं। जिला पंचायत सीईओ डॉ नेहा जैन ने ग्राम कुलांस कला पहुंचकर किसान श्री गजराज वर्मा द्वारा स्थापित मसाला एवं दाल यूनिट का भी अवलोकन किया और मसालों तथा दालों की प्रोसेसिंग प्रक्रिया में बारे में विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने कुलांस कला में कुलांस नदी के उद्गम स्थल का भी निरीक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने ग्राम पिपलिया मीरा में पीएचई विभाग द्वारा बनाई गई पानी की टंकी से की जाने वाली जल प्रदाय प्रक्रिया का निरीक्षण किया और संबंधितों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जनपद सीईओ श्रीमती नमिता बघेल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

रोजगार, स्वरोजगार एवं अप्रेन्टिसशिप मेला (युवा संगम) तथा जिला स्तरीय इण्डस्ट्री स्किल एण्ड एम्प्लॉयमेंट कॉनक्लेव का आयोजन

जिले में 435 हितग्राहियों को 16 करोड़ 19 लाख रुपए का ऋण स्वीकृत

विदिशा (निप्र)। इण्डस्ट्री स्किल एण्ड एम्प्लॉयमेंट कॉनक्लेव आज शुक्रवार को सम्राट अशोक टेक्नोलॉजीकल इंस्टीट्यूट, कैलाश सत्यार्थी हॉल (एसएटीआई) विदिशा में किया गया। जिला स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में आयोजित रीजनल इंडस्ट्री स्किल एण्ड एम्प्लॉयमेंट कॉनक्लेव (आरआईएसई) का सीधा प्रसारण दिखाए जाने के प्रबंध सुनिश्चित किए गए थे एसएटीआई में आयोजित कार्यक्रम में 435 हितग्राहियों को 16 करोड़ 19 लाख का लाख का ऋण स्वीकृत एवं वितरण किए गए एवं 209 आवेदकों का चयन किया गया है। साथ ही मौके पर 15 आवेदकों को मंच से ही ऑफर लेटर प्रदाय किए हैं। जिला स्तर पर विदिशा विधायक श्री मुकेश टंडन के मुख्य आतिथ्य में आयोजित इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमति प्रीति राकेश शर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि गण श्री ब्रजेश लोधी के अलावा जिला पंचायत के अतिरिक्त सीईओ श्री पंकज जैन, आईएमसी अध्यक्ष, संरक्षक, लघु उद्योग भारती श्री प्रदीप मित्तल, अध्यक्ष, लघु उद्योग भारती श्री अश्विनी गुप्ता, सचिव लघु उद्योग भारती श्री हिमांशु कोठारी की उपस्थिति में सपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक श्री अशोक श्रीवास्तव, आईटीआई प्राचार्य श्री एपी श्रीवास्तव, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक, श्री भगवान सिंह बघेल, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र की सहायक प्रबंधक श्रीमती जंयती कुमारी, जिला रोजगार कार्यालय विदिशा से श्री नन्नूलाल साहू, श्री अनुरूप चतुर्वेदी तथा विभिन्न कॉलेजों के प्राचार्य, विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं से संबंधित अधिकारी एवं विभिन्न जिलों से आमंत्रित कंपनियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में अतिथियों द्वारा मंच से विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र, वितरण तथा विभिन्न कंपनियों द्वारा चयनित आवेदकों को ऑफर लेटर वितरित किये गये। इस कार्यक्रम का आयोजन संयुक्त रूप से जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, विदिशा एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं रोजगार विभाग द्वारा किया गया था।

- 209 आवेदकों का चयन, 15 को मंच से ही ऑफर लेटर प्रदाय किए -

इस कार्यक्रम में विभिन्न सेक्टर की कुल 14 कंपनियों तथा 03 टीपीए द्वारा पंजीकृत 504 आवेदकों में से 209 आवेदकों का चयन किया गया है एवं 15 ऑफर लेटर मंच से वितरित किये गए हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में आयोजित रीजनल इंडस्ट्री स्किल एण्ड एम्प्लॉयमेंट

सभी विभाग पदोन्नति कार्य को दें सर्वोच्च प्राथमिकता

सीहोर (निप्र)। मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन ने सभी विभाग प्रमुखों से कहा कि लोक सेवा पदोन्नति नियम-2025 के तहत पदोन्नति कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाये। यह प्रयास किया जाये कि 31 जुलाई 2025 तक अधिकारी-कर्मचारियों को पदोन्नत किया जा सके।

उन्होंने कहा कि राज्य शासन की मंशानुरूप कर्मचारी-कल्याण को प्रमुखता से लें। मुख्य सचिव श्री जैन ने गुरूवार को मंत्रालय में लोकसेवा पदोन्नति नियम-2025 के परिचर्चा के दौरान यह निर्देश विभाग प्रमुखों को दिये। मुख्य सचिव श्री जैन ने कहा कि 9 साल की बड़ी समस्या इस नियम के लागू होने से समाप्त हो सकेगी। नियमों को बनाने में वरिष्ठ सचिव समिति एवं सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने बहुत मेहनत एवं गहन चर्चा की। नियमों के लागू होने से प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी।

कर्मचारी कल्याण को दें प्राथमिकता : मुख्य सचिव श्री जैन ने अधिकारियों से कहा कि अपने विभाग में कर्मचारी-कल्याण को प्राथमिकता दी जाये। विभागीय परामर्शदात्री समिति की बैठकें आयोजित की जाये। कर्मचारियों के गोपनीय प्रतिवेदन, विभागीय जाँच एवं पेंशन प्रकरणों का निराकरण समय से करें।

नियमों की दी गयी विस्तृत जानकारी : परिचर्चा के दौरान अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन श्री संजय दुबे एवं उप सचिव श्री अजय कटेसरिया ने मध्यप्रदेश लोकसेवा पदोन्नति नियम-2025 की विस्तृत जानकारी दी। इसमें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के लिए आरक्षित पदों की गणना, विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक, अर्हकारी सेवा की गणना, वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन, पदोन्नति हेतु अनुपयुक्तता, पदोन्नति का प्रकार, पदोन्नति के फलस्वरूप वेतन का निर्धारण, सीलबंद लिफाफे की स्थिति में प्रक्रिया सहित प्रतीक्षा सूची से रिक्तियों को भरे जाने की विस्तृत जानकारी दी गयी।

प्रश्नों का समाधान : परिचर्चा में पुलिस, महिला एवं बाल विकास, नगरीय प्रशासन, अनुसूचित जाति विकास, परिवहन, वन सहित अन्य विभाग के अधिकारियों के प्रश्नों का समाधान मुख्य सचिव श्री जैन द्वारा किया गया।

अशासकीय स्कूलो में शैक्षणिक गतिविधियों का क्रियान्वयन तय नियमो के अनुसार क्रियान्वित हो: कलेक्टर

विदिशा (निप्र)। कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता ने आज विदिशा जिले में संचालित समस्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, हाई स्कूल, माध्यमिक, प्राथमिक विद्यालय (सीबीएसई), विद्यालय के संचालको की बैठक आयोजित कर उन्हें शासन के दिशा निर्देशानुसार शैक्षणिक संस्थानो में गतिविधियों का क्रियान्वयन कराने हेतु सचेत किया है। कलेक्टर श्री गुप्ता ने कहा कि अशासकीय विद्यालयो में अध्ययनरत बच्चो को शासन की जिन-जिन योजनाओं के हितलाभ हेतु पात्रता रखते है वे उससे वंचित ना रहे यह दायित्व संबंधित शैक्षणिक संस्था का भी होगा। उन्होंने कहा कि बच्चों के बस्तो का वजन कक्षावार तय किया गया है जिसका पालन सुनिश्चित हो। कोई भी शैक्षणिक संस्थान अनावश्यक रूप से अभिभावको को पुस्तके, ड्रेस खरीदने अथवा अन्य सामग्री खरीदने के लिए दबाव नहीं बनाएंगे।

जिन स्कूलो के लिए एनसीआरटी की किताबे बाध्य की गई है वे अन्य निजी प्रशासको की किताबे खरीदने के लिए किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बनाएंगे। उन्होंने कहा कि यह पहली बैठक है अतः सभी अशासकीय स्कूलो के संचालक व मौजूद प्रतिनिधि ऐसी कार्यप्रणाली अपनाएं कि शासकीय नियमो की अनदेखी ना हो और ना ही कहीं से शिकायते प्राप्त हो। कलेक्ट्रेट के बेतवा सभागार कक्ष में आयोजित इस बैठक में जिन एजेण्डा बिन्दुओं पर चर्चा कर क्रियान्वयन कराने हेतु निर्देशित किया गया उनमें सभी विद्यालयो के लिए शैक्षणिक सत्र 2025-26 में बढाई गई फीस के औचित्य एवं कारणो को स्कूलवार रेखांकित किया गया। विद्यालयों में खेल सुविधाएं, प्ले ग्राउण्ड तथा कितने बच्चों के द्वारा स्टेट एवं नेशनल स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लिया कि जानकारी तथा इस शैक्षणिक सत्र में ली जाने वाली फीस की विस्तृत जानकारी जैसे एडमिशन, क्रीड़ा, स्काउट, रेडक्रास, कैरियर काउंसलिग, शाला विकास, शिक्षण शुल्क, परिवहन शुल्क आदि की जानकारी, ईको क्लब पौधरोपण की जानकारी शामिल है। अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को स्कूल तक आने जाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले वाहन जैसे बस, आटो के संबंध में जिला परिवहन अधिकारी के द्वारा आवश्यक जानकारियां सांझा की गई और हरेक स्कूल में एक-एक वाहन प्रभारी नियुक्त करने के सुझाव पर सहमति व्यक्त की गई है वही आटो में निर्धारित संख्या में बच्चो को लाने ले जाने का कार्य किया जाए। बच्चे किन-किन आटो से आते है उन आटो के नम्बरो संबंधी जानकारी स्कूलो में संधारित की जाए।

दो किसानों के खेतों में रिचार्ज स्ट्रक्चर निर्माण कूप का कार्य पूर्ण

विदिशा (निप्र)। जल गंगा संवर्धन अभियान विदिशा जिले के लिए वरदान बन गया है जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने में सार्थक साबित हो रहा है। जल स्त्रोतों का जीर्णोद्धार और पुनर्जीवन में इस अभियान की भूमिका अहम बन गई है। इसी के तहत विदिशा जिले के विभिन्न ग्रामों में रिचार्ज स्ट्रक्चर निर्माण कूप बनाए गए है। विदिशा जिले के ग्राम काला देव के श्री रघुवीर पिता करोड़ी लाल के खेत में और ग्राम सरोज के किसान श्री भुजबल सिंह शाक्य के खेत में रिचार्ज स्ट्रक्चर निर्माण कूप का निर्माण पूर्ण कराया गया है। यह स्ट्रक्चर इन दोनों किसानों के खेतों में बनाए गए कुओं के समीप स्थापित किया गया है , ताकि बारिश का जल भूजल स्तर को बढ़ा सके और सूखे की स्थिति उत्पन्न ना हो।किसानों के खेतों में रिचार्ज स्ट्रक्चर निर्माण हो जाने से अब इन किसानों को सुखे की स्थिति से निपटना नहीं पड़ेगा। भूजल स्तर में सुधार होगा और सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध हो सकेगा। ये संरचनाएं वर्षा के जल को भूजल में रिसने देती हैं। जिससे पानी की कमी और सूखे की समस्या की संभावना बहुत कम हो जाती है। मुख्यमंत्री जी की पहल पर 30 जून तक जारी जल गंगा संवर्धन अभियान से विदिशा जिले में बड़ी संख्या में जल स्रोतों को संवारा गया है जो जल की कमी को पूरा करने में सार्थक साबित होगा। जिले के किसान श्री रघुवीर और भुजबल सिंह ने इस अभियान के माध्यम से रिचार्ज स्ट्रक्चर निर्माण कूप जैसी संरचनाएं स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री जी, जिला प्रशासन और जिला पंचायत के प्रति धन्यवाद व्यक्त किया है।

रीजनल इण्डस्ट्रीज स्किल एंड एम्प्लाईमेंट कॉन्क्लेव 2025 का जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित

बैतूल (निप्र)। प्रदेश में औद्योगिक कौशल विकास, स्वरोजगार एवं रोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के विशेष आतिथ्य में शुक्रवार को रतलाम जिले में आयोजित रीजनल इण्डस्ट्रीज स्किल एंड एम्प्लाईमेंट कॉन्क्लेव 2025 का जिला स्तरीय कार्यक्रम कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित किया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री हंसराज धुर्वे, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती पार्वती बाई बारस्कर उपस्थित थी।

सर्वप्रथम मुख्य अतिथियों ने मां सरस्वती के छायाचित्र समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान रतलाम जिले में आयोजित रीजनल इण्डस्ट्रीज स्किल एंड एम्प्लाईमेंट कॉन्क्लेव 2025 का लाइव प्रसारण देखा गया। कार्यक्रम में अतिथियों ने विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों को चेक प्रदान कर हितलाभ वितरण किया। कार्यक्रम के दौरान योजनाओं से लाभान्वित होने वाले हितग्राहियों ने अपने अनुभव साझा किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री धुर्वे ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा युवाओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। आजीविका मिशन से जुड़कर महिलाएं लखपति बन रही है।

कार्यक्रम के दौरान उन्होंने लाभान्वित हितग्राहियों को शासन से प्राप्त सहायता का सही उपयोग कर एक मिसाल कायम किए जाने के लिए प्रेरित किया। नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती बारस्कर ने कहा कि प्रदेश सरकार की योजनाओं से महिलाएं आर्थिक सशक्त बना रही है। उन्होंने सभी महिलाओं को शासन की योजनाओं का लाभ लेकर अन्य महिलाओं को भी प्रेरित किए जाने की बात कही। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री राजीव नंदन श्रीवास्तव, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सहायक संचालक श्री नरेन्द्र गौतम, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के अधिकारी कर्मचारी, उद्योगपति, स्व सहायता समूह की महिलाएं उपस्थित थीं।

जेएच कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस का आयोजन

बैतूल (निप्र)। सामाजिक न्याय विभाग के द्वारा शासकीय जेएच स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैतूल के सहयोग से गुरुवार को स्वामी विवेकानंद सभागृह में अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रधान न्यायाधीश श्री शिवबालक साहू उपस्थित थे। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि द्वारा मां सरस्वती के छायाचित्र समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस दौरान प्रधान न्यायाधीश द्वारा श्री साहू द्वारा नशे से दूर रहने की सलाह देते हुए डिजीटल नशे के विषय में विस्तृत रूप से उद्बोधन दिया। डॉ. सुखदेव के द्वारा युवा वर्ग को निरंतर नशा मुक्त अभियान चलाने की पहल की जाने की सलाह दी गई। प्राध्यापक श्री शंकर सातनकर के द्वारा भी नशे से दूर रहने व नशे के दुष्परिणाम की जानकारी से अवगत कराया गया।

नशा मुक्ति का लिया संकल्प

कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सभी अतिथियों व जनसमुदाय के द्वारा नशा मुक्त होने की शपथ ली गई। सामाजिक न्याय विभाग के कलाकार श्री नवल किशोर महोबे व उनके साथियों द्वारा गायन प्रस्तुत किया गया तथा स्वास्थ्य विभाग की एएनएम एवं जय गुरुदेव संस्था के द्वारा नुक्कड़ नाटक की मनमोहक प्रस्तुति दी गई। उल्लेखनीय है कि जिले में 01 जून से 26 जून तक सामाजिक न्याय विभाग एवं अन्य अशासकीय संस्थाओं के माध्यम से नशा मुक्ति अभियान चलाया गया।

इस कार्यक्रम में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया तथा विभिन्न प्रतियोगिता भी संचालित हुई। प्रतियोगिताओं में प्रस्तुत प्रतिभागियों को सामाजिक न्याय विभाग के सौजन्य से प्रमाण पत्र प्रदाय किए गए।

महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में प्राचार्य डॉ. मीनाक्षी चौबे के द्वारा दिये गये सहयोग से कार्यक्रम का आयोजन सफलता पूर्वक सम्पन्न हुआ एवं कार्यक्रम के अंत में उपसंचालक सामाजिक न्याय विभाग सुश्री रोशनी वर्मा के द्वारा समस्त महाविद्यालय, समस्त शासकीय विभाग, अशासकीय संस्थाओं, नेहरू युवा केन्द्र, जन अभियान परिषद व कार्यक्रम में उपस्थित जन समुदाय का आभार व्यक्त किया गया।

जल गंगा संवर्धन अभियान में माखन नगर तालाब को मिला पुनर्जीवन

तालाब में पानी हुआ लबालब अब सुनाई देता है पक्षियों का कलरव

नर्मदापुरम (निप्र)। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत जिले में प्राचीन बावड़ी, तालाब, खेत तालाब, कूप रिचार्ज आदि जल संरचनाओं का जीर्णोद्धार कर जल संरक्षण के कार्य किए जा रहे हैं। जल गंगा संवर्धन अभियान में लुप्त प्राय एवं समाप्त हो चुकी पुरातन एवं नवीन जल संरचनाओं को श्रमदान कर एवं शासन की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनको पुनर्जीवत कर उन जल संरचनाओं को उपयोगी बनाया जा रहा है। उन्हें पुनः नवीन कर जीवन प्रदान करने का कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में माख न नगर के नसीराबाद रोड पर स्थित प्राचीन माखन नगर तालाब के पुनर्जीवन का कार्य किया गया है। अमृत --2 योजना के तहत 43 लाख रुपए की राशि से निर्मित माखन नगर तालाब अब पानी से भरा रहता है यहां अब पक्षियों का शोर सुनाई देता है और तालाब के पुनर्जीवन से आसपास के क्षेत्र का जलस्तर भी बढ़ गया है। नगर पालिका अधिकारी माखन नगर ने बताया कि जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत माखन नगर तालाब में पिचिंग एवं पाथवे का निर्माण कार्य किया गया है। लाइटिंग भी लगाई गई है जिससे रात्रि में तालाब का अद्भुभुत दृश्य दिखाई पड़ता है। अब तालाब में लबालब पानी भरा हुआ है। इससे आसपास के पक्षी आकर कलरव भी कर रहे हैं। नगर पालिका अधिकारी ने बताया कि मुख्यतः वाटर लेवल बढ़ाने के लिए तालाब मैं व्याप्त गंदगी एवं कचरे को तथा जलकुंभी को निकाला गया और पुनर्जीवन का कार्य किया गया है और इसमें काफी सफलता मिली है। अब आसपास पानी का स्तर बहुत बढ़ गया है।

98 कर्मचारी सेवानिवृत्त होंगे तीन माह में

विदिशा (निप्र)। जिला पेंशन अधिकारी श्री रूपेन्द्र सिंह मरावी ने बताया कि विदिशा जिले में सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी, कर्मचारियों के सम्मान में प्रत्येक माह की दस तारीख को कलेक्ट्रेट के बेतवा सभागार कक्ष में कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। उन्होंने बताया कि जून, जुलाई, अगस्त में कुल 98 जिले में पदस्थ शासकीय सेवक सेवानिवृत्त होंगे जिसमें जून माह में 29, जुलाई में 42 और अगस्त माह में 27कर्मचारी सेवानिवृत्त होंगे। जिला पेंशन अधिकारी ने सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी, कर्मचारियों की तमाम दावो का भुगतान सेवानिवृत्त तिथि को प्रदाय किया जाए इसके लिए विभागीय अधिकारियों को पत्र प्रेषित कर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की छह माह पूर्व जानकारियां मांगी गई हैं ताकि दावो से संबंधित आपत्तियों का निराकरण सेवानिवृत्ति तिथि के पूर्व किया जा सके।

भोपाल, ग्वालियर समेत कई जिलों में बारिश

11 जिलों में हेवी रेन का अलर्ट

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम बना हुआ है। रविवार को भोपाल, नर्मदापुरम, रतलाम, धार और रायसेन, विदिशा और खंडवा में में सुबह से रुक-रुककर तेज और रिमझिम बारिश जारी थी।

मौसम विभाग ने ग्वालियर, चंबल, रीवा और शहडोल संभाग के 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। यहां अगले 24 घंटे के दौरान साढ़े 4 इंच तक पानी गिर सकता है। 1 जुलाई से स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनेगा। इससे प्रदेश के आधे से ज्यादा जिलों में अति भारी या भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार, रविवार को भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर समेत अन्य जिलों में बारिश का यलो अलर्ट है। वहीं गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, मंडला और बालाघाट में भारी बारिश होगी।

भोपाल में 90 डिग्री मोड़ वाले ब्रिज को लेकर एक्शन

सीएम ने 8 अफसरों को किया सस्पेंड, डिजाइन और निर्माण एजेंसी भी ब्लैकलिस्ट

भोपाल (नप्र)। भोपाल के 90 डिग्री एंगल वाले ऐशबाग आरओबी के निर्माण में हुई गंभीर लापरवाही पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 8 अफसरों को सस्पेंड करने के निर्देश दिए हैं।

शनिवार रात मुख्यमंत्री ने एक्स पर लिखा है कि मैंने संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए थे। जांच रिपोर्ट के आधार पर लोक निर्माण विभाग के 8 इंजीनियर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई है। दो सीई सहित सात इंजीनियर्स को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। एक सेवानिवृत एसई के खिलाफ विभागीय जांच की जाएगी।

इस प्रोजेक्ट में आरओबी का त्रुटिपूर्ण डिजाइन प्रस्तुत करने पर निर्माण एजेंसी एवं डिजाइन कंसल्टेंट, दोनों को ब्लैक लिस्ट किया है। आरओबी में आवश्यक सुधार के लिए कमेटी बनाई गई है। सुधार के बाद ही आरओबी का लोकार्पण किया जाएगा।

सस्पेंड अफसरों पर आज तय होंगे आरोप- अपर मुख्य सचिव लोक निर्माण विभाग नीरज मंडलोई ने बताया कि जिन अफसरों पर कार्रवाई हुई है। उनके खिलाफ कल आरोप तय किए जाएंगे।

समय-सीमा से एक साल प्रोजेक्ट लेट- ऐशबाग रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण 21 मई 2022 को शुरू था। समय-सीमा से प्रोजेक्ट एक साल देरी से चल रहा है। 17 करोड़ 37 लाख की लागत वाले ब्रिज का निर्माण अगस्त 2024 में पूरा होना था। लेकिन, जून 2025 में भी इसे बनाने की प्रक्रिया जारी है।

मंत्री राकेश सिंह ने कराई थी जांच- बता दें, पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) से जांच करवाई थी। एनएचएआई ने ब्रिज को लेकर अपनी रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें 35-40 किमी प्रति घंटा से अधिक गति से गाड़ी नहीं चलाने का सुझाव दिया गया है। इससे अधिक स्पीड में गाड़ी चली तो हादसा होने का खतरा है। ऐसे में इस ब्रिज को रिडिजाइन करने का फैसला लिया गया है। हालांकि इस मामले में अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं।

सोशल मीडिया पर मीम्स भी बने

भोपाल में बने इस रेलवे ओवरब्रिज को लेकर लोगों ने सोशल मीडिया पर मीम्स भी बनाए हैं। इस ब्रिज पर 90 डिग्री के एंगल से मोड़ दिया गया है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि यहां वाहन कैसे टर्न लेंगे। वाहनों के या तो ब्रिज की दीवारों से या फिर आपस में टकराने का खतरा बना रहेगा।

क्रॉसिंग बंद होने से ब्रिज की जरूरत

ब्रिज के निर्माण के समय रेलवे ने भी 90 डिग्री की इस टर्निंग पर आपत्ति की थी, लेकिन पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों ने यहां जगह कम होने का हवाला देते हुए कहा था कि और कोई विकल्प नहीं है। ऐशबाग रेलवे क्रॉसिंग बंद होने के बाद इस इलाके के लिए आरओबी एक बड़ी जरूरत है। इसलिए कम जगह में भी इसे बनाना होगा।

18 महीने में बनकर तैयार होना था

इस ब्रिज का निर्माण मई 2022 में शुरू हुआ था और इसे 18 महीने में पूरा करना था, लेकिन अब तक पूरी तरह से नहीं बन सका है। इसकी लागत 18 करोड़ रुपए है। 648 मीटर लंबे और 8 मीटर की चौड़ाई वाले ब्रिज का 70 मीटर हिस्सा रेलवे का है।

प्रदेश की औद्योगिक विकास दर को गति देने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध : मुख्यमंत्री

औद्योगिक समूहों से जुड़ाव, प्रदेश में निवेश को सुगम बनाने और रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए सूरत में हो रहा है इंटरएक्टिव सेशन

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश की कृषि विकास दर के समान औद्योगिक विकास दर को आगे बढ़ाने के लिए के लिए राज्य सरकार कृत संकल्पित है। इसी उद्देश्य से उद्योग व्यापार और निवेश गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश में क्षेत्रीय स्तर पर समिट आयोजित करने और देश-विदेश के प्रमुख औद्योगिक व्यापारिक केंद्रों से संपर्क का क्रम जारी है। राज्य सरकार की इस पहल का प्रदेश को लाभ भी मिल रहा है। इसी क्रम में आज सूरत में 'मध्य प्रदेश में निवेश के अवसरों पर इंटरएक्टिव सेशन' रखा गया है। यह आयोजन उद्योग एवं रोजगार वर्ष 2025 अभियान की श्रृंखला में बेंगलुरु के बाद दूसरा बड़ा संवाद है। क्षेत्रीय स्तर पर औद्योगिक समूह से जुड़ाव बढ़ाना और प्रदेश में रोजगार के अवसर सृजित करना तथा निवेश को सुगम बनाना इस अभियान का उद्देश्य है। सूरत देश का प्रमुख औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र है। वहां के उद्योग व्यापार जगत के सहयोग से प्रदेश में निवेश गतिविधियों को प्रोत्साहन मिले, इस उद्देश्य से वहां समिट आयोजित किया गया है। राज्य सरकार प्रदेश में औद्योगिक व्यापारिक गतिविधियों के विस्तार के लिए हर संभव सहयोग देने के लिए तत्पर है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सूरत प्रस्थान से पहले मीडिया के लिए जारी संदेश में यह विचार व्यक्त किऐ।

भोपाल में लगे ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के पोस्टर, बताया हीरो

डेरे के इमाम बोले- ये सेलिब्रेशन नहीं, एक वैचारिक प्रदर्शन है

भोपाल (नप्र)। भोपाल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-6 के पास स्थित ईरानी डेरा में इस बार मोहर्रम के मौके पर ईरान के नेताओं के पोस्टर लगाए गए हैं। कई जगहों पर शिया समुदाय के प्रभावशाली धार्मिक और सैन्य नेताओं आयतुल्ला अली खामेनेई, अली अल सिस्तानी, जनरल मोहम्मद बाघेरी, कासिम सुलेमानी और अयातुल्ला खोमैनी के बड़े-बड़े पोस्टर्स लगाए गए हैं। एक जगह आयतुल्ला अली खामेनेई का फोटो तिरंगे के नीचे लगा है।

फतेहपुर से भोपाल आए ईरानी डेरे के इमाम शाहकार हुसैन ने कहा कि हर साल पोस्टर्स लगाए जाते हैं, लेकिन इस बार संख्या ज्यादा है। इसकी वजह है 12 दिन की वह जंग, जिसे इजराइल ने बुजदिलाना अंदाज में शुरू किया और ईरान ने करारा जवाब दिया।

इजराइल-ईरान के बीच संघर्ष विराम को लेकर उन्होंने कहा कि सीजफायर की मांग खुद इजराइल-अमेरिका ने की। यह सिर्फ ईरान नहीं, इंसाफ पसंद तमाम लोगों की जीत है।

खामेनेई सिर्फ धर्मगुरु नहीं, अब आलमी लीडर बन चुके हैं- ईरानी डेरे के इमाम शाहकार हुसैन के मुताबिक, आयतुल्ला खामेनेई ने खुद कहा है कि यह जीत मोहर्रम की देन है। हमने इमाम हुसैन से सीखा है कि जुल्म के खिलाफ सिर नहीं झुकाते। मोहर्रम का यही

संदेश है और इस बार इसे दुनिया के सामने रखना जरूरी था कि हक की राह पर चलने वाले कभी हारते नहीं।

शाहकार हुसैन ने कहा- यहां जो बैनर लगे हैं, वे कोई सेलिब्रेशन नहीं, बल्कि एक वैचारिक प्रदर्शन हैं। यह दिखाने के लिए है कि अगर इमाम हुसैन की राह पर चला जाए तो बड़ी से बड़ी ताकत को झुकाया जा सकता है।

भारत के रुख की तारीफ, ईरानी कल्चरल हाउस ने भेजा शुक्रिया पत्र- शाहकार हुसैन ने कहा कि इसमें भारत का बैलेंस रवैया रहा है। ईरानी कल्चरल हाउस ने एक लेटर जारी किया है। भारत की अवाम का शुक्रिया अदा किया है कि वह साथ में खड़े रहे, भारत का रवैया बिल्कुल सही था, जंग में किसी का फायदा नहीं है, नुकसान ही है। उन्होंने जंग रुकवाने की कोशिश भी की, मगर यूरोपियन कंट्रीज का स्टैंड गलत था।

अहमदाबाद में खुलेगा मप्र औद्योगिक विकास निगम का ऑफिस : मुख्यमंत्री

सूरत में सीएम बोले- बिना गुजरात की भूमिका के भारत का पूर्ण उत्थान संभव नहीं

भोपाल (नप्र)। मप्र सरकार औद्योगिक और रोजगार के क्षेत्र में लगातार प्रयास कर रही है। सीएम डॉ मोहन यादव ने आज गुजरात के सूरज में उद्योगपतियों के साथ इंटरेक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट को संबोधित किया।

सीएम ने अपने संबोधन में कहा- मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम का कार्यालय अब अहमदाबाद में भी खोला जाएगा। इससे गुजरात के उद्यमियों को हमारे राज्य में निवेश करने में और अधिक सुविधा होगी।सीएम ने कहा- गुजरात और मध्यप्रदेश के बीच औद्योगिक विकास निगम का नया कार्यालय औद्योगिक सेतु केवल व्यापारिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक होगा।

मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने कहा- गुजरात की धरती पर आकर मैं आत्मविभोर हूं। यह केवल 300 वर्षों का इतिहास नहीं, बल्कि भगवान श्रीकृष्ण से जुड़ी हुई सनातन परंपरा और सांस्कृतिक धरोहर का गौरवशाली प्रतीक है। सीएम ने कहा- भगवान श्रीकृष्ण ने कंस का वध कर धर्म की स्थापना की और द्वारका बसाकर एक आदर्श राज्य का निर्माण किया। वास्तव में, बिना गुजरात की भूमिका के भारत का पूर्ण उत्थान संभव नहीं।

कठिन परिस्थितियों में भी गुजरात के लोग साधारण जीवन जीते हैं- सीएम ने कहा- गुजरात ने न केवल अध्यात्म का, बल्कि उद्योग, व्यापार और सादगीपूर्ण जीवनशैली का भी मार्ग प्रशस्त किया है। यहां के लोग कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी साधारण और ईमानदारी से जीवन जीते हैं। यही गुजरात की विशेषता है, जो हमारी सनातन संस्कृति की सच्ची पहचान है।

महात्मा गांधी हों या सरदार वल्लभभाई पटेल इन महान व्यक्तित्वों ने भारत को दिशा दी। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटकर भारत को स्वतंत्रता दिलाई, वहीं पटेल जी ने 600 से अधिक रियासतों को एकत्र कर भारत को अखंड राष्ट्र बनाया।

आज हम गर्व से कह सकते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में एक महाशक्ति के रूप में उभर रही है। साल 1947 में जहां हम 15वें स्थान पर थे, आज हम विश्व की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गए हैं।इसका श्रेय निश्चित ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता, पारदर्शिता और प्रतिबद्धता को जाता है।

गुजरात ने व्यापार के मामले में देश में उदाहरण पेश किया- सीएम ने कहा- गुजरात में व्यापार करने की सरलता, व्यवस्था की पारदर्शिता और नवाचार के प्रति जागरूकता ने पूरे देश के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। आज यदि कोई भारत के औद्योगिक विकास को देखना चाहता है, तो उसे गुजरात अवश्य आना चाहिए।

जबलपुर में पत्नी-बेटे के साथ जॉय स्कूल संचालक गिरफ्तार

सेना में अधिकारी रही बहू ने लगाया धर्मांतरण का आरोप, कहा- प्रताड़ित कर घर से निकाला

जबलपुर (नप्र)। जबलपुर के जॉय सीनियर सेकेंडरी स्कूल के संचालक अखिलेश मेबिन, उनकी पत्नी और बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। रविवार को तीनों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया है।

सेना में अधिकारी रह चुकी अखिलेश की 36 वर्षीय बहू आकांक्षा अरोरा ने 28 जून को महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें आरोप लगाया था कि उस जबरन धर्मांतरण का दबाव बनाया जा रहा है। मना करने पर ससुर, सास और पति ने उससे मारपीट की है। नर्मदा रोड आदर्श नगर निवासी अपनी शिकायत में आकांक्षा ने बताया कि पति तनय मेबिन स्कूल का डायरेक्टर है। 20 दिसंबर 2017 में उसका विवाह तनय से हुआ था। वह सेना में कैप्टन के पद रह चुकी है। शादी के कुछ माह तो सब कुछ ठीक रहा पर उसके बाद से ससुराल वालों का आचरण बदल गया। मारपीट करने के साथ-साथ अखिलेश मेबिन उनकी पत्नी और बेटा ईसाई बनने का कह रहे हैं।

इससे पहले भी छात्रों के परिजनों से करोड़ों रुपए की अधिक फीस वसूली और भगवान राम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में अखिलेश जेल जा चुके हैं।

रीवा में खड़े ट्रक से टकराई बाइक, तीन की मौत

मृतक किशोरी की पहचान नहीं हो सकी ; दूसरी 8 वर्षीय बच्ची की हालत गंभीर

रीवा (नप्र)। रीवा जिले के गढ़ थाना क्षेत्र में रविवार को सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 वर्षीय बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। बाइक खड़े ट्रक में पीछे से जा टकराई।

जानकारी के मुताबिक, कटरा से गढ़ की ओर जा रहे बाइक सवार सूरज गिरी (24) और रावेंद्र साकेत (46) की मौके पर ही मौत हो गई। इनके साथ बाइक पर सवार एक 8 वर्षीय बच्ची भी थी, जिसे गंभीर हालत में संजय गांधी अस्पताल के ICU में भर्ती कराया गया है।

अभी एक बच्ची की पहचान नहीं- थाना प्रभारी अवनीश पांडेय ने बताया कि हादसा कलवारी मोड़ से 100 मीटर दूर हुआ। मृतकों में एक बच्ची भी शामिल है, जिसकी पहचान की जा रही है। परिजनों को सूचना दे दी गई है।

पुलिस जांच में जुटी- स्थानीय लोगों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा और बाइक नंबर के आधार पर पहचान की कार्रवाई शुरू की। शवों का पोस्टमॉर्टम परिजनों की मौजूदगी में कराया जाएगा। पुलिस आगे की जांच कर रही है कि हादसा किन परिस्थितियों में हुआ और ट्रक किन नियमों के तहत सड़क किनारे खड़ा था।

कही-सुनी

रवि भोई

(लेखक पत्रिका समवेत सृजन के प्रबंध संपादक और स्वतंत्र पत्रकार हैं।)

कौन होगा छत्तीसगढ़ का अगला मुख्य सचिव

छत्तीसगढ़ के नए मुख्य सचिव सुब्रत साहू होंगे या अमित अग्रवाल, या फिर मनोज पिंगुआ के सिर सेहरा बंधेगा? यह सस्पेंस बना हुआ है। छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्य सचिव अमिताभ जैन 30 जून को रिटायर हो जाएंगे। श्री जैन की विदाई और नए मुख्य सचिव के परिचय /स्वागत के लिए 30 जून को पूर्वान्ह 11 बजे साय कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। इससे साफ़ हो गया कि राज्य को 30 जून को नया चीफ सेक्रेटरी मिल जाएगा। मध्यप्रदेश, राजस्थान और ओडिशा के अनुभव के आधार पर लग रहा है चीफ सेक्रेटरी के बारे में निर्णय दिल्ली से होगा। तीनों दावेदारों में सुब्रत साहू वरिष्ठ हैं। वे 1992 बैच के आईएएस हैं। सुब्रत साहू कांग्रेस राज में मुख्यमंत्री के एसीएस थे। कांग्रेस राज में मुख्यमंत्री सचिवालय में रहे कुछ के जेल जाने और कुछ के विवादों में रहने के बाद भी सुब्रत साहू पाक-साफ़ रहे। इस कारण वे मुख्य सचिव की दौड़ में हैं। 1993 बैच के अमित अग्रवाल दिल्ली में पदस्थ हैं। अब वे दिल्ली छोड़कर रायपुर आते हैं या नहीं, यह बड़ा सवाल है। मुख्य सचिव की रेस में 1994 बैच के आईएएस और एसीएस गृह मनोज पिंगुआ भी हैं। मनोज पिंगुआ को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पसंद बताया जा रहा है। कहा जा रहा कि इन तीन आईएएस में से कोई एक मुख्य सचिव बनेगा और फैसला 30 जून को कैबिनेट की बैठक के पहले होगा। नए मुख्य सचिव की नियुक्ति के बाद मंत्रालय स्तर पर कई उलटफेर भी होंगे।

कांग्रेस के युवा नेता को पायलट की फटकार

कहते हैं पिछले दिनों अपने छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट ने कांग्रेस के एक युवा नेता को जबर्दस्त फटकार लगाई। ये युवा नेता कांग्रेस के एक संगठन के इंचार्ज बताए जाते हैं। इनके रिश्तेदार कांग्रेस के राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं। चर्चा है कि युवा नेता के बारे में सचिन पायलट को कई तरह की शिकायतें मिली थीं। उन शिकायतों को लेकर सचिन ने युवा नेता की क्लास ले ली और जमीन में रहने की हिदायत भी दी। बताते हैं युवा नेता के पिछले एक साल में काफी पंख लग गए थे। वे कई वरिष्ठ लोगों को मात देकर तेजी से आगे बढ़ गए। तेज चाल के चलते उनके कदम फिसलने भी लगे थे, तो मौका लगते ही सचिन पायलट ने युवा नेता को धो दिया। कांग्रेस के अंदरूनी हलकों में युवा नेता को सचिन पायलट की फटकार चर्चा का विषय है।

संतुलन साधने नीलू शर्मा को पर्यटन

कहते हैं संगठन में संतुलन साधने के मकसद से भाजपा हाईकमान ने राजनांदगांव के नेता नीलू शर्मा को पर्यटन मंडल के अध्यक्ष की कुर्सी दे दी। कहा जाता है कि राजनांदगांव में राजनीति की धुरी पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह के आगे-पीछे ही घूमती है। बताते हैं नीलू शर्मा राजनांदगांव से महापौर का चुनाव लड़ना चाहते थे। राजनांदगांव महापौर का पद सामान्य वर्ग के लिए था, लेकिन डॉ रमन सिंह की पसंद पर भाजपा ने मधुसूदन यादव को उम्मीदवार बना दिया। वे चुनाव जीत गए। मधुसूदन यादव ओबीसी हैं। सामान्य सीट पर ओबीसी को उम्मीदवार की भरपाई कहीं न कहीं करनी थी, सो नीलू शर्मा को पर्यटन मंडल के अध्यक्ष की कुर्सी देकर कर दी गई। वैसे भाजपा की राजनीति में नीलू शर्मा को डॉ रमन सिंह की धारा का नहीं माना जाता है। नीलू शर्मा के पिता अशोक शर्मा का सुर डॉ रमन सिंह से नहीं मिलता था, पर मुख्यमंत्री रहते डॉ रमन सिंह ने संतुलन के लिए अशोक शर्मा को पाठ्य पुस्तक निगम का अध्यक्ष बनाया था।

भतपहरी के पीछे लगे ठेकेदार

कहते हैं लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता विजय कुमार भतपहरी के पीछे कुछ ठेकेदार लग गए हैं और उन्हें खो करने के चक्कर में हैं। विजय कुमार भतपहरी दोबारा ईएनसी बनकर आए हैं। वे पिछली कांग्रेस सरकार में भी ईएनसी थे और काफी साल चले भी। लेकिन बाद में सरकार उनसे नाराज हो गई और हटा दिया, उनकी जगह के के पीपरी को ईएनसी बना दिया। पीपरी के रिटायरमेंट के बाद भतपहरी को फिर मौका मिल गया। एक तो विभाग में भतपहरी के अलावा कोई सीनियर नहीं थे, विजय भतपहरी ने गणित फिट करने के अलावा केमेस्ट्री भी अपने अनुकूल कर लिया। चर्चा है कि लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ईएनसी के पद पर किसी और को बैठना चाहते थे, विजय भतपहरी ने ऊपर से पव्वा लगा लिया। अब देखते हैं ठेकेदारों की लॉबी विजय भतपहरी को हिला पाती है या नहीं।

प्रदेश भाजपा की नई कार्यकारिणी जल्द

कहते हैं जल्द ही प्रदेश भाजपा की नई कार्यकारिणी बनने वाली हैं। नई कार्यकारिणी के लिए प्रदेश इकाई केंद्रीय संगठन को सूची भेजेगी। केंद्रीय संगठन ही प्रदेश कार्यकारिणी पर अंतिम मुहर लगाएगा। उम्मीद की जा रही है कि नई प्रदेश कार्यकारिणी पांच-सात दिन में घोषित कर दी जाएगी। पार्टी संगठन ने नई कार्यकारिणी में जगह देने के लिए कुछ नेताओं से बायोडाटा भी मांगा है। बताते हैं पार्टी संगठन ने ऐसे लोगों से भी बायोडाटा की मांग की है, जो दशकों से भाजपा की राजनीति कर रहे हैं और पहले भी संगठन और सत्ता में रह चुके हैं। बायोडाटा के लिए संगठन के एक पदाधिकारी के कार्यालय से नेताओं के पास संदेश गया है। चर्चा है कि बायोडाटा के संदेश से पार्टी के कुछ कद्दावर नेता भड़क गए हैं। वे कह रहे हैं पार्टी के लिए जीवन खपाने के बाद भी उन्हें अब पद के लिए बायोडाटा देना होगा।

कौन होगा जल संसाधन का ईएनसी

जल संसाधन विभाग के ईएनसी इंद्रजीत उइके 30 जून को रिटायर होने वाले हैं। उइके की जगह जल संसाधन विभाग का अगला ईएनसी कौन होगा, इस पर गुणा-भाग शुरू हो गया है। कहते हैं जल संसाधन विभाग के ईएनसी पद के लिए बिलासपुर के चीफ इंजीनियर जे आर भगत और चीफ इंजीनियर बांगो दीपक बुमेरकर दावेदार हैं। इनमें भगत की सर्विस आठ माह और बुमेरकर की चार माह बची है। वरिष्ठता में दोनों बराबर माने जा रहे हैं, ऐसे में सरकार लंबे पीरियड वाले को प्राथमिकता देती है तो भगत का चांस ज्यादा लग रहा है। जल संसाधन विभाग के अफसरों को सरकार के फैसले का इंतजार है।

संघ की बैठक में साय सरकार के काम की समीक्षा होगी

खबर है कि आरएसएस के दिल्ली स्थित झंडेवालान दफ्तर में आगामी चार से छह जुलाई तक देशभर के प्रांत प्रचारकों की बैठक होने वाली है। इसमें छत्तीसगढ़ के प्रांत प्रचारक अभयराम भी शामिल होंगे। वैसे तो यह बैठक मूलतः संघ के शताब्दी वर्ष कार्यक्रम के लिए हो रही है, पर बैठक में भाजपा शासित राज्यों के कामकाज पर चर्चा होने की उम्मीद की जा रही है। बैठक में छत्तीसगढ़ की साय सरकार के कामकाज पर विश्लेषण हो सकता है। बताया जा रहा है कि आरएसएस ने छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार के कामकाज के आब्जर्वेशन के लिए तीन-चार पर्यवेक्षक नियुक्त किए थे। पर्यवेक्षकों ने प्रांत प्रचारक को रिपोर्ट दे दी है। माना जा रहा है कि प्रांत प्रचारकों की बैठक में पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट पेश की जा सकती है और उस पर चर्चा भी हो सकती है।

दुश्मनों पर भारी पड़े मंत्री जी

कहते हैं राज्य के एक मंत्री को निपटाने में कुछ लोग लगे थे, उनके खिलाफ फर्जी तरीके से प्रधानमंत्री कार्यालय को भ्रष्टाचार की शिकायत भेजी गई। मंत्री जी के दुश्मनों ने तो बड़े शातिर तरीके का खेल खेला था। शिकायत के एक बड़े नाम और बड़ी संस्था को हथियार बनाया था। जाँच पड़ताल में पता चला कि शिकायतकर्ता ने तो मंत्री जी के बारे कोई शिकायत ही नहीं की थी। नाम और संस्था के उपयोग को लेकर मामला पुलिस तक पहुंच गया और दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। चर्चा है कि मंत्री जी की शिकायत के पीछे कुछ प्रशासनिक अधिकारियों का हाथ हो सकता है। जाँच में सब कुछ खुलासा होगा, पर अभी तो मंत्री जी ने दुश्मनों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और वार का प्रतिवार कर दिया है।

चपेटे में भूपेश बघेल के साथी

विजय भाटिया के बाद के के श्रीवास्तव को भी जाँच एजेंसियों ने दबोच लिया। दोनों को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का करीबी माना जाता रहा है। भूपेश बघेल सत्ता में थे तब दोनों उनके काफी नजदीकी माने जाते थे। खबर है कि भूपेश बघेल कई बार के के श्रीवास्तव के बिलासपुर आवास गए भी। चर्चा है कि जाँच एजेंसियों ने विजय भाटिया और के के श्रीवास्तव को ऐसा उलझा दिया कि भूपेश बघेल चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस राज में सत्ता की चौकड़ी में शामिल कई लोगों की गिरफ्तारी के बाद विजय भाटिया और के के श्रीवास्तव की गिरफ्तारी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं।